LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, July 25, 2024 / Sravana 3, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, July 25, 2024 / Sravana 3, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

…	1 – 2
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 41 – 46)	3 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 47 – 60)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 461 – 690)	51 – 280

Uncorrected – Not for Publication LSS-D-II

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, July 25, 2024 / Sravana 3, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, July 25, 2024 / Sravana 3, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 83
MOTION RE: 1ST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	284
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 342ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID	284
Shri Ajay Tamta	
ELECTION TO COMMITTEE	284
Rajghat Samadhi Committee	
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	285 - 304
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	305 - 17
Shri Arun Kumar Sagar	305
Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	305
Shri Kali Charan Singh	306
Shri Pradeep Purohit	306
Shri Raju Bista	307
Dr. Nishikant Dubey	308

Shri Ganesh Singh	**309**
Shri P.P. Chaudhary	**309**
Shri Khagen Murmu	**310**
Shri Janardan Singh Sigriwal	**310**
Shri Dilip Saikia	**311**
Shri Praveen Patel	**311**
Shri Benny Behanan	**311**
Shri Hibi Eden	**312**
Sushri S. Jothimani	**312**
Shri Ummeda Ram Beniwal	**313**
Shri B. Manickam Tagore	**313**
Shri Jitendra Kumar Dohare	**314**
Shri Zia Ur Rehman	**314**
Shrimati June Mallah	**314**
Shrimati Pratima Mondal	**315**
Shri K.E. Prakash	**315**
Shri Kaushalendra Kumar	**316**
Shri Navaskani K.	**316**
Shri Balashowry Vallabhaneni	**317**

GENERAL BUDGET - GENERAL DISCUSSION	**318 - 418**
AND	
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET - GENERAL DISCUSSION	
AND	
UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR - DEMANDS FOR GRANTS	
(Contd. - Inconclusive)	
Shri Charanjit Singh Channi	**318 - 24 & 327 - 30**
…	**325 - 26**
@ Shri Sunil Dattatrey Tatkare	**331 – 32 & 335**
…	**333 - 34**
Prof. Sougata Ray	**336 - 42**
Shri Baijayant Panda	**343 - 50**
# Dr. T. Sumathy *Alias* Thamizhachi Thangapandian	**351**
& Shri Bastipati Nagaraju	**352**
Dr. Alok Kumar Suman	**353 - 55**
Shri Hibi Eden	**356 - 59**
Shri C.M. Ramesh	**360 - 64**
Shri Rajeev Rai	**365 - 67**

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Sunil Dattarey Tatkare In Marathi, please see the Supplement (PP 332A to 332B & PP 335A to 335C)

 # For English translation of the speech made by the hon. Member, Dr. T. Sumathy *Alias* Thamizhachi Thangapandian in Tamil , please see the Supplement (PP 351A to 351D).

& For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Bastipati Nagaraju in Telugu, please see the Supplement (PP 352A to 352D).

Shri Arvind Ganpat Sawant	368 - 72
Shri Arun Bharti	373 - 78
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	379 - 81
Shri Rahul Kaswan	382 - 84
Shri Vivek Thakur	385 - 89
Shri Sudhakar Singh	390 - 92
@ Shri Malvinder Singh Kang	393
Shri Mian Altaf Ahmad	394 - 96
Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	397 - 99
Shri Raj Kumar Chahar	400 - 04
Shri Anand Bhadauria	405 - 06
Shri Raja Ram Singh	407 - 08
Shri Chandan Chauhan	409 - 11
# Shri C.N. Annadurai	412
Shri Sasikanth Senthil	413 - 15
Shri M. Mallesh Babu	416 - 18

xxxxxx

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Malvinder Singh Kang in Punjabi, please see the Supplement (PP 393A to 393B).

For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri C.N. Annadurai in Tamil, please see the Supplement (PP 412A to 412B).

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, July 25, 2014 / Sravana 3, 1946 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS PAGES

XXX	XXX	XXX	XXX
Xxx	xxx	xxx	xxx
Xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx

GENERAL BUDGET - GENERAL DISCUSSION
AND
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET - GENERAL DISCUSSION
AND
UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR - DEMANDS FOR GRANTS — 332A - 32B & 335A - 35C & 351A - 52D & 393A - 93B & 412A - 12B

xxx xxx xxx xxx

Shri Sunil Dattatrey Tatkare — 332A - 32B & 335A - 35C

xxx xxx xxx xxx

Dr. T. Sumathy *Alias* Thamizhachi Thangapandian — 351A - 51D

Shri Bastipati Nagaraju — 352A - 52D

xxx xxx xxx xxx

Shri Malvinder Singh Kang — 393A - 93B

xxx xxx xxx xxx

Shri C.N. Annadurai — 412A - 12B

xxx xxx xxx xxx

(1100/KN/SM)
1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे रूलिंग मांगते हैं। … (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 41.

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : पिछले दिन जो हुआ, भाजपा के एक सांसद द्वारा जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया… (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिये।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : हम आपसे रूलिंग मांगते हैं। … (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ बता रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : एक मंत्री ने कुछ नहीं बोला। … (व्यवधान) उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, कुछ नहीं बोला। … (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिये।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग इस महान सदन के सदस्य हैं और आप इसको प्रिसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य यदि ऐसी टिप्पणी करता है, जिससे सदन की गरिमा को चोट पहुंचती है, तो यह सब के लिए अत्यंत दु:खद घटना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चाहे सत्ता पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का सदस्य हो, कोई भी सदस्य हो, इस तरह की टिप्पणी या भाषा का इस्तेमाल करता है, जो संसदीय परम्परा में परमिसिबल नहीं है और सदन की गरिमा को चोट पहुंचती है तो आप समय-समय पर कार्रवाई करते ही हैं। उसको सदन की कार्यवाही से बाहर निकालने के साथ-साथ आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य यदि इस तरह का व्यवहार करेगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी अधिकार माननीय अध्यक्ष जी के पास है। मैं सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं, मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं, मैं कल यहां सदन में नहीं था, मैं राज्य सभा में गया हुआ था। जब मैं आया तो यह घटना हुई। … (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप उनको पूरी बात बोलने दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : जो कार्रवाई करनी थी, वह आप नहीं कर पाए। … (व्यवधान)
श्री किरेन रिजिजू : मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हमारे किस मैम्बर ने प्रोवोक किया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है, तो उचित कार्रवाई करने का अधिकार माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर साहब जरूर करें। … (व्यवधान)
श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : इन्होंने जनरल बोल दिया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये।

प्रश्न संख्या 41 – डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही जी।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This kind of a person was the Judge of a High Court! It is a very unfortunate thing … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी रूलिंग सुनिये। मैं रूलिंग दे रहा हूं। आप बैठिये।

… (व्यवधान)

डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही (बरहामपुर) : सर, क्वेश्चन नंबर 41.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप कार्रवाई करेंगे? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपरा रही है, परिपाटी रही है। हम सब का सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोक सभा के अंदर हूं और जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हों, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें। कोई ऐसी टिप्पणी न करें, जो सदन की मर्यादाओ के अनुकूल न हो और संसदीय परंपराओं के अनुकूल न हो। हम और कोशिश करें कि इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, परिपाटी बने। लोग चर्चा करें कि 18वीं लोक सभा के अंदर चुने हुए माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसकी मर्यादा, प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र की जिस तरह की प्रतिष्ठा है, वैसी परम्परा बनी है।

(1105/VB/RP)

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि ऐसे शब्दों को हम एक्सपंज तो कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द या कोई भी बात न तो बैठे-बैठे टिप्पणी करें, न ही अपने भाषण के अन्दर टिप्पणी करें।

मैं आपसे एक और आग्रह करूँगा कि कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी न करें। आपसे पुन: आग्रह करता हूँ कि हम आसन और सदन की जितनी गरिमा रखेंगे, उतनी ही प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने-अपने क्षेत्रों में बढ़ेगी। इस संसद के अन्दर बोलने वाले…

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कह दिया है और भविष्य के लिए चेतावनी दे दी है।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **(**जोरहाट**) :** खेद प्रकट करने के लिए नहीं कहा।… (व्यवधान) मंत्री जी ने खेद प्रकट किया।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पूरे सदन से कह दिया है। फिर ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया।

… (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप थोड़ा उनको इंटिमेट कीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

क्वेश्चन नम्बर 41, डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 41)

DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY (BERHAMPUR): Hon. Speaker, Sir, through you, I want the Minister to illustrate before the House the measures taken by the Government to ensure transparency, accountability, and equity in the carbon trading schemes, particularly, in the verification process of carbon credit while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing. How can the blockchain technology be leveraged to enhance tracking and verification by fostering participation across all sectors aligning with India's broader environmental goal?

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, जहाँ तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी ने एक बहुत ही डिटेल्ड प्रॉसीज़र पब्लिश कर रखा है, जिसमें उसके वैलिडेशन का विषय हो, प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन का विषय हो, ये विषय वास्तव में गंभीर हैं और इससे पूरी दुनिया चिंतित हैं। इंटरनैशनल मार्केट के भी बहुत-से पैरामीटर्स हैं, सभी कंट्रीज इस पर बैठकर विचार करते हैं। सबसे पहले वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में इस विषय की शुरुआत की गई थी। भारत में वर्ष 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। वर्ष 2005 में, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक मेथड बनाया गया था और उसके बाद हम लगातार 'द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म' के अंतर्गत अपनी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इसके आगे हमारे अचीवमेंट्स लगातार बढ़ते गये हैं। हमारे कुछ कमिटमेंट्स भी, टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, बनी हैं और उसी के अंतर्गत आज का यह विषय है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट को भारत वर्ष में एस्टैब्लिश किया जाए। इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं।

DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY (BERHAMPUR): Sir, I would like to know whether the Government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues.

SHRI MANOHAR LAL: Under the Registry of the Grid Controller of India, the Carbon Credit Certificates are being issued.

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. With your permission, I want to ask a broader policy question. Going back to the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, there was a consensus which emerged in the global community that global warming must be limited to 1.5 degree centigrade or 2.7 degree fahrenheit of the pre-industrial temperature which prevailed during the 1500s, before the First Industrial Revolution took place.

(1110/PC/NKL)

Now, from 1992 till 2024, this figure has been the trigger for a number of regimes like the Common But Differentiated Responsibilities and the Nationally Determined Contributions.

In the current Economic Survey – I do not know whether the hon. Minister has had the chance to read the current Economic Survey – there are two chapters which pertain to energy transition. Those are Chapter 6 and Chapter 13. Interestingly, in this Economic Survey, the sacrosanctity of 1.5 degree centigrade, that is, the global temperature should not rise beyond 1.5 degree centigrade, has been questioned in both the chapters. This is extremely significant.

So, my question to the hon. Minister is whether the Government agrees with the assertion which has been made in the Economic Survey.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): If the Government agrees with the assertion which has been made in the Economic Survey, it disrupts a large number of global consensuses which have held the field and triggered the CBDRs and the National Voluntary Contributions.

श्री मनोहर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री होने के नाते मेरा अध्ययन, जैसा कि आपने बताया, I have completed just one month's tenure in this House. कुल मिलाकर यह विषय बहुत बड़ा है। यह इंटरनैशनल कन्सर्न का विषय है। वर्ष 1992 या 1997 से कन्सर्न बढ़ता चला आ रहा है। हमने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं। उन कमिटमेंट्स में हमने एमिशन के कमिटमेंट्स किए हैं। वर्ष 2005 का जो कमिटमेंट था, यानी कार्बन एमिशन का जो कमिटमेंट था, यह था कि we will reduce it up to 33 to 35 per cent. यह हमारा कमिटमेंट था, लेकिन बाद में इसको हमने अचीव कर लिया। हमें इसे वर्ष 2030 तक अचीव करना था, लेकिन हमने इसको अचीव कर लिया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लक्ष्य उसके पहले ही पूरा कर लिया।

… (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : जी हां, हमने लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है। … (व्यवधान) अत: हमने अपना महत्वाकांक्षी टार्गेट अपने आप तय करके बताया था कि हम वर्ष 2030 तक 45 परसेंट तक ले जाएंगे। जब हम कार्बन एमिशन कम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ग्लोबल वॉर्मिंग को कम करने का जो लक्ष्य है, उसको भी हम प्राप्त करेंगे। फिर भी, इतने बड़े विषय को लेकर, टैक्निकल इश्यू होने के नाते, निश्चित रूप से हम बैठकर चाय पिएंगे और सारी बातें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप लोग बैठिए, मैं बता रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कभी भी प्रश्न काल में यह मत कहिए कि चाय पीते हुए जवाब देंगे। जो जवाब आपने दे दिया, वह ठीक है। चाय पीकर जवाब नहीं देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने इस बारे में बोल दिया है।

… (व्यवधान)

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): Sir, the organisations that issue carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy.

We have companies which, to offset their carbon emissions, invest in projects that reduce greenhouse gas emissions.

So, my question to the hon. Minister would be this. Is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think, it also connects to the question that has already been raised earlier. Thank you.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के लिए कुछ टार्गेट्स तय किए जाते हैं। हर इंडस्ट्री के हर सैक्टर को कुछ टार्गेट्स दिए जाते हैं। उन्हीं में से उनका एक कॉम्पिटीशन खड़ा होता है कि कौन अपने कार्बन एमिशन के टार्गेट्स को पूरा करता है, कौन उन टार्गेट्स से बैटर अचीव करता है। जो बैटर अचीव करता है, उसी को कार्बन सर्टिफिकेट्स इश्यू होते हैं, तभी वह फ्री मार्केट में उसे बेच सकता है।

बेचने और खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो निश्चित रूप से उसकी मेज़रमेंट अपने आप होगी, क्योंकि our Indian carbon market is yet on the way. वर्ष 2026 तक इंडियन कार्बन मार्केट जब सामने आएगी, तो उसी में से एक मूल्यांकन होगा कि किस इंडस्ट्री के सैक्टर ने अपना टार्गेट पूरा किया है, किसने पूरा नहीं किया है?

(1115/CS/VR)

जो भी टारगेट पूरा करेंगे और जो टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। जो टारगेट पूरा कर पाएंगे, बल्कि बेहतर कर पाएंगे, they have to sell their certificates. उसमें से ही चीजें अपने आप तय होंगी।

माननीय अध्यक्ष : यह भी बताइए कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है, जो उसके लक्ष्यों को समय पर पूरा करेगा और साथ में हमारी जो लायबिलिटीज थी, उससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हमने कम किया है। यह दुनिया में संसद की तरफ से मैसेज जाना चाहिए।

(इति)

… (व्यवधान)

(प्रश्न 42)

श्री अमरा राम (सीकर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि खाड़ी देशों में हमारे लाखों भारतवासी रोजगार और व्यापार के लिए जाते हैं। घरेलू क्षेत्रों में तो पॉइंट 2 परसेंट उड़ानें पिछले 3 महीने में रद्द हुई हैं। खाड़ी देशों के लिए 2 परसेंट उड़ानें पिछले 3 महीनों में रद्द हुई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने समय पहले एयरलाइन्स ने इस संबंध में यात्रियों को सूचित किया है। कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और कितनों को इस कारण से नुकसान हुआ है? मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। जब एक इंडियन एयरलाइन्स की यह हालत है तो जितनी एयरलाइन्स हैं, उनकी कितनी उड़ानें रद्द हुई हैं और कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सर, यह प्रश्न वैसे एयर इंडिया के हिसाब से पूछा गया था तो उससे संबंधित सूचना हमने दी थी। वैसे जो कैन्सिलेशन और डिले की बात आती है तो इस वर्ष अप्रैल और जून के बीच में ओवरऑल, चूँकि यह विषय केरल से संबंधित था तो उसी की सूचना अभी रखी है, बाकी आपका प्रश्न पूरे देश से संबंधित हो तो हम उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, बाद में उसका भी सर्कुलर लेंगे। इसके हिसाब से अप्रैल कैन्सिलेशंस कुल मिलाकर 14 हुए हैं, मई में 132 हुए हैं और जून में 18 हुए हैं। पूरे मिलाकर तीनों महीनों में 164 कैन्सिलेशंस हुए हैं।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you very much, Sir. Nowadays, the delay of flights especially of Air India and other flights has become the order of the day. Being a Member of Parliament from Kerala, I want to say that a huge number of people from Kerala are living in Middle East countries. They are badly suffering due to these delays in flights. Sometimes the flights are cancelled without any information, and no refund is done to the customers. Once it is cancelled, the amount is gone.

Sir, I want to know whether the Government has taken note of these things, and whether they are going to set up a system to monitor these cancellations. What action is the Government going to take in this regard?

There is one more thing, Sir. The fares are very high. The Government of Kerala itself has written to the Centre and many hon. Members have also submitted in writing with regard to the exorbitant hike in fares of the Gulf sector. The fare is very exorbitantly high. There is no justification. *....(Interruptions)* All over India, same pattern is there –

exorbitant fares. I want to know whether the Government of India has developed any mechanism to tackle this issue.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, the hon. Member, the senior Member has raised his concern regarding the cancellation of flights. We acknowledge the fact that there has been one issue with the Air India Express, not Air India, especially in the month of June. On May 7th this year – there were a lot of the crew with Air India Express – because it was merging with Air Asia, there were some internal issues that had cropped up, and there was a mass strike that happened. It was because of that strike, a lot of cancellations happened. We have seen this in the month of May. In fact, in the earlier answer, I have given the reason with regard to the number of cancellations. There was a huge spike in May because of this issue. When this issue started, it was the Ministry which got the DGCA involved, facilitated a lot of discussions between the airlines, the crew members and everything. So, it was sorted.

(1120/SAN/IND)

But because of the gap which was there for three days when the crew was not functioning and there were cancellations, there was another software glitch also which happened. Because of this software glitch, the crew member data which was supposed to be with the airlines, there was some problem with that and then, they were trying to enter it manually. So, for everything to get back to normalcy, there was some time. Right now, we are ensuring that there are no cancellations or no delays happening in the flight system.

Sir, like you have mentioned, there are civil aviation requirements also. There are already regulations and guidelines which are in place, which will ensure that whenever there is a delay or a cancellation happening, and if the airline is not following the regulations that are being set up by the Ministry, then the Ministry gets involved. It is ensuring that they get the refund, re-accommodation or readjustment done in other flights.

I would also like to take an example. Recently, when we investigated and observed that Air India was not following certain guidelines, we have penalised them for Rs. 10 lakh.

Then, the strike incident of Air India Express also happened. The DGCA is going into its depth and investigating the issue. If there seems to be any non-compliance by the airlines, then we are definitely going to penalise them and ensure that the passenger is the top priority.

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रयाग राज एयरपोर्ट के संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछली बार कुंभ में करीब 22 करोड़ लोग आए थे और इनमें से बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट के माध्यम से आए थे।

महोदय, चूंकि आगामी कुंभ होने वाला है और इस बार लगभग प्रस्तावित 40 करोड़ लोग आने की संभावना है, इसलिए एयरपोर्ट पर काफी दबाव रहेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी? कुंभ के दौरान क्या इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा दी जा सकती है?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Hon. Speaker, Sir, the question is not directly related to the Question that is on the list today. So, I will give the Member relevant information afterwards.

माननीय अध्यक्ष : आप नए-नए मंत्री बने हैं। आप तीन महीने में सारे एयरपोर्ट्स का अध्ययन कर लें। अगली बार पूरा जवाब परफेक्टली होना चाहिए।

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : महोदय, क्वैश्चन लिस्ट में एक एयरपोर्ट के बारे पूछा जाता है और कुल 157 एयरपोर्ट्स हैं। देश में पहले 74 एयरपोर्ट्स थे लेकिन पिछले दस साल में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 157 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। अब हम 157 एयरपोर्ट्स की जानकारी की तैयारी कर रहे हैं।

(इति)

(Q.43)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, first I congratulate Shri Rammohan Naidu *garu* for becoming the Civil Aviation Minister. He is the youngest Minister in the Cabinet and I wish him all success.

Sir, Vijayawada Airport comes under my parliamentary constituency. As the Chairman of Airport Advisory Committee, I have visited and reviewed the ongoing development works at the airport on many occasions. These works were started in 2019 and they were supposed to be completed by 2022, but till today, there is no major visible progress. What is the reason behind the delay?

Since the hon. Minister is from my State, he understands the importance of this airport. It is the airport of our capital city, that is, Amravati, which is the new capital of Andhra Pradesh. Therefore, this airport is important for us.

What is the new deadline for completion of this project? How does the Minister make sure that this time, all the proposed works will be completed before the said deadline?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Hon. Speaker, Sir, I totally agree with what the hon. Member of Parliament has raised here that this is a work which was started in June 2020. The overall estimated cost of the project was Rs. 611 crore. There has been subsequent delay, which was observed, because of COVID-19 that has happened. Like the Member has mentioned, I also come from the same State.

(1125/SNT/RV)

It is the capital airport that we have but for the last few years there have been other external factors also in the State which has hampered the progress, especially due to the non-availability of sand and other materials in the State. Right now, we are ensuring that it is going to be completed on time. I have taken it up as a top priority and the new deadline that we have fixed for this project is June, 2025.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, at the outset, let me also thank the hon. Minister because as soon as he took the charge, he introduced two flights from Vijayawada to Mumbai. Earlier, there was no flight to Mumbai. This was a long pending demand. We are requesting flights from Vijayawada to Kolkata, Vijayawada to Varanasi, and additional flight from Delhi

to Vishakhapatnam and Tirupati also. There is a demand for the flights to Sri Lanka, Thailand, and Singapore also.

I would like to know from the Minister whether these sectors are also in the consideration at the Ministry level.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह इस देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि माननीय सदस्यों के माध्यम से देश की जनता की आकांक्षा जगने लगी है कि मेरे यहां भी एयरपोर्ट बन जाएगा। यह देश के लिए अच्छा संकेत है।

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: As I have just mentioned, the infrastructure around airports has increased so much in the last 10 years. A huge push has been given for Civil Aviation Ministry. Right now, the way Members are raising their demands and asking for new airports or connectivity, if you go 10 years or 20 years back, it used to be the demand with railways. पहले रेलवे से कहा जाता था कि यहां ट्रेन चाहिए, यहां स्टॉपेज चाहिए। अब वह हालत एयरवेज़ की हो गयी है। So, airways is the new railways of the country, and I am very proud about it. … (*Interruptions*) दादा, उसी के बारे में बोल रहा हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उनकी बातों का जवाब मत दीजिए।

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: The hon. Member has mentioned about the connectivity but let me make it clear from the Ministry that we do not have any direct jurisdiction where we interfere with the connectivity of the airlines. It is entirely a demand-driven process, market-driven process and the airlines decide the connectivity. We offer the infrastructure. अगर एयरलाइन्स कंपनी कहती है कि वे यहां से वहां तक चलाना चाहते हैं, we ensure that there is airport connectivity at both the places. As there has been a big demand from all the Members that we need more connectivity, we are just forwarding the request to the airlines and asking them to favourably consider according to the demand of that airport.

माननीय अध्यक्ष: कल्याण बनर्जी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुदीप बंदोपाध्याय जी।

कल्याण जी, आपके प्रश्न को सुदीप दादा ने ले लिया।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): No issue, Sir. He is my leader.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I am happy to see this young Minister whose father was one of my best friends in the 12th and 13th Lok Sabhas.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): His father, Yerran Naidu was my very dear friend. Shri Baalu was there. That was long time back during the 12th and 13th Lok Sabhas. He knows it well. So, my question is this.

West Bengal is always neglected from all corners. Why is the second international airport in Kolkata not taking shape? The proposal has been taken up. The budgetary allotment has been done. The space has been proposed by the State Government. But why is the Government not initiating the proposal? A reply is being given by the Government that the distance of the second airport from Kolkata is very long. But if the State Government agrees, if the people of West Bengal agree, if the land is available, then why is the second international airport not being initiated immediately which is the desire and expectation of the people of Kolkata and West Bengal for a long time? Will the Minister reply in a positive form?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: I would like to thank the senior hon. Member also who has given his blessings.

Regarding Kolkata, the need is there. If the land is available, if the State also supports for the construction, and if the connectivity between the two locations is possible, then definitely we are going to take it up positively. I would request him that we will definitely meet up after the Session also. We can have a special meeting regarding the Kolkata airport and the development of the new terminal.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस विषय पर बोलने की सबकी मांग है। बहुत सारे माननीय सदस्यों के द्वारा इस पर सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का निवेदन आया है। अगर इस सत्र में समय बचा तो इस सत्र में ही, नहीं तो अगली बार इस विषय को 'कॉलिंग अटेंशन' में लेकर इस पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय देंगे, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो जाए।

(1130/GG/AK)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधान मंत्री जी भी कई बार पूर्णिया एयरपोर्ट और भागलपुर एयरपोर्ट का ज़िक्र कर चुके हैं कि वह खुल गया, पूरा हो गया। लेकिन अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार द्वारा जितनी ज़मीन का अधिग्रहण होना था, उसमें 15 एकड़ लैण्ड

का अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है। मैं आपसे मिल कर भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरूआत करने का आग्रह कर चुका हूँ। क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास कर के दो साल के अंदर वहां विमान सेवा शुरू करने का आपका कोई निर्णय है? मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पप्पू जी, बैठ जाइए नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सर, माननीय सांसद इस विषय के संबंध में हमसे मिल चुके हैं और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है। ज़मीन का जो थोड़ा इश्यु था, वह भी अभी सैटल होने वाला है। हम जल्द ही इस कार्य को प्रारंभ करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा – उपस्थित नहीं।

डॉ. संबित पात्रा।

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में पूछना चाहता हूँ। वर्ष 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में there was a need, which arose for the international airport in Puri, and in the year 2023, the grant for the site clearance was forwarded by the Ministry of Civil Aviation. What is the progress in this field? I am asking this because the airport is to be built in Brahmagiri Tehsil which is very close to the Jagannath Temple and because of the Jagannath Temple and Puri being a tourist destination, this airport is of prime importance. So, I would like to know this through the hon. Speaker. How much have we progressed in it? Thank you, Sir.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I also support it with regard to the Puri airport. … (*Interruptions*) Kindly do it quickly. More Bengalis go to Puri than the Oriyas. … (*Interruptions*) So, kindly do it. … (*Interruptions*)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सर, पुरी जो भगवान जगन्नाथ जी की धरती है, उससे संबंधित जो एयरपोर्ट है, वह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है तो सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहां यह ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहां पर एक नया एयरपोर्ट बने। उसी तरह जब हमारे मंत्रालय को प्रस्ताव मिला कि राज्य वहां पर एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस दे दिया है। जनरल प्रोसिजर यह रहता है कि आफ्टर साइट क्लियरेंस इन-प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए वह राज्य फिर से डीपीआर बना कर, जो भी लैण्ड का हो, पॉवर का हो, वॉटर का हो, वह सब तैयार कर के, लिखता है। पर अभी तक हमें इन-प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए राज्य से कुछ जानकारी आई नहीं है। Since it is a greenfield airport being made on PPP mode, the responsibility lies with the State Government to construct the airport, हम साइट क्लियरेंस देते हैं, वह दे दिया है। अगर राज्य हमें लिखता है कि इन-प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए तो हम ज़रूर उस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी तक इन- प्रिंसिपल अप्रूवल आया नहीं है।

(इति)

(Q. 44)

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Sir, you are a young Minister. I know your answer will not be s template or s copy-paste. I know kind of an answer you will be having an intent to do something for our NRI communities. They are treated by the airlines like people deported from the country. At times, the airline seat prices will be Rs. 5,000 or Rs. 6,000, but for the same sector during the vacation time or during the season when they come to meet their family, they are being charged Rs. 50,000 or Rs. 60,000 or even Rs. 85,000 for Economy Class. How can a four-Member family afford this? How can they come back? At the time of their parent’s death, people cannot even come to attend their funeral. It is a sad state of affairs for our NRIs. So, something must be done for them. They are not orphans. We have a Government to question the airline companies which are treating them very badly. So, I request you to kindly get involved in this to take some action on the issue raised by me.

(1135/UB/MY)

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, the hon. Member has raised a very important question. Of course, I sympathise with the issues that he has flagged. Regarding the rules that we have within the Ministry, the airlines use market-driven approach for deciding the airfares. In fact, after I took charge as the Minister of Civil Aviation, my immediate commitment to the people of this country was to make the airfares affordable. I did not know what was going through it. I was not aware of the rules, but I gave a commitment to the people that we are going to make it affordable. I am ensuring that. Whatever process can be involved in achieving this, we will do it. At present, the rules are totally against doing that. At one point of time, when the DGCA also wanted to do something, the courts got involved. It is a very tricky process. Even while deciding the airfares, there are a lot of parameters that come into play.

Especially, one situation that the whole country needs to be aware of is that there are 800 and odd planes in the country, and because of engine issues, almost 120 planes are grounded right now. They are not able to fly. Due to lack of aircraft that we have in our fleet, there is a lot of additional burden on the existing aircraft. That is also driving up the prices. The happy thing the country should know is that we have 1,200 aircraft order which is the highest in the world. The country with the highest aircraft orders is India and we are ensuring that they are delivered on time. We will do whatever best we can do in this scenario.

Additionally, there are already civil aviation requirements. Already, the rules are in place which protect the passengers. If the airline is trying to manipulate the situation or they are not trying to give them a prior information, or if they are not trying to give them refund, the rules are already in place. If the hon. Member has any specific case that has happened, we are very much willing to support the case and fight on behalf of the passenger and ensure that his right is protected. The customer is always the king. That is our priority.

माननीय अध्यक्ष: हाँ, आप बोलिए। मैंने आपको मौका दिया है।

… (व्यवधान)

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Sir, you talked about specific cases. The extreme exploitation has become a new normal for the airlines. An amount of Rs. 1,10,000 crore is the remittance from NRI people that a State like us receives. What do we give them back? Why can we not constitute a high-level committee to look into it, to hear out our people, to know the social economic consequences, to enact a new law, and to stop this exploitation? Why can we not constitute a high-level committee?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: It is a suggestion being given by the hon. Member. We will definitely look into it.

SUSHRI SAYANI GHOSH (JADAVPUR): Sir, there has been rampant increase in the number of elderly passengers and senior citizens travelling by airline due to various reasons like physical convenience and saving time. Is there any senior citizen discount or concession available right now? If so, I would request the hon. Minister to provide the details. If not, will the hon. Minister take into consideration any sort of concession or discount for the senior citizens or measure for ease of commutation and easier access?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: I would like to comment on behalf of the Ministry. Whatever best we can do for the differently-abled community or the senior citizens of this country, we are going to do it. I do not have specific details on what is being done on that side, but I will pass on the information to the hon. Member.

माननीय अध्यक्ष: हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन आप बैठे-बैठे बहुत टिप्प्णी करते हैं।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, thank you. I would like to congratulate the hon. Minister. He is young and very dynamic. His father was a good friend of the DMK Party.

I have a habit of booking the flight tickets for Delhi online through the Vistara Airlines which belongs to Tata, and the software is operated by Tata's TCS. When I book a one-way ticket from Chennai to Delhi, it is Rs. 33,000. But when I go to make the payment, an error message pops up. The moment the error message comes, the price goes to Rs. 93,000 or Rs. 78,000.

(1140/SRG/CP)

Sir, this has been happening probably because the TCS is using a super messy software, and everybody has got a Miles Account. So, we have logged in. Sir, this has been happening very frequently on the Delhi-Chennai or Chennai- Delhi route. Sir, this does not come under the DGCA route. DGCA is the In-charge when the airline cancels a flight or re-schedules it. But this is happening in the software. There is a conspiracy happening. We would like you to do a thorough inquiry. Tata is having a monopoly in this business segment. The money is paid by the Government of India.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर विषय उठाया है। यह बहुत गम्भीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने भी शिकायत की है। क्योंकि इसका पैसा पार्लियामेंट से जाता है, इसलिए हमें चिंता है।

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Definitely, Sir. We will get the matter investigated.

Like our senior Member has mentioned, the DGCA looks after the rights of the passengers and it dwells into that. Also, there is a DGCA Tariff Monitoring Unit which looks after this specific issue that he has raised. So, we are going to investigate that. We are going to ensure that these kinds of incidents do not happen in the future.

(ends)

(प्रश्न 45)

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जो टेबल पर आंसर किया गया है, मैंने उसे पूरे ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहती हूं। एमएसएमई में देश की महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने का बहुत इंपोर्टेंट रोल रोल था। इस टेबल पर जो आंसर रिप्लाई किया गया है, उसमें बताया है कि वर्ष 2021 तक यह संख्या 4 लाख 88 हजार थी। मिनिस्ट्री 'उद्यम' नाम की योजना 1 जुलाई, 2020 को लेकर आई, वह बहुत ही अच्छी थी, पेपरलेस थी, ऑनलाइन थी, सेल्फ डिक्लरेशन पर थी। इसकी वजह से जो आंसर मुझे मिला है, उसमें महिलाओं की संख्या 4 लाख 88 हजार से बढ़कर 1 करोड़ 84 लाख हुई है। मैं मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहती हूं कि 'उद्यम' को और सपोर्ट करने के लिए उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म 11 जनवरी, 2023 को लेकर आए हैं, जिससे कि महिलाओं को यहां पर रजिस्टर करने में खासकर बहुत सुविधा हो रही है।

मेरा प्रश्न है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो महिलायें एमएसएमई में काम कर रही हैं, उनका सैक्टरवाइज ब्रेकडाउन क्या है?

श्री जीतन राम माँझी: अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि भारत सरकार जो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महिलाओं, वीकर सैक्शन, अनुसूचित जाति, मेरे कहने का मतलब है कि जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान दे ही है। महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने आज माननीय संसद को यह बताया जा सकता है कि महिलाओं के उत्थान में खासकर एमएसएमई जो हमारा विभाग है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसकी चर्चा हमने कर दी है।

इनका अलग-अलग फ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। इसमें दो टाइप के सैक्शन होते हैं, एक होता है 'उद्यम', दूसरा वह होता है जो साधारण रूप में सब शर्तें पूरा नहीं कर सकती हैं, उनको इसमें लेते हैं। उद्यम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग-अलग है। माइक्रो में उन्होंने 26,921 करोड़ रुपये दिए हैं, स्मॉल में 7,011 करोड़ रुपये दिए हैं, उसी प्रकार से यूएपी में भी 19,900 करोड़ रुपये दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि अलग-अलग दोनों में प्रावधान किया गया है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, 'उद्यम' में 21.35 प्रतिशत उनका इन्वॉल्वमेंट है।

(1145/NK/RCP)

यूएपी में 63.11 का इन्वोल्मेंट है, इस तरह से कहा जा सकता है कि हम महिलाओं को इसमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी माननीय सांसद ने जो सूचना मांगी है, उसको हम भिजवा देंगे।

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आधी आबादी कितनी महत्वपूर्ण है, यह प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं, यह जो नम्बर बढ़ा है उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। मेरा एक सवाल है, हम यहां सभी साथी बैठे हैं। उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर्स हैं, अगर हमें यह नम्बर पता चल जाए कि अर्बन और रूरल में कितना नम्बर रजिस्टर्ड हुआ है तो यहां बैठे हुए सभी साथियों को अपने-अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी होगी।

मेरा मंत्री जी से सवाल है कि एमएसएमई में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी परसेंट महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, अगर यह बताएंगे तो हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद।

श्री जीतन राम माँझी : स्पीकर महोदय, वह मैंने बता दिया, टोटल एमएसएमई में जितने रजिस्टर्ड हुए हैं, उसकी रिपोर्ट है, उसके तहत 24/7/2024 से ही उसको हमने इम्प्लिमेंट किया है। उसके नम्बर्स मेरे पास हैं, हम उसको भिजवा देंगे। जहां तक परसेंटेज का सवाल है, टोटल परसेंटेज 38.80 है। जहां तक वूमेन का सवाल है, इसमें दो भाग हैं, एक उद्यम का है, उसमें 21.3 प्रतिशत है और दूसरा यूएपी है, जो उद्यम में क्वालिफाई नहीं करते हैं, जैसे पैन कार्ड की जरूरत है, जीएसटी की बात होती है, बहुत छोटे-छोटे लोग है, जैसे कोई दर्ज का काम करता है और छोटा-छोटा काम करते हैं, उनके पास पैन कार्ड और जीएसटी नम्बर नहीं होता है, उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उनकी संख्या जो टोटल 38.80 प्रतिशत है, उसका 63.11 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि हम महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है।

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Speaker, Sir, the MSMEs are called the powerhouse of Indian economy. Reportedly, they account for about 11 crore jobs in the country, and they contribute 29 per cent of the country's GDP. They not only fuel economic growth, but also serve as a vital catalyst for inclusive development across various sectors. The PM Modi's Government talks of women-led development.

I would like to know this from the hon. Minister. How many registered MSMEs are there in Odisha and in the Bhubaneswar Parliamentary segment? What are the concrete steps or initiatives taken by the Central Government to ensure women's participation in the MSME sector? Thank you.

श्री जीतन राम माँझी : स्पीकर महोदय, हमने अपने जवाब में बताया है, हमने प्रश्न के जवाब में ही कहा है कि जहां महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या का सवाल है, यह समस्त भारत में 1 करोड़ 84 लाख 57 हजार है। उसमें हिमाचल प्रदेश में 83 हजार 834 है। जहां तक ओडिशा का

सवाल है 6 लाख 96 हजार 559 है। प्रश्न में मयूरभंज के बारे में पूछा गया था, मयूरभंज में यह संख्या 35 हजार 935 है, फ्रैक्शन में भी बता दिया गया है।

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you Speaker, Sir. The Minister has given a very elaborate answer. I would like to ask a supplementary regarding the actual functioning of this entire process in UAP and Udyam. There was an amendment which had taken place in 2018 regarding public procurement policy which was amended mandating the Central Government, the Departments and the Undertakings to go in for procurement from the women entrepreneurs to the extent of three per cent.

(1150/PS/SK)

There are instances where the cottage industries go for procurement within the limits prescribed. But when the small timers -- the small-time enterprises run by women entrepreneurs -- supply it, the bills are not being paid in time because of paucity of funds with the Undertakings itself. Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to ask this question to the hon. Minister. What measures are being taken in this direction? It is because the small timers do not have any alternative but to go for closure of their units. What measures are being taken by the Government to see that this anomaly is taken off and the units run seamlessly? Thank you.

श्री जीतन राम माँझी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस संबंध आपको और सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मंत्रालय विभागों और उपक्रमों में जिस प्रकार से महिलाएं, खासकर जो उद्यमी हैं, को इतनी रियायत दी गई है कि जो सामान लोग खरीदते हैं उसमें तीन प्रतिशत सामान महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को खरीदें, इसके लिए सुविधा दी गई है। इसमें 300 करोड़ रुपये का कारोबार महिलाओं ने किया है। इसमें 19,000 महिलाएं लगी हुई हैं। इससे उद्यमियों को फायदा हुआ है। इसकी शुरूआत 1.7.2020 से हुई है, इसे देखते हुए जो आंकड़ा दिया गया है, यह पर्याप्त है, हालांकि हम इसे और आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाओं को कम से कम 50 परसेंट उद्यमियों में लाभ दे सकें। (इति)

(Q.46)

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to ask question.

The main question is this. Will the hon. Minister of Jal Shakti be pleased to state:

(a) The details of the number of Functional Household Tap Connections provided under the Jal Jeevan Mission during the last five years in each district of Andhra Pradesh year-wise.

(b) The percentage of rural households in Andhra Pradesh that have received FHTCs under JJM compared to the total number of rural households in the State.

(c) Whether any audit has been conducted to measure the impact of JJM on reducing the distance to water sources for rural households in Andhra Pradesh; and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

माननीय अध्यक्ष: सब विवरण तो मंत्री जी ने दे दिया है।

… (व्यवधान)

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): Yes, Sir. I thank the hon. Minister for giving an extensive answer for that. Now, I would like to ask the supplementary question.

Under the Jal Jeevan Mission, Andhra Pradesh is the sixth lowest State in terms of households with tap water supply, which is less than the national average of 77 per cent. Therefore, I would like to ask the hon. Minister whether the State Government has contributed its share of funds under the Jal Jeevan Mission during the last five years.

Has the State Government submitted Utilisation Certificates under this scheme for the last five years? Has the Central Government observed any discrepancies or fund diversions by the State Government of Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission over the last five years?

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय अध्यक्ष जी, जब जेजेएम स्कीम आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में शुरू हुई, उस समय आंध्र प्रदेश में 32 परसेंट कनैक्शन्स लगे हुए थे। पिछले पांच सालों में करीब 40 परसेंट यानी यह काम आंध्र प्रदेश में 72-73 परसेंट तक हो चुका है। आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जो फंड मिलता है और जो टेक्नीकल सहायता मिलती है, हम उसके आधार पर 100 परसेंट काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

(1155/SMN/MK)

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): I would like to ask this question to the hon. Minister. What are the major challenges that are being faced by the Government in achieving 100 per cent functional household tap connections in Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission? What measures are being taken to overcome these challenges especially in the remote districts?

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में करीब-करीब 11 जिलों और 8 यूटी/ प्रदेशों के अंदर 100 परसेंट काम हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में और कई राज्य 100 परसेंट की ओर बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश भी 73 परसेंट काम के साथ चल रहा है और उनकी बाकी जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है, वह भी पूरी हो गई है। उनका काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह भी 100 परसेंट क्लब में जुड जाएगा। आंध्र प्रदेश का भी काम हो जाएगा और सबको गाँव-गाँव तक पानी मिल जाएगा।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न मूल रूप से आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन 'जल जीवन मिशन' एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि बिहार में भूजल में गंदे आर्सेनिक की अतिरिक्तता की वजह से बड़े पैमाने पर जो कैंसर की बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए बिहार के अंदर 'जल जीवन मिशन' को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? कैसे उसको प्रभावशाली ढंग से वहां चलाने की कोशिश हो रही है? बिहार में

'जल जीवन मिशन' के तहत वर्तमान में अभी तक नल कनेक्शन वाले कितने घरों को पानी मिला है? खास तौर पर मैं अपने क्षेत्र सीमांचल, जो बिहार का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है, उसमें भी हमारा क्षेत्र जो कटिहार है, वहां हम अपने भ्रमण के दौरान देखते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं चल रहा है। मैं बिहार में इस कार्यक्रम को मजबूती से चलाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार एक ऐसा प्रदेश है, जिसने जेजेएम के लिए केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मांगा है। उन्होंने अपने नाम से, अलग तरीके से नल से जल देने का काम वहां पर किया है। जैसा इन्होंने कहा कि पानी में अलग-अलग प्रकार कुछ द्रव्य आते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम है तो हम जरूर इस बात को वहां की सरकार के ध्यान में रखेंगे कि इसके ऊपर काम किया जाए। हमारे पास राज्य द्वारा भेजी गयी जो रिपोर्ट है, उसमें नल से जल का करीब-करीब 100 परसेंट काम बिहार में राज्य सरकार ने अपने बलबूते पर कर दिया है।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): There is a good progress that has been made with respect to Jal Jeevan Mission in the last five year, that is, the number of new connections have increased from three crore to almost 11 crore. And also, in Andhra Pradesh, 39 lakh new connections have been added to the 30 lakh connections already given. But the problem is this.

I come from the Constituency of Palnadu where Rs. 350 crore has been given under the Jal Jeevan Mission. We are giving connection from the overhead tank to every household. But I come from a location, from a Constituency where even if you dig a borewell of 1200 feet, you will not get water. So, we have connection from overhead tank to the household but there is no water in that overhead tank. The funds that you have allocated, that you have spent, are not being used properly. So, if you can guide us in such a way so that the source of water can be found whereby the water is actually given to the overhead tank. Then those tap connections will be of any use. Unless you do that, this is a huge wastage of funds, which is happening. If you can guide us how that can be addressed, it will be of great help to us.

Thank you very much.

(pp. 22-30)

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत गंभीर है और कई जगह से कम्प्लेंट भी आती है। यह राज्य सरकार का काम है और यह उनकी जवाबदेही है। उसका सोर्स ढूंढ़ना भी उन्हीं का काम है। मगर, कई जगहों पर राज्य सरकारों ने वहां पर जो बोर किए हैं, उनमें पानी नहीं पाया गया या कम पाया गया, उसकी वजह से वहां मार्च-अप्रैल तक पानी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। उसकी वजह से वहां नल होता है, जल नहीं होता है। हमने अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ अलग-अलग मीटिंग करके उनके ध्यान में यह बात रखी है।

(1200/SJN/SM)

अभी जो नया टेक्निकल सिस्टम आया है, जल कहां है, कितनी मात्रा है, उससे हम वह सब कुछ जान सकते हैं। उसके आधार पर वहीं पर बोर किया जाएगा। अगर उसके आधार पर बोर होगा, तो पानी भी मिलेगा। अगर कोई गांव बड़ा है, तो एक से ज्यादा बोर किए जाएं, हमने उनको इस प्रकार का सुझाव दिया है। चाहे वह दो बोर करें या तीन बोर करें, तब भी उनको मंत्रालय की ओर से पैसा दिया जाता है। मगर पानी की मात्रा तय करके गांवों की जो अपेक्षा है, हर गांव में 55 लीटर शुद्ध पानी देने की योजना बनी है, तो उतनी मात्रा में पानी मिले। अगर उस तरह की प्लानिंग होगी, तो मेंबर की जो समस्या है, वह हल हो जाएगी। हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 2, श्री किंजरापु राममोहन नायडू जी।

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.335(E) in Gazette of India dated 19th June, 2024, under Section 14A of the Aircraft Act, 1934.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(1) The Electricity (Second Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.45(E) in Gazette of India dated 17th January, 2024.

(2) The Electricity (Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.36(E) in Gazette of India dated 11th January, 2024.

(3) The Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) (Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.146(E) in Gazette of India dated 29th February, 2024.

(4) The Electricity (Third Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.181(E) in Gazette of India dated 12th March, 2024.

(5) The Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.125(E) in Gazette of India dated 22nd February, 2024.

(6) The Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023, published in Notification No. L-1/2064/2022-CERC in Gazette of India dated 23rd January, 2024.

(7) Notification No. RA-14026(11)/4/2020-CERC. published in Gazette of India dated 12th April, 2024, extending the period of applicability of the RE Tariff Regulations, 2020, till 30th June, 2024 or notification of the Regulations by the Commission for the next control period, whichever is earlier.

(8) The Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2024, published in Notification No. L-1/270/2023/CERC. in Gazette of India dated 14th June, 2024.

(9) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Second Amendment) Regulations, 2024, published in Notification No. L-1/261/2021/CERC. in Gazette of India dated 1st July, 2024.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री किरेन रिजिजू जी।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : अध्यक्ष महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना सं. फा.सं. एफ/1/0027/2019/सीओआरडी/आवासन (समन्वय) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.753(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण, निदेशक (अनुसचिवीय), भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.635(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (प्रणाली), भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.117(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (आयोजना), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.355(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) दिल्ली विकास प्राधिकरण (आयुक्त और सचिव के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.366(अ) में प्रकाशित हुए थे।

MOTION RE: 1ST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1203 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the First Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th July, 2024."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 जुलाई, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिवहन, पर्यावरण और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में परिवहन, पर्यावरण और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन
राजघाट समाधि समिति

आवासन और शहरी कार्य मंत्री; तथा विद्युत मंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :-

"कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

------

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1204 बजे

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Speaker Sir. I wish to draw the attention of the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas to the woeful situation of traditional fishermen in Kerala who are grappling with the debilitating shortage of kerosene.

The limited quantity of kerosene available through the Public Distribution System has proven vastly detrimental to the operators of thousands of small country boats which do not have onboard motors. They use kerosene as fuel. They say that they are scarcely able to make their both ends meet. The traditional fishermen are compelled to buy kerosene from black marketeers at extraordinary prices.

It is high time that the Union Government took cognisance of the agony of these Indian citizens. Most of them are socially and economically disadvantaged persons.

(1205/RP/SPS)

The Government should augment the quantity of subsidised kerosene made available from the PDS. Moreover, both the availability of kerosene and the volume of their daily catch are in doubt which make numerous fishermen cut short their working day to toil in odd jobs in the hope of earning, at least, some money. The lack of support from the Union Government is worsening their misery. In fact, the allocation by the Union Government of PDS kerosene to Kerala has declined from 55,000 kilo litres during fiscal year 2018-19 to just 15,000 kilo litres last year. I know, the Union Government will say that they want to encourage States to shift to cleaner and safer fuels like LPG, PNG, and so on which is why they are reducing PDS kerosene. I understood, Sir. But, coastal States like Kerala are already amongst India's foremost States in terms of LPG and green energy coverage but the demand for kerosene is only to alleviate the agony of our traditional fishermen who rely on kerosene for fuelling their fishing boats.

If the Union Government truly desires to facilitate the transition to more sustainable fuels, then, it must subsidise an alternative, perhaps, provide other

---

* Please see pp.304 for List of Members who have associated

kinds of engines to our fisher people with genuine subsidy. Otherwise, they should provide more kerosene, Speaker Sir.

Thank you very much.

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Hon. Speaker, Sir, my erosion-prone constituency of Dakshin Maldaha in West Bengal consists of five blocks in Maldaha District and two blocks in Murshidabad district.

Since the construction of the Farakka Barrage in 1971, which is managed by the Water Resources Department, severe river erosion has occurred in Maldaha and Murshidabad Districts. The construction of the Barrage has caused huge silt and sand deposits which led to the creation of new silt land formations and caused the Ganges to change its course by 17 kilometers east towards Maldaha. More than 900 square kilometers of land has been eroded since then.

This has meant that five of the seven Blocks in my constituency namely, Farakka and Samserganj of Murshidabad District and Manikchak, Mothabari, and Baisnabnagar of Maldaha District are heavily impacted by erosion because over the years the Ganges is constantly changing its flow and course. More than one lakh families or 7,00,000 people in this vast area have lost agricultural land and homes into the Ganges. They are facing severe problems. More than 35 primary schools and 10 secondary schools, innumerable temples, mosques, markets and Government infrastructure have been destroyed by Ganga erosion. In the last seven to eight years alone, severe erosion has started again in various parts along the river. About 5000 families from my Constituency are still living in temporary shelters and temporary colonies along the river and not on their own land.

Furthermore, there is a grave concern that the part of Ganges River in Manikchak Block of Dakshin Maldaha may soon merge with the Fulahar River channel of Ratua potentially wiping out large areas of Bhutni, Bilaimari and and Ratua.

Sir, I offer a few suggestions to this burning issue of erosion caused by the Ganges. The Ganga River is a national river so the Central Government and Farakka Barrage Authority with the cooperation of the State Government of West Bengal should take back full responsibility for anti-erosion work for a 120-kilometer stretch of the Ganges. This was the case from 2005 onwards

under the UPA Government. The Central Government took the responsibility for managing 40 kilometres upstream into Malda from the Farakka Barrage and 80 kilometres in Murshidabad downstream of the Farakka Barrage.

The current erosion prevention methods using sandbags are ineffective. Large scale investment in the present Budget using boulder pitching, porcupine work and even dredging is required. New technologies and approaches such as geo-synthetic tubes need to be explored for their effectiveness to save the people.

The rehabilitation and housing for thousands of families affected by erosion, including legal land rights for 5000 families in rehabilitation colonies is required.

Thank you, Sir.

(1210/MM/NKL)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज लंच नहीं होगा। 1 बजे से सामान्य बजट पर चर्चा पुन: आरम्भ होगी।

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Hon. Speaker Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, I rise to bring to your urgent attention about the recurring flooding of the Teesta River which is severely affecting the areas like Totgaon under Mal block and Gajoldoba under Rajganj block, apart from some other areas of Mekhliganj and Maynagur blocks in my constituency. Despite repeated flooding, the West Bengal Government has failed to implement any permanent solution to this, resulting in displacement of numerous people, significant agricultural loss due to siltation, and also tragic loss of human and animal lives. The persistent flooding suggests potential misuse of Central funds by the State Government as temporary measures are implemented annually instead of addressing the root cause.

Sir, I urge upon the Central Government to constitute a team to analyse the situation and propose permanent measures to mitigate flooding. Immediate intervention is necessary to safeguard the livelihoods and homes of our citizens and also to prevent further loss of lives.

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली के बारे में बताना चाहूंती हूं। मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में पंचायती राज होने के बावजूद यहां जिला पंचायत, पंचायत एवं नगर पालिका में अधिकार न होने की वजह से आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं, जैसे- अच्छी सड़कें, स्वच्छ पीने का पानी, सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है।

महोदय, भारत सरकार की सभी स्कीम्स प्रदेश की जनता के घर-घर तक पहुंचे, साथ ही जनता को उनका हक और अधिकार मिले। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रदेश को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पुन: असेंबली दिए जाने के संदर्भ में वर्ष 2014 में महामहिम उपराष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में तथा स्टेंडिंग कमेटी ने भी दोनों प्रदेशों को पुन: विधान सभा देने की सिफारिश की थी। इस विषय को वर्ष 2019 एवं वर्ष 2021 में तत्कालीन सांसद मोहनभाई देलकर जी ने भी इस सदन में रखा था। यह मुद्दा तीसरी बार मैं आपके सामने रख रही हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इस पर उचित कार्यवाही की जाए। दादरा और नागर हवेली को पुन: असेंबली दिए जाने की दिशा में कार्य शुरू करने की कृपा करें।

महोदय, जब तक असेंबली का गठन न हो जाए, तब तक सभी स्वराज संस्थाओं को पूर्ण अधिकार दिए जाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद! जय दादरा नागर हवेली!

श्री अनूप संजय धोत्रे (अकोला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय किसानों से संबंधित है।

Sir, I request that the crop loans should be treated on a par with the other cash credit loans. To get interest subvention benefit, farmers have to pay their entire loan amount by 31st March every year. This is unfair because the farmers have to often sell their produce at lower prices to meet this deadline. In contrast to other industries, they need to maintain the sanctioned loan amount to renew their cash credit loans and have to pay the full amount.

मेरी विनती है कि किसानों को उनकी पूरी उपज का जब मार्किट में प्राइस कम रहता है तब उनको अपनी क्रॉप बेचनी पड़ती है। अगर किसानों के लोन को कैश क्रेडिट केटेगिरी में डाला जाए और उनको वही ट्रीटमेंट मिले तो किसानों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। एमएसपी में सरकार के 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं, उसमें भी राहत मिलेगी। किसानों को इससे बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। हमारी मोदी सरकार ऐसा एक क्रांतिकारी निर्णय लेगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं।

(1215/YSH/VR)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, संविधान खतरे में है। हम यहां पर दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं। सभी सरकारों की नीतियां, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एक मात्र लक्ष्य यही होता है कि उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं संथाल परगना एरिया से आता हूँ। जब झारखण्ड बिहार से अलग हुआ तो वर्ष 2000 में आदिवासियों की पॉपुलेशन संथाल परगना में 36 प्रतिशत थी और आज आदिवासियों की पॉपुलेशन 26 प्रतिशत है। 10 प्रतिशत आदिवासी कहां पर गायब हो गए, कहां खो गए, इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता नहीं करता है। वह वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है।

हमारे राज्य में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। वह इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। आज हमारे यहां पर बांग्लादेश के घुसपैठ लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं। यह हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहां पर जो महिलाएं लोक सभा का चुनाव लड़ती हैं, वे आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्ष महोदया हैं, उनके पति मुसलमान हैं। आदिवासी जो मुखिया होते हैं, आप समझिए कि हमारे यहां पर 100 ऐसे मुखिया हैं, जो आदिवासी के नाम पर हैं और उनके पति सभी के सभी मुसलमान हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अभी विधान सभा का चुनाव हुआ। यहां सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक पांच साल में 15 से 17 परसेंट पॉपुलेशन बढ़ती है या वोटर्स बढ़ते हैं। हमारे यहां पर 123 परसेंट बढ़े हैं। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आया हूँ, उसकी एक विधान सभा मधुपुर में लगभग-लगभग 267 बूथों पर 117 परसेंट मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। झारखंड में कम से कम 25 विधान सभाएं ऐसी हैं, जहां 110 परसेंट तक इनकी आबादी बढ़ी है। यह एक बड़ा चिंता का विषय है।

दूसरा, हमारे यहां पर पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डागापाडा में दंगा हो गया था। दंगा इसलिए हुआ है, क्योंकि बंगाल से ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं। हिंदुओं के गांव के गांव खाली हो रहे हैं। यह बड़ा ही सीरियस विषय है।… (व्यवधान) यह मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूँ। यदि मेरी एक बात भी गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ।… (व्यवधान) बंगाल, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया है। यह ऑन रिकॉर्ड है और झारखण्ड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और असरगंज, चूँकि झारखंड हाईकोर्ट का यह 22 जुलाई का ऑर्डर है, जो यह कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां पर भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और जो पूरा संथाल परगना है, उसे यूनियन टेरेटरी बनाया जाए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे।… (व्यवधान) वहां पर

एनआरसी लागू कीजिए।... (व्यवधान) इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो वहां सबसे पहले हाउस की एक कमेटी को भेजिए और उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एमपीज को रखिए। दूसरी, लॉ कमीशन की वर्ष 2010 की जो यह 235वीं रिपोर्ट है, उसको लागू कीजिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य सदन का सदस्य नहीं है, अगर उसका नाम लिया गया होगा तो उसको निकाल देंगे।

... (व्यवधान)

*SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you hon. Speaker for giving me this opportunity. This matter pertains to Tandur and Basheerabad railway line. This is an important and urgent matter. Railways is a mode of transport for all of us but for the people of Basheerabad it is a mode of education, because passengers travel to schools by using trains. It is also a mode of employment because people travel for their jobs. People travel from Vikarabad and Tandur to Hyderabad. For medical emergencies as well, people depend on the railways here. There is the river 'Kagna' between Tandur and Basheerabad. If you have to travel by road, we will have to take a long detour but if we go by train it goes straight because of the railway bridge over this river. Several trains pass through Basheerabad but they do not stop in Basheerabad. We had made several requests that train number 17319 Hubli Express may be stopped at Basheerabad. We have been making this request for the last five years. Recently Rayalaseema Express, which used to stop at Basheerabad, was cancelled for the last three days. Now people of Basheerabad are deprived of a regular train which used to stop here. Their request for giving stoppage to new trains has not been accepted yet. This is an important issue which I would like to bring to the notice of the Railway Minister on behalf of the people of Tandur. People of Tandur and Basheerabad will be thankful if the Railway Minister accedes to their request. Once again, I thank you for giving me this opportunity.

---

* Original in Telugu

(1220/RAJ/SAN)

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय को अवगत कराना चाहता हूं कि एमबीबी हवाई अड्डा,अगरतला त्रिपुरा का एक मात्र एयरपोर्ट है। वह नॉर्थ-ईस्ट रीजन में यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। वहां नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 04.01.2022 को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां एक हजार अंतरराज्यीय और दो सौ अंतरराष्ट्रीय यात्री संभालने की क्षमता है, बीस चेक इन काउंटर्स हैं और तीन मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता है। अगरतला-चिटगांव मार्ग पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी है। वहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और ग्राउंड लाइटिंग की सुविधा मौजूद है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 04.01.2023 को एमबीबी हवाई अड्डे को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया है। मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस संबंध में घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय में तत्कालीन माननीय नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया है कि इमीग्रेशन चेक पोस्ट का विषय गृह मंत्रालय से संबंधित है। माननीय नागर विमानन मंत्री जी से अनुरोध है कि गृह मंत्रालय से बातचीत कर एमबीबी एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन चेक पोस्ट शीघ्र-अतिशीघ्र शुरू करे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करे।… (व्यवधान)

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद में एक भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित चिकित्सालय नहीं है।

महोदय, फर्रूखाबाद जनपद में सैकड़ों की संख्या में भट्टे भी हैं, बीड़ी उद्योग का बड़ा काम होता है और साथ ही साथ में तंबाकू के भी कई गोदामें-कारखाने हैं। इसी के साथ-साथ कपड़ा पेंटिंग एवं जरदोजी के बड़े काम होते हैं, जिनमें हमारे यहां लगभग हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। परंतु उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक भी श्रमिक चिकित्सालय नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रमिक एवं रोजगार मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद में एक श्रमिक चिकित्सालय ईएसआईसी, अस्पताल की स्थापना कराने की कृपा करें। जब कोई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होती है, तो वहां वे चिकित्सा करा कर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें।…(व्यवधान)

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कौशाम्बी से चुन कर आया हूं। मैं सबसे पहले उन लोगों की आवाज रखना चाहता हूं जिनकी आवाज सदन में कम उठाई जाती है। हमारे इंडियन फोक आर्ट फेडरेशन के लोगों और कल्चरल लोगों की आवाज कम उठाई जाती है।

सर, प्रयागराज में एनसीईजेडसीसी ऑडीटोरियम बहुत समय से रेनोवेट हो रहा है। उनकी तीन प्राथमिकताएं हैं। उनकी तीन छोटी मांगे हैं, जो मैं मिनस्टर ऑफ कल्चर के सामने रखना चाहूंगा।

(1225/KN/SNT)

सर, एक मांग यह है कि थोड़ा इंटरवेंशन करके उनका जो रिनोवेशन प्रोसेस है, वह स्पीड-अप करें। क्योंकि वे अपनी बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं और अपनी प्रेक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी उनकी मांग यह है कि उनकी बुकिंग फीस चार गुणा बढ़ाई जा रही है। यह एक प्राथमिकता है, क्योंकि उन पर जो

चार गुणा भार है, वह बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसका संज्ञान लेते हुए उस बुकिंग फी को थोड़ा कम करें। उनकी तीसरी मांग यह है कि जो बुकिंग स्लॉट्स हैं, वह चार से छ: घंटे हैं। वे पूरे दिन काम करके आते हैं और शाम का समय उनको प्रेक्टिस करने के लिए मिलता है। माननीय मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसका संज्ञान लेते हुए, हमारे जो फोक आर्ट फेडरेशन के लोग हैं और जो कल्चरल लोग हैं, उनका संरक्षण करते हुए इन तीन प्राथमिकताओं पर काम करें। धन्यवाद।

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूंगी, जिसका सरोकार जन-जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफी लम्बे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले, पानीपत-कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह बेहद आवश्यक रेलमार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थस्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है।

अंत में दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेलमार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिससे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद जरूरी है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

*SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. I want to raise an important issue regarding the injustice faced by the people of Tamil Nadu. I wish to remind you of the unfair treatment being faced by the people living in and around Kappalur Toll Plaza. I had raised this issue in the same House on 9th December 2022. Thereafter I had a meeting with the hon. Union Minister of Highways Shri Nitin Gadkari on 22nd December 2022 and discussed this issue. The hon.Minister gave a reply in March 2023. I urged upon him to shift the Kappalur Toll Plaza to some other place. But he assured that he will find a solution to this issue in a scientific manner. Even after 15 months after his assurance, the same atrocities continue to take place at Kappalur Toll Plaza. On 30th July 2024, the people of this area have planned to do a lockdown strike in Tirumangalam. The whole city of Tirumangalam will get into strike mode for removing this Toll Plaza. This is a clear indication of the approach of BJP being anti-people. For around 900 vehicles of this area, each vehicle has to pay Rs 350 for just passing through two kms, which is unjustified. This is an unfair treatment. I request that the vehicles belonging to Tirumangalam and Kappalur Sipcot should just be exempted from paying this toll fee. The BJP Government should provide justice to Tamil Nadu. Why is the Government reluctant to provide us with these rights? I request, through you, Sir, that the Union Government should come forward to stop such unfair and unjust treatment faced by the people of Tirumangalam and Kappalur Sipcot due to Kappalur Toll Plaza. Thank you.

* Original in Tamil

(1230/VB/AK)

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं आदरणीय श्री कांशीराम जी, जिन्हें बहुजन नायक और मान्यवर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति में एक राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सदा ही सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह किसी से छिपा नहीं है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। लेकिन वह राजनीति से ज्यादा देश के दबे-कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मान्यवर कांशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किये जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए।

धन्यवाद।

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपनी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया।

हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत-सी ऐसी कला शैलियाँ हैं, जो विलुप्त हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में घर बनाने की एक कला शैली है, जिसे 'काठ कुनी' कहा जाता है। वहाँ भेड़ और याक के उनों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाये जाते हैं, जैसे जैकेट्स, टोपियाँ, शॉल, स्वेटर्स आदि, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है। ये कला शैलियाँ हमारे यहाँ पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश का जो संगीत है, खासकरके स्पीति, किन्नौर और भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाले ट्राइबल्स के कपड़े, उनके फॉक आर्ट फॉर्म्स हैं, वे भी विलुप्त होते जा रहे हैं। इन सभी के विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

धन्यवाद।

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान उस महत्वपूर्ण रेल परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो आज से लगभग डेढ़ दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को देखते हुए छितौनी-तमकुही रेल परियोजना शुरू की गई थी। सात-आठ साल के अन्दर पटरी बिछाकर और छितौनी का एक नया रेलवे स्टेशन बनाकर वह परियोजना बंद हो गई थी। पिछले वर्ष लोगों की भारी मांग पर माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने फरवरी माह में इस बंद पड़ी परियोजना को डी-फ्रीज़ करते हुए, गोरखपुर रेल महाप्रबंधक से इसका नया डीपीआर मांगा। 5 महीने से इस लंबित परियोजना की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि बिहार

और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को पूरा कराने के लिए इस अति महत्वपूर्ण बंद पड़ी परियोजना को पुन: शुरू करायी जाए।

धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को सेब उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में दूसरे नम्बर पर सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है, विशेष रूप से इसका 80 प्रतिशत उत्पादन मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश में सेब की जो आर्थिकी है, वह लगभग 5 हजार करोड़ रुपए की है।

महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बर्फबारी न होने के कारण, भारी बरसात के कारण और कई बार ओला वृष्टि के कारण सेब की फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों और बागबानों को इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार से अन्य फसलों को फसल बीमा योजना के तहत लाया गया है, उसी प्रकार से सेब की खेती को भी फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि बागबानों को आपदाओं के कारण जो नुकसान होता है, उससे उसकी भरपाई की जा सके और किसानों को मदद दिया जा सके।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1235/UB/PC)

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Sir, despite mandated reservations, there is a prolonged issue of insufficient recruitment of faculty from Other Backward Classes (OBC), Scheduled Castes (SC), and Scheduled Tribes (ST) in the Central institutes of higher education. The Government data reveals a persistent and substantial gap in faculty positions within the reserved categories.

In 2021, 6,074 faculty positions remained vacant across 42 Government-run universities, with 75 per cent falling under the reserved categories. A recent Parliamentary data on 1st August, 2023, revealed that only four per cent of professors recruited belonged to the OBC category. Data for an RTI reply in 2023 also exposed faculty shortages in SC, ST, and OBC categories in several departments of IIT-Delhi, with 14 departments having no faculty from SC or ST, 24 departments lacking any SC faculty, 15 departments lacking any ST faculty, and nine departments having no faculty from OBC.

The Central Universities, including IITs, mandated to follow the reservation policies allocating 15 per cent to SCs, 7.5 per cent to STs, and 27 per cent to OBCs in faculty appointments and admissions, display a clear

mismatch between the Government equity goals and the actual recruitment outcomes.

1236 hours (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

I urge the Government to take immediate corrective action. Initiatives like intensified special recruitment drives, rigorous implementation monitoring, and forward-looking measures such as Government-sponsored preparatory programs for aspiring faculty are essential.

*SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): (Thank you Chairperson for allowing me to speak for the first time in the 'Zero Hour', as a first-time elected Member of Parliament from Medak. Medak Parliamentary Constituency, which is being represented by me, was earlier represented by former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, and K Chandrashekhar Rao.)

The constituency I am representing is Medak which was earlier represented by Shrimati Indira Gandhi and Telangana Chief Minister, KCR also. But, unfortunately, when Shrimati Indira Gandhi was contesting in the year 1980, she promised a railway line from Tellapur, Patancheruvu, Sangareddy, Jogipet, Medak, Ramayampet, Siddipet to Karimnagar. A railway line of 225 kms was promised in the year 1980. Since then, for the past 44 years, just nine kms of railway line has been laid from Tellapur to Patancheruvu. After running the train for a period of three months, रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि आमदनी नहीं हो रही है, ऐसा बोलकर वह रेल भी रोक दी गई। पतानचेरू में जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन हुआ था, वह भी तोड़ दिया और रेल बंद हो गई।

It is a long-pending demand. When Telangana was formed, it had only 10 districts. Now, there are 33 districts in the Telangana State. Only one district headquarters, that is, Sangareddy does not have the railway station, rest of the 32 districts are connected by a railway line. One of the Assembly constituencies is Patancheruvu, which falls in the Parliamentary constituency, is among Asia's biggest industrial areas. It is my sincere appeal, through you, to the hon. Minister. As there is a demand and a survey has been completed in the year 1980 itself, I urge the hon. Minister to kindly look into this matter of 225 kms of railway line from Tellapur, Patancheruvu, Sangareddy, Jogipet, Medak, Siddipet and Karimnagar. This is one of the largest industrial areas.

* () Original in Telugu

So, there is a huge demand from the people for this new railway station which will connect almost seven districts of Telangana.

(1240/CS/SRG)

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): Madam, thank you very much for giving me the opportunity to speak on an important issue of my constituency in this august House. I would also like to thank the people of my constituency.

The people of my constituency, Jhargram, popularly known as Jangalmahal in West Bengal, has a long-pending demand for laying down of new railway line between Jhargram and Baripada. During the past Lok Sabha election campaigns, leaders of a national political Party gave many assurances to the people of Jangalmahal/Jhargram, and one such assurance was the Jhargram-Gopiballavur-Baripada railway link. But till today, no step has been taken to fulfil their assurance. In fact, there is no direct railway connectivity between Jhargram and Baripada, and between Jhargram and Bandwan of Purulia district in my constituency.

Therefore, I would urge upon the Central Government and the hon. Minister of Railways to take up this railway project and construct the new railway line between Bandwan and Baripada via Jhilimili-Jhargram-Gopiballavpur in my constituency.

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) : महोदया, देश के इस सर्वोच्च सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपनी और महासमुन्द लोक सभा की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

महोदया, मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में रबी और खरीफ दोनों के सीजन में धान की खेती का रकबा कई गुना बढ़ गया है, जिससे दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों के उत्पादन की जगह सब लोग धान की खेती करने लगे हैं। समस्या यह है कि धान की कटाई के बाद जो खेत में धान की पराली बच जाती है, उसको जलाने की विकराल समस्या देश के सामने खड़ी हुई है। इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और भूमि की उर्वरता लगातार नष्ट हो रही है। इससे दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है।

महोदया, आज पूरे विश्व को जलवायु परिवर्तन के चलते भयावह स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। पराली प्रबंधन के लिए फसल कटाई के समय कम्बाइन हारवेस्टर के पीछे लगने वाले सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम मशीन को प्रत्येक कम्बाइन हारवेस्टर के साथ अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय, बैल आदि के लिए आज चारे की जो आवश्यकता पड़ रही है, वह इससे दूर होगी। अगर उस मशीन के मूल्य में

विशेष छूट प्रदान की जाए ताकि उस पराली को हम गौशाला में दें और उसे बिना जलाये, पहले उस पराली को इकट्ठा कर लें और तब उस जमीन का खेती के लिए उपयोग करें। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत जल्दी अक्टूबर-नवम्बर में धान की फसल की फिर से कटाई होगी, जिससे फिर यह समस्या हमारे सामने आएगी। मैं इस तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदया, नमस्कार। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे आज बोलने का वक्त दिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती लोक सभा में पूना का बहुत शहरी एरिया आता है।

*A large part of Pune city falls under my Constituency, Baramati. Yesterday, there was a heavy downpour in that area. Heavy rains lashed Pune, Satara and Kolhapur Districts. So, the administration opened the floodgates of Khadakvasla Dam. The dam water should have been released gradually in small volumes but the floodgates were opened suddenly without sounding any alert. This is not carelessness but absolute negligence. If the Government knew about the yellow and orange alert, they should have shared the information with the locals there. In and around Sinhgad Road, Pimpri-Chinchwad and in Pune area, houses, schools, and offices drowned and people had to suffer a lot.

Hence, I would like to request the Union Government that, through NDRF, necessary help should be provided. The Maharashtra Government should declare a relief package for the affected people. The people residing in Pune and Kolhapur area should be given immediate help, and relief work should be carried out by the Administration and that is my only request to you.

---

* Original in Marathi

(1245/IND/RCP)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : सभापति जी, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं, जिसे गेटवे ऑफ एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर में सम्मिलित होने के बाद भी हम लोग विभिन्न विसंगतियों से जूझते हैं। अभी सरकार ने पिछले दिनों रेपिड रेल चलाई, जो मेरठ के आखिर तक रुक गई। यह रेल मुजफ्फरनगर चलानी चाहिए थी, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा उद्योग-धंधे हैं। यहां के लोग उद्योग-धंधों का दंश तो झेल रहे हैं, क्योंकि इनसे पानी बहुत दूषित होता है। यहां कैंसर की बीमारी है, आंख की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। यदि रेपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक कर दिया जाए तो लोगों को आवागमन की सुविधा होगी तथा व्यापार भी फले फूलेगा।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस रेपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक कर दिया जाए और उन इंडस्ट्रीज पर जिनके धुएं से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं और जो ग्राउंड वॉटर प्रदूषित हुआ है जिसकी वजह से लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, उन पर भी रोकथाम लगाने का काम किया जाए।

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : सभापति जी, मैं आपका ध्यान देश की बहुत गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है और उसमें लिखा है कि 'अब सहन नहीं होता' और ड्रग्स तस्करों के नाम लिए हैं। जो स्वयं ड्रग्स लेते हैं, उन्होंने विडियो बनाकर पंजाब के ड्रग्स तस्करों के नाम लिए। यह लुधियाना की खबर है। उन्होंने कहा कि अब सहन नहीं होता है और हम दलदल में बहुत बुरे तरीके से धंस चुके हैं। अगली इंडियन एक्सप्रेस की खबर है – "Vaping trend in classrooms of Ludhiana rings alarm bells; schools increase vigilance after recovery of devices from children." मेरे कहने का मतलब है कि पंजाब के अंदर, वैसे तो यह देश की समस्या है लेकिन पंजाब के अंदर ड्रग्स की इतनी ज्यादा समस्या है कि गांवों के गांव खाली हो गए हैं। कुछ नौजवान साथी देश छोड़ कर चले गए हैं। जो बच गए हैं वे ड्रग्स में लग गए हैं। इसकी वजह मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब की सीमा के साथ 425 किलोमीटर बार्डर लगता है। जब लोग प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि चार गुना ड्रग्स हो गया है, तो प्रदेश वाले कहते हैं कि बीएसएफ का एरिया बढ़ गया है। 13/10/2021 तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 15 किलोमीटर तक आगे जा सकती थीं लेकिन अब 13/10/2021 के बाद से वह एरिया 50 किलोमीटर एरिया बढ़ा दिया है। बीएसएफ घर-घर में चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रग्स की समस्या हल नहीं हुई।

महोदया, मैं संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ड्रग्स के विषय पर दो-चार दिन की बहस होनी चाहिए। यह बहुत चिंता का विषय है और यह भी देखना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): Respected Madam, thank you for giving me an opportunity. I represent one of the most backward Parliamentary constituencies, that is, Kandhamal Parliamentary constituency in Odisha. Most of the area in my constituency is hilly terrain inhabited by tribals and backward population. In spite of the best effort of the Modi Government, some areas are not covered with internet and mobile services. I thank the Modi Government for completing 300 mobile towers in the last two years. Another 600 mobile towers are required in my constituency to cover the areas. Kandhamal district comes under Aspirational Districts. That is why, I would request the hon. Minister of Communications, through you, to provide adequate telecom services in my area. Thank you.

(1250/RV/PS)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदया, केन्द्रीय पुलिस बल, सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें बी.एस.एफ.. सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी., एन.एस.जी., एस.एस.बी., असम राइफल्स शामिल हैं। हमारे इन पुलिस बलों के ऊपर न सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ-ईस्ट तक, नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं पर, बन्दरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यहां तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इनके हाथों में दी गयी है। आपके माध्यम से मैं इनके हितों से जुड़ी हुई दो-तीन बातें रखना चाहता हूं।

महोदया, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब देश के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गयी तो उस समय यह कहा गया - 'New Pension Scheme for all employees except for the Armed Forces in the first stage'. उसमें आर्मी, नेवी, और एयर फोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन, उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह क्लैरिफाई किया कि ये जो सी.ए.पी.एफ. हैं, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। ये भी आर्म्ड फोर्सेज़ की परिभाषा में आने चाहिए। इसलिए जब इन्हें देश की सुरक्षा दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी हमारी सरकार का कार्य है।

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि इनके लिए 100 दिनों का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स न हों, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इन फोर्सेज़ को केवल 60 दिनों का अवकाश दिया जा रहा है। इनके लिए 100 दिनों का अवकाश सुनिश्चित किया जाए।

हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज़ पर अर्द्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ-साथ हर राज्य में अर्द्धसैनिक बोर्ड का गठन हो, ताकि इन कर्मियों के हितों की सुरक्षा की जाए।

श्री राधेश्याम राठिया (रायगढ़) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में प्रथम बार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे। जब वे रेल मंत्री थे, तब रायगढ़ जिले में कोयला, चूना-पत्थर, डोलोमाइट एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिज-सम्पदा की बहुतायत को देखते हुए उन्होंने रायगढ़ रेलवे स्टेशन के विस्तार की योजना के उद्देश्य से वर्ष 1998 में वहां रेल टर्मिनल की भूमि का शिलान्यास किया था, पर उसके बाद टर्मिनल निर्माण का कार्य ठंडे बस्ते में चला गया।

रायगढ़ रेलवे स्टेशन द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 में अर्जित आय में यात्री आरक्षण टिकट से करीब 19 करोड़ रुपये, अनारक्षित टिकट से लगभग 28 करोड़ रुपये, माल भाड़ा से करीब 46 करोड़ रुपये, पार्सल से लगभग 5 करोड़ रुपये शामिल हैं। बिलासपुर ज़ोन में यह कोरबा के साथ सबसे अधिक आय देने वाला शामिल है। आज वहां एनटीपीसी जैसे पावर सेक्टर द्वारा 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और वहां सैकड़ों फैक्ट्रियां होने के कारण पूरे भारत से वहां लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इससे वहां लगातार यात्री टिकट में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बिलासपुर ज़ोन द्वारा इस तरफ किसी प्रकार का ध्यान न देने के कारण वहां के लोग उपेक्षित और ठगा महसूस करते हैं। महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से रायगढ़ जिले के वासियों के लिए वहां एक टर्मिनल बनाने का अनुरोध करता हूं।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चित्तौड़गढ़ के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में सड़क और परिवहन मंत्रालय की कई सौगातें दी हैं। आज़ादी के बाद के 60 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम पिछले दस वर्षों में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में हुआ है। इसमें केन्द्रीय सड़क निधि की सड़कें भी हैं और 4-लेन से 6-लेन की सड़कें भी हैं।

महोदया, अभी किशनगढ़ से अहमदाबाद तक एक 6-लेन सड़क बनी। उसमें भीलवाड़ा से उदयपुर के बीच लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर तक का एक गंगरार कस्बा

है। वहां फ्लाईओवर बनने पर दोनों तरफ के बाज़ार एक तरह से खत्म-से हो जाएंगे। आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि अगर वहां एलिवेटेड फ्लाईओवर बनता है तो वहां के बाज़ार भी सुरक्षित रह पाएंगे और उस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं भी मिल पाएंगी।

वहां इसके बीच एयरपोर्ट के नज़दीक एक वल्लभनगर कंस्टीट्युन्सी है, जो विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय है। वहां जाने के लिए एक अंडरपास की आवश्यकता है।

महोदया, वहां अगर ऐसे दो-तीन काम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से 4-लेन से 6-लेन सड़क होने का फायदा उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। आपके माध्यम से मेरी सरकार से यही मांग है।

(1255/SMN/GG)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you Madam for giving me an opportunity to raise the most important issue relating to the US ban on the import of sea shrimp from India.

Since 2019, the US has not imported shrimp from India, accusing Indian fishermen of not attaching Turtle Excluder Devices (TED) to their nets. As a result, our fishermen are suffering greatly. Since then, there has been only a meagre increase in the export of sea shrimp from India. The US claims that sea turtles are getting caught in the nets, but this argument is not entirely true. Traditional fishermen are the ones who traditionally protect sea turtles. Moreover, in 2019, the CMFRI reported that the presence of sea turtles on the West Coast is very low, with fewer than 10 sea turtle eggs found on these beaches in a year.

The fishermen argue that various Governments and the Seafood Export Development Authority, who were supposed to act on the said report, have completely failed to address this reality. No sea turtles are caught during trawling in any Indian State. In Odisha, where the sea turtles are largely concentrated, trawling has been banned during their breeding season. In Kerala also, there are no reports of sea turtles being caught in nets at any stage of fish production.

Due to the US ban initiated in 2019, India is estimated to lose Rs. 2,500 crore in seafood exports every year. Taking advantage of this situation, the European Union, China, Japan, and other countries are

bargaining and reducing the price of shrimp. Consequently, the prices of shrimp varieties like kara, naran, karikadi, poovalan, and kazhanthan in the domestic market are falling, pushing our fishermen into a severe crisis.

Considering the seriousness of this matter, I urge upon the Government to intervene in this matter urgently and find out a solution to this issue.

Thank you, Madam.

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं शिवहर लोक सभा क्षेत्र से आती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के परनहिया प्रखण्ड के अदौरी घाट से खोरीपाकर, पूर्वी चम्पारण जिले को जोड़ने वाली बागमती नदी पर पुल निर्माण की मांग दशकों से लम्बित है। पुल का निर्माण हो जाने से दोनों जिलों की दूरी काफी कम हो जायेगी और करीब 4-5 लाख की आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। साथ ही, सीतामढ़ी जिला पूर्वी चम्पारण से जुड़ जाएगा और उसकी भी दूरी कम हो जाएगी। जब वहां पर बारिश ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ की समस्या हो जाती है, कटान हो जाता है। इसलिए वहां पर कम से कम डैम बनाया जाए। इस पुल के बन जाने से सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण और सीतामढ़ी का जानकी धाम और अयोध्या का सम्पर्क सीधा जुड़ जायेगा।

अतः मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह करती हूँ कि केन्द्र सरकार इस पुल के निर्माण के लिये जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करे।

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : सभापति महोदया, मैं भरतपुर क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन और सर्व समाज को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहां, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में चुन कर भेजा है।

महोदया, मैं भरतपुर संसदीय क्षेत्र से आती हूं। यहां शहर से लेकर गांव तक पानी की बड़ी समस्या है। मेरे क्षेत्र में पीने योग्य पानी की कमी है क्योंकि ज्यादातर पानी में फ्लोराइड और खारापन है, जिसके पीने से गंभीर बिमारियों से लोग जूझ रहे हैं।

महोदय, मेरे भरतपुर में ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। परिवार का पेट भरने के लिए खेती के अलावा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। पानी की कमी के कारण किसान भुखमरी और आत्महत्या करने पर मजबूर है।

(1300/MY/SM)

महोदया, मैं जमीन से जुड़ी हुई हूं और एक किसान परिवार की बेटी हूं, इसलिए किसानों का दर्द महसूस करती हूं। सरकार पानी को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है, परंतु आज धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। मुझे इस बात का दुख है कि पूरा देश राजस्थान में पानी की किल्लत को बखूबी जानता है, फिर भी बजट में राजस्थान की अनदेखी की गई है। सरकार ने राजस्थान की जनता को पानी से संबंधित या कोई अन्य राहत पैकेज नहीं दिया है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : महोदया, अंत में, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान और मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में उक्त गंभीर और विकट समस्या पर ध्यान देकर यहां की जनता को कृतार्थ करें। धन्यवाद।

*SHRI MURASOLI S. (THANJAVUR): Hon.Speaker Sir, Vanakkam. I thank you for giving me an opportunity to speak in this House of Parliament. I have been elected from my delta district, Thanjavur of Tamil Nadu which belonged to the Chola kingdom. You are aware that Chola kingdom is called the rice bowl with so much of paddy production. Water is released from Mettur dam for the farmers of my delta district. Last year since there was no water flow towards Mettur dam, farmers of my delta district had to suffer a lot. Now, this year, all the dams constructed in Karnataka are full and overflowing. Hence the excess water from these dams are only released to Mettur dam. I urge upon the Union Government that unlike the present situation it should ensure through the Cauvery River water Management Authority, that sufficient and prescribed volume of Cauvery water should be released to Mettur dam by Karnataka. Sir, I place this request through you to the Union government on behalf of the people of my delta district of Thanjavur. Thank you.

माननीय सभापति: शून्य काल समाप्त।

---

*Original in Tamil

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Sanjna Jatav	Shri Navaskani K.
Shrimati Lovely Anand	Shri Navaskani K.
Shri k. C. Venugopal	Shri Navaskani K.
Shri Chandra Prakash Joshi	Shri Navaskani K.
Shri Murasoli S.	Shri Navaskani K.
Shri Deepender Singh Hooda	Shri Rahul Kaswan
Dr. Gumma Thanuja Rani	Shri Navaskani K.
Shri Suresh Kumar Kashyap	Shri Navaskani K.
Shri Vijay Kumar Dubey	Shri Navaskani K.
Shri Madhavaneni Raghunandan Rao	Shri Navaskani K.
Shri Kalipada Saren Kherwal	Shri Navaskani K.
Shrimati Roopkumari Choudhary	Shri Navaskani K.
Shrimati Supriya Sule	Shri Navaskani K.
Dr. Shashi Tharoor	Shri Navaskani K.
Shri Isha Khan Choudhury	Shri Navaskani K.
Shri Konda Vishweshwar Reddy	Shri Navaskani K.
Shri Biplab Kumar Deb	Shri Navaskani K.
Shri Mukesh Rajput	Shri Navaskani K.
Shri Pushpendra Saroj	Shri Navaskani K.
Sushri Iqra Choudhary	Shri Navaskani K.
Shri B. Manickam Tagore	Shri Navaskani K.
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	Shri Umeshbhai Babubhai Patel
Shri Deepender Singh Hooda	Shri Navaskani K.
Shri Amrinder Singh Raja Warring	Shri Navaskani K.
Shri Harendra Singh Malik	Shri Navaskani K.

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1302 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेजें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (व्यवधान)

Re: Need to confer Bharat Ratna upon late Shri Kanshi Ram

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : श्री कांशी राम, जिन्हें बहुजन नायक और मान्यवर के नाम से भी जाना जाना है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूहों सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने सादगी जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया । यह किसी से छिपा नहीं है कि मान्यवर श्री कांशी राम जी ने दलित राजनीति में एक विशिष्ट स्थान बनाया। लेकिन, वह राजनीति से ज्यादा देश के दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे ।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मान्यवर कांशी राम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही करें। (इति)

Re: Need to construct a weir at Badalpur in Anand Parliamentary Constituency

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : मेरे लोकसभा मत क्षेत्र आनंद मे खंभात और बोरसद के कई विस्तार मे किसानो की जमीन समुद्र का पानी महिसागर नदी के रास्ते वापिस आने के कारण खारी हो रही है। इन विस्तारों में नदी के किनारे के गाँव काफी प्रभावित हैं। ऐसे ही समुद्र का पानी आना जारी रहा तो आने वाले 20 वर्षों के बाद ये जमीने बंजर हो सकती है एवं किसानों को तबाह कर सकती हैं। महिसागर नदी में बदलपुर गाँव में वियर (जल अवरोधक) बनाने से कई किसानो की जमीन को खारा होने से बचाया जा सकता है। महोदय, सदन के माध्यम से मेरा जलशक्ति मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय अनुरोध है कि बदलपुर में वियर (जल अवरोधक) बनाने हेतु अपने स्तर पर उचित कदम उठाएँ। (इति)

Re: Construction of rail over bridge at Chandwa

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : झारखंड राज्य का चतरा संसदीय क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है और यह जिला भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। विगत एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों और गृह मंत्रालय के विशेष कार्यक्रमों के तहत इन आकांक्षी जिलों में विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हुआ है सड़कों के निर्माण और सघनता ने सड़कों के संपर्कों को सुधारकर विकास दर को गति दी है। NH-22 चंदवा-चतरा-लातेहार मुख्य मार्ग है, जो चोपन-गोमो रेल लाइन को पार करता है। चंदवा में रेल ओवर ब्रिज की अनुपस्थिति के कारण क्षेत्रवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है और रेल ओवर ब्रिज की कमी ने सुरक्षा और आवागमन में अतिरिक्त समस्याएं उत्पन्न की हैं वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग रही है कि चंदवा में गोमो-चोपन रेल लाइन पर एक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण हो। इस महत्वपूर्ण मांग को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप माननीय रेल मंत्री जी से चंदवा में रेल ओवर ब्रिज बनाने की पहल करें, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सके और विकास को और प्रोत्साहन मिले।

(इति)

Re: Need to bring Ayurved College in Paikmal, Bargarh under Central Government

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : मैं माननीय आयुष मंत्री का ध्यान ओडिशा के बरगढ़ के पदमपुर उप-विभाग के पाइकमल में आयुर्वेदिक कॉलेज को केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन लिए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गंधमर्दन पर्वत श्रृंखला ओडिशा के बलांगीर और बरगढ़ जिले के बीच स्थित एक पहाड़ी है। यह पहाड़ी औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक बॉक्साइट रिजर्व है, जिसे राज्यसरकार द्वारा एक निजी उद्यम के माध्यम से अन्वेषण हेतु योजना बनाई गई है। भगवान हनुमान यहाँ श्रीलंका के पिदुरु पर्वत में निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, हनुमान ने लक्ष्मण के जीवन को बचाने हेतु हिमालय से इस पहाड़ी को अपने कंधों पर उठाया था। यहाँ भगवान नृसिंहनाथ की पूजा की जाती है और यह ओडिशा के तीर्थ और पवित्र स्थानों में से एक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार, यहाँ 2200 से अधिक औषधीय पौधे हैं। बरगढ़ के पदमपुर उप-मंडल के पाइकमाल में एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो शोध कार्य आदि कर रहा है। इस कॉलेज को आगे के विकास और शोध कार्यों हेतु केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन लिया जाना चाहिए! मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कॉलेज और इसके छात्रों के लाभ हेतु इस कॉलेज को तुरंत अपने अधीन लेने पर विचार करें।

(इति)

Re: Need to declare Teesta flood as a National Disaster

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Over 500 families living along Teesta river in Darjeeling and Kalimpong Districts have been impacted due to the floods in river Teesta People have lost their homes, agricultural land, livelihoods, and even their lives. Major portions of NH – 10, which is the only highway connecting our border region of Kalimpong, Sikkim and Darjeeling is damaged in many places. Despite the scale of the disaster, neither the West Bengal Government has not taken any steps to assist the people, nor have they been able to fix NH-10, which is under WB PWD NH Division.

Sir, we are also part of India; we also pay taxes. Revenue from Teesta's hydro-dams alone exceeds Rs 750 crores annually, totaling over Rs 7500 crores in the past decade. WB Government is the sole beneficiary of this revenue collected. Yet, they have not taken any steps to rebuild or resettle the people. I request the Central Government to declare Teesta Floods as National Disaster, West Bengal Government to ensure adequate compensation, and take steps for their rehabilitation; and NH-10 be handed over to BRO/NHAI or NHIDCL, so that connectivity to this strategically important road is restored at the earliest.

(ends)

Re: Completion of various developmental projects in Deoghar

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar is an important religious hub and is home to one of the twelve Jyotirlingas and a Shaktipeeth with upwards of fifty million people visiting the pious city annually. I urge to chalk out a comprehensive programme in which previously sanctioned projects shall be reviewed and new projects be tabled for further development in the backward region.

1 Q-Complex, which received a grant of Rs. Twenty-five crores from the Government of India in the year 2012 is lying unfinished.

2 The Ministry of tourism has included Deoghar city in the Prasad Yojana. At the time of its inclusion, I had raised an issue concerning the narrow streets of the city leading to the temple should be widened.

3 The Prime Minister in the year 2015 had announced a package for the development of religious sites in the region, especially the Sultanganj to Deoghar corridor for the betterment of the facilities in the Kanwar Yatra and the overall holistic development of religious sites in the area.

4 The Deoghar, Santhal Pargana, and Jharkhand region is the hub of numerous religions, including Jainism and Hinduism. A comprehensive plan should be chalked out for the development of a circuit which connects the major religious hubs of the pious region. This circuit will impact India's reputation globally. Parasnath, Deoghar, Basukinath, Maluti, Tarapith, Vikramshila, Bateshwarsthan, Mandar, Champapuri, sultanganj, Karangari in Munger are all pivotal religious hubs with hundreds of millions of devotees flocking to these temples annually to pay their respects.

5 The Food Craft Institute is an incomplete project in Deoghar.

Thus, I request to complete the projects for the development of the backward region. (ends)

Re: Setting up of an IIT in Satna, MP

श्री गणेश सिंह (सतना) : मेरा लोकसभा क्षेत्र सतना एक औद्योगिक जिला है, मेरे क्षेत्र से लगे विन्ध्य क्षेत्र, महाकौषल एवं बुन्देलखंड क्षेत्र में खनिज एवं मिनरल का प्रचुर भंडार है। भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0) मध्यप्रदेश के मात्र इन्दौर जिले में है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में है तथा हमारे क्षेत्र से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे क्षेत्र के युवाओं का कौशल विकास रूका हुआ है। जो आई0आई0टी0 के लिये मानदण्ड निर्धारित हैं, वह हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से उसके अनुरूप है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2 आई0आई0टी0 है, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 है। मार्च 2020 तक देश में कुल 23 आई0आई0टी0 हैं। मेरे क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की मांग है। आई0आई0टी0 आने से सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे क्षेत्र में बड़े सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। मेरी केन्द्र सरकार से पुरजोर मांग है कि सतना में एक आई0आई0टी0 महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need for stringent regulations for labelling and sale of processed food products

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Today, I highlight a critical health concern regarding the surge in processed food consumption. Concerning data shows that top urban households spend over ₹500 monthly per person on such foods. Lab tests reveal that chips have 5.2 times more fat and namkeen 6.1 times more salt than recommended limits. This trend may lead to 351.1million cases of abdominal obesity, 315.5 millions of hypertension, and 254.2 millions of generalised obesity in adults as projected by the ICMR-INDIAB National Study. While I commend FSSAI's recent limits on trans-fat in various food items, I humbly request the Hon'ble Minister of Health and Family Welfare to implement front-of-pack nutrition labelling, regulating marketing of ultra-processed foods, and promoting access to healthier alternatives. This aligns with Prime Minister's vision for a healthy India. I urge comprehensive action to safeguard our citizens' health.

(ends)

Re: Relief and rehabilitation of flood affected people by Ganga, Phulhar and Koshi Rivers

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मैं पूरे सम्मान के साथ यह तथ्य सामने लाना चाहता हूं कि भारी बारिश और नदी की गहराई में कमी के कारण गंगा, फुलहर और कोशी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और रतुआ ब्लॉक के अंतर्गत खासमोहोल, नसीरुद्दीन टोला, भाषाराम टोला, कानतु टोला, महानंदा टोला और भिलाई मारी पंचायतों के जैसे गांवों के नदी किनारे के आवासों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिसमें 300 से अधिक परिवार गंगा, फुलहर और कोशी कटाव से प्रभावित हुए हैं। जबकि हरिश्चंद्रपुर-II ब्लॉक के उत्तर और दखिन भाकुरिया, रशीद पुर जैसे गांव जिनमें लगभग 135 से अधिक परिवार फुलहर से प्रभावित हुए हैं। उपरोक्त सभी ग्रामीण दुर्भाग्यवश तीनों नदियों के कहर के कारण अपने घरों से विस्थापित होकर सड़कों पर आ गए हैं। इन सभी लोगों को यथाशीघ्र उचित राहत एवं मुआवजा देकर पुनर्वासित किया जाना चाहिए।

ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गंगा, फुलहर एवं कोशी के तटवर्ती बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से माननीय जल शक्ति मंत्री से एवं पश्चिम बंगाल सरकार से बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को पुनर्वास की व्यवस्था तुरंत की जाए।

(इति)

Re: Infrastructure development for setting up of a Mega Food Park in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज बिहार कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। कृषि ही मुख्य रूप से मेरे क्षेत्र की जनता का जीवन-यापन एव अर्थोपार्जन का मुख्य साधन है। रवि-खरीफ सहित वार्षिक फसलों के सभी चक्रों के अन्न, सब्जी एवं फलों का उत्पादन मेरे ससदीय क्षेत्र के बहुतायत किसानों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारे क्षेत्र के किसान बंधुओं के लिए उत्पादित सभी स्तर के उत्पादन को संरक्षित करने, आधुनिक भण्डारण की व्यवस्था करने, खेत-खलिहान से लेकर अच्छे एवं लाभकारी विपन्नन की व्यवस्था प्रदान करने की जरूरत है। इसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के विभिन्न योजनाओ के तहत मेगा फूड पार्क एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन परिरक्षण अवसंरचना स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है, जिससे कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानो को जनहित में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर मिल सके तथा उनके आय को दोगुनी किया जा सके।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से खादय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत अपने मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं के तहत मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन परिरक्षण अवसरचना स्थापित कराया जाये।

(इति)

Re: Need for proper planning to check floods in North Eastern States

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : प्रत्येक वर्ष उत्तर पूर्वी भारत मे बाढ़ और भूस्खलन से लाखों लोग प्रभावित होते है और उन्हें जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है, हजारों हैक्टेयर फसल बर्बाद होती है, बहुत से लोगों व पशुओं को अपनी जान गवानी पड़ती है। इस साल भी बाढ़, भूस्खलन और तूफान से दरांग, कामरूप व कोकरा झार समेत 26 जिलों के 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए है। 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा की फसल भूमि जलमग्न हो गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने हाल के वर्षों में सबसे खराब बाढ़ देखी है, जिसके परिणामस्वरूप डूबने या बचाव कार्यों के दौरान 159 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। इस भीषण बाढ़ के कारण यहाँ के बुनियादी ढांचे को भी बहुत नुकसान हुआ है, इस नुकसान मे 94 सड़कें, 03 पुल, 26 घर और छह तटबंध शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश और केंद्र सरकार अपने स्तर पर बचाव कार्य कर रही है और लोगों तक मदद भी पहुंचा रही है, लेकिन मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारत के उत्तर-पूर्वी भाग को प्रत्येक वर्ष की भीषण बाढ़ से बचाने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार करे और बड़े पैमाने पर ठोस कदम उठाए जाएँ। (इति)

Re: Need to increase wages of labourers under MGNREGA and enhance allowances of Gram Pradhans

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन वर्ष 2005-06 से मनरेगा कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। यह सबसे बड़े रोजगार गारंटीकृत कार्यक्रमों में से एक है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को कम-से कम 100 दिनों का गारंटीकृत काम प्रदान किया जाता है। जिसके व्यस्क सदस्य स्वेच्छा से स्थानीय क्षेत्र में कार्य करते है। अधिनियम पारित हुए लगभग 19 वर्ष बीत चुके है एवं वर्तमान में औसत मजदूरी रू 289 प्रति दिवस है तथा महगांई भी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में रू 289 मजदूरी में रोजमर्रा की चीजों को वहन करना कठिन है। ग्राम प्रधानों की निधि भी आवश्यकतानुसार कम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मनेरगा मजदूरी व ग्राम प्रधानों का भत्ता भी बढ़ाया जाए। (इति)

Re: Need to provide stoppage of trains at Angamaly railway station in Kerala

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Angamaly is the nearest railway station to Cochin International Airport, which carries over 1 crore passengers and 36.95 lakh international passengers, which is higher than either Bengaluru or Hyderabad. Angamaly also serves as a major bus hub for people traveling to North Kerala, and will soon become a railway junction with the completion of the Sabari Railway project. Despite its importance, it has not received the attention it deserves. Out of the 190 trains that pass through Angamaly, only 48 trains stop there. This allocation is disproportionate to Angamaly which is among the top 100 revenue-generating stations in Southern Railway, especially when lesser revenue-generating stations are granted more stops. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Railways to urgently allot the stopping of more trains at Angamaly railway station. (ends)

Re: Approval of Coastal Zone Management Plan (CZMP) in Kerala

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): "The CRZ Notification 2019 dated 18.01.2019 aimed to provide coastal communities more room for development while protecting sensitive ecosystems. However, the implementation of the new notification has been considerably delayed. The State Government of Kerala after approval from the National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSM), Chennai, on 07.02.2024, had subsequently submitted to the Union Government, the prepared CZMP. Regrettably, the Union Government has not yet considered and notified this CZMP. Until the CZMP is finalized and notified, the stringent provisions of 2011 remain in effect, restricting development and causing difficulties for them. Additionally, the CRZ Notification 2019 mandates the preparation of Integrated Island Management Plans (IIMP) for each island within the CZMP, which has also not been prepared. It is also important to recognize that coastal people have played a significant role in the history of Keralites. Fishermen, often described as Kerala's own army, have received the honours and respect of society for their heroic efforts in saving lives during floods. Despite their invaluable contributions, both the Central and Kerala governments are showing great deception in addressing their critical issues. I urge upon the Ministry to expedite the approval of the CZMP for Kerala, including Ernakulam, without delay." (ends)

Re: Conduct of NEET Exam

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Even after several students' suicides, claims of impersonation, question paper leak scams, grace mark scams and merit scams, it is said that "No big malpractice took place", but they can't entirely deny their guilt and stand against their grace mark scam. Moreover, in the All India Quota for NEET PG, the OBC category faced total exclusion, resulting in the loss of 11027 seats from 2017 to 2021, despite OBCs constituting over 60% of the population. This exclusion underscores the competitive disadvantages inherent in the current NEET framework. From the beginning, Tamil Nadu advocated for a NEET ban and unanimously passed the "Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Act, 2021 (TN L. A. Bill No.43 of 2021)' bill in the assembly in response. Despite Tamil Nadu's robust health sector and commitment to social justice through comprehensive reservation policies, NEET imposition undermines these efforts and erodes state autonomy. This system has inadvertently fueled the rise of capitalist coaching classes, leading to student fatalities and diminished medical education quality. For the betterment of the national medical infrastructure, it's imperative to abolish NEET and till then grant Tamil Nadu an exemption, upholding the state's autonomy in accordance with the constitution.

(ends)

Re: Need to give priority to local people for employment in companies set up in Barmer Parliamentary Constituency

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर -जैसलमेर में कार्यरत सोलर, विंड,खनिज ,गैस ,तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों व रिफायनरी आदि क्षेत्र में स्थानीय लोगो को रोजगार में प्राथमिकता नही देने के कारण उत्पन्न समस्या के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रम एवम रोजगार मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए अवगत करवाना चाहता हुं कि मेरा संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है,यहां तेल,गैस, खनन व सोलर तथा विंड एनर्जी व रिफायनरी के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां स्थानीय लोगो को रोजगार में प्राथमिकता नही देती तथा जिसके कारण वहां के लोगो को मजबूरन रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है की जिन किसानों की जमीनों पर यह कंपनिया आबाद हुई उन किसानों के बेटो और बेटियों को रोजगार नही दिया जा रहा है। महोदय पर्यावरण अनापत्ति जब कोई कंपनी लेती है, तो उसमे भी जमीन अवापति से प्रभावित लोगो को रोजगार सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की बात होती है, लेकिन कोई भी कंपनी चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो या गैर तकनीकी क्षेत्र हो, स्थानीय लोगो को रोजगार नही देती है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है की ऐसी कंपनियों में स्थानीय लोगो को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाई जाए। (इति)

Re: Establishment of a medical college and multi-speciality hospital in Sivakasi

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Today, I present a transformative vision for our Virudhunagar constituency: the establishment of a state-of-the-art medical college and multispeciality hospital in Sivakasi. This initiative aims to enhance medical care and serve as a hub for education and research, ensuring high-quality healthcare and advanced medical training accessible in our district. Currently, our region faces significant healthcare access challenges, with advanced medical facilities located far away, causing financial and physical burdens. A multispecialty hospital will provide comprehensive local medical care, reducing the need for long-distance travel for specialized treatment. The proposed Medical College will offer diverse medical courses, nurturing a new generation of skilled healthcare professionals dedicated towards serving our community. This project will generate significant employment opportunities, stimulate the local economy, and foster research and innovation in medical science. The total estimated cost is approximately ₹1000 crore, allocated across various components of the project. To realize this vision, we need the united support of all stakeholders. I urge each member of this esteemed assembly to back this vital initiative. Establishing a Medical College and Multispecialty Hospital in Sivakasi is a promise for better health, advanced medical training, and a brighter future for our community. (ends)

Re: Provision of train stoppages in Etawah Parliamentary Constituency

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : इटावा लोकसभा क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान बंद की गई रेलगाडियों को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहल्दा रेलवे स्टेशन पर कई सुपरफास्ट ट्रेन / एक्स्प्रेस ट्रेनों का ठहराव था जो कि रोक दिया गया है। सरकार से अनुरोध है कि इस स्टेशन पर उन ट्रेनों का ठहराव पुनः' किया जाए। इसके अतिरिक्त इटावा स्टेशन पर (अजमेर एक्सप्रैस) 12987 और (जियारत एक्सप्रेस) 12395 का ठहराव कराया जाए तथा राजधानी और दूरंतो ट्रेन का ठहराव किया जाए ताकि जनता को आने जाने में सहूलियत मिल सके।

(इति)

Re: Establishment of an AIIMS in Sambhal or Moradabad

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में एक AIIMS (एम्स) की स्थापना के संबंध मे अपनी मांग रखना चाहता हूँ। मेरी लोक सभा क्षेत्र में अब तक किसी भी एम्स की स्थापना नही हुई है। जिला सम्भल और मुरादाबाद में कैंसर से हजारों लोग पीड़ित है। इसके अलावा क्षेत्र में कई गंभीर रोगो का भी प्रभाव है। जिसके कारण काफी लोगों की मौत हो चुकी है। इन गंभीर बीमारीयों का मुरादाबाद व संभल में कोई इलाज नहीं है।

गरीब व्यक्ति धन के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते और जान दे देते है। कृपया इस गंभीर विषय की ओर अपना ध्यान देकर एम्स की स्थापना संभल या मुरादाबाद मे कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Provision of basic Railway infrastructure in Medinipur Parliamentary Constituency

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): In my Parliamentary Constituency Medinipur (West Bengal) approximately 13 to 15 thousand households with a population comprising 70 to 80 thousands approximately reside on land owned by the railways for more than 50 years.

Their lives and livelihood are both dependent within this area which comprises 8 wards of Khargapur Municipality.

Unfortunately, each time the Municipality tries to provide basic infrastructure to the residents, they face absolute non cooperation from the Railways.

This issue has been pending for the longest time and the people of Khargapur who are living in these wards for more than few generations definitely deserve an immediate intervention and solution from your end.

(ends)

Re: Grant of funds under MGNREGA

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I write today with deep anguish and despair of millions of citizens who have been consistently denied their rightful wages under MGNREGA. This grave injustice stems from the Central Governments inexplicable decision to withheld funds since December, 2021. MGNREGA is not merely a scheme, it is a beacon of hope for the rural poor, ensuring their livelihood and dignity through guaranteed employment. Yet, despite its monumental importance, the centre has withheld Rs. 6913 Crore. The consequences of this fund stoppage over devastation of the rural economy are crumbling.

Accountability is essential, but punishing millions of innocent, hardworking people for alleged discrepancies is not only unjust but also cruel.

I issue a fervent appeal to the conscience of the Hon'ble Minister of Panchayati Raj and Rural Development and the Central Government to release the pending MGNREGA funds to West Bengal immediately. The essence of MGNREGA is to provide timely guaranteed employment and we must honour this sacred commitment. Kindly release the funds now and restore dignity and justice to the lives of our rural people.

(ends)

Re: Surge in Cancer Cases in Erode

SHRI K. E. PRAKASH (ERODE): I rise to bring to your attention the alarming surge in cancer cases in Erode and the surrounding region. One of the primary reasons for this increase is water contamination from untreated waste discharged by industrial units. Additionally, there are other environmental exposures contributing to this health crisis. As a result, Erode is now being regarded metaphorically as the "cancer capital" of the state. Despite plans to establish a Common Effluent Treatment Plant (CETP), the situation remains dire. The residents are suffering, and there is a critical need for a dedicated cancer research centre to address this public health crisis. It would be beneficial if this centre could specially focus on preventive care based on the unique environmental exposures of the region. I earnestly request the Ministry of Health & Family Welfare to prioritise this issue and take immediate steps to establish a cancer research centre in the region. The health and lives of countless citizens depend on it.

(ends)

Re: Grant of Special status to Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को देश का सर्वाधिक गरीब राज्य बताया गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय मानव विकास व जीवन स्तर के मानकों पर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। बिहार में प्राकृतिक संसाधनों व जलीय सीमा के अभाव तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व भी इसका एक कारण है. साथ ही बिहार बाढ व सुखाड़ से प्रभावित प्रदेश भी है। केन्द्र सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी अभी तक कोई पहल नहीं की है, जबकि उत्तर के 3 राज्य जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश एव नार्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहाँ औद्यागिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। इससे बिहार आर्थिक सब्सिडी और टैक्स देने में सक्षम होगा। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से उत्तर के 3 राज्य और नार्थ-ईस्ट में केन्द्र की पहल का जो परिणाम आया है वही परिणाम बिहार में भी विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्राप्त होगा।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि नार्थ ईस्ट राज्यों के तर्ज पर एवं 9 मार्च, 2024, गजट संख्या-पी-44015/1/2023-डीबीआर-2. नाथ-ईस्ट को औद्योगिकीकरण स्कीम 2024 के आधार पर बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। (इति)

Re: Development of various tourist sites in Ramanathanpuram Parliamentary Constituency

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Rameswaram Ramanathan Swami Temple is located in my constituency. Thousands of devotees from all over the country visit there every day. Similarly, Dhanushkodi, which is a historical landmark, is already visited by all who visit Rameswaram and if developed further Dhanushkodi itself might become a separate tourist attraction spot especially from overseas countries and without saying it will pave way for the revenue through tourists. There are also areas of outstanding coastal beauty covered in coastlines which are still lying unnoticed and underdeveloped and if the Ministry focuses on the same the entire stretch will stay unique due to its nature's beauty. I table below recommendation on basic amenities like modern parking facilities and improved basic facilities, marine sports activities etc. can be established to attract the interested tourists. Similarly, the beaches in areas such as Atiyaman Irumeni Emmanam Kondan and Prappanavalai Riverside under my constituency are beautiful beaches without rocks which is a nature’s gift on the northern coast. But quite unfortunately, these areas are still underdeveloped and unnoticed by the tourism industry resulting in lack of development. Therefore, I request special attention to these locations and allocate special funds for the development of various tourist sites. (ends)

Re: Four laning of National Highways connecting Machilipatnam Port in Andhra Pradesh

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): In my Parliamentary Constituency i.e., Machilipatnam, a new port is coming up. So, there is a need to have better road infrastructure for transportation of goods. For this purpose, there is an urgent need for 4-laning of National Highways connecting Machilipatnam Port to enhance trade and supply-chain efficiency. The port's benefits can only be fully realized with good connectivity and infrastructure. Hence, I request the Hon'ble Road Transport & Highways Minister regarding the following issues:

1. Pedana to Gudivada section of NH-216H proposed 2-lane may create traffic issues.
2. A portion of NH-216 from port connectivity road to NH-216H and NH-65 4-lane needed to prevent traffic congestion.
3. Link road from port connectivity to its junction at NH-216 is needed. Land has already been acquired.

These upgrades will ensure smooth movement of traffic for port, strengthen NHs, interconnectivity and contribute to economic growth.

I appreciate your consideration and look forward towards a positive response and swift action.

(ends)

सामान्य बजट – सामान्य चर्चा
और
जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट – सामान्य चर्चा
और
जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र – अनुदानों की मांगें - जारी

माननीय सभापति: माननीय श्री चरनजीत सिंह चन्नी जी।

1303 बजे

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) :

देह शिवा वर मोहि इहै, सुभ (शुभ) करमन ते कबहूं न टरौं।।
न डरौं अरि सों जब जाई लरौं निश्चय कर अपनी जीत करौं

माननीय चेयरमैन, मुझे लगता है कि जो सरकार वाले हैं, दस साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिनसियरिटी भी नहीं है। देश के बजट पर कितनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। जब से चर्चा शुरू हुई है, मैं देख रहा हूं कि न प्रधानमंत्री जी, न होम मिनिस्टर, न फाइनैंस मिनिस्टर, आप उस तरफ देखो।… (व्यवधान) उन खाली कुर्सियों को देखो।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, मंत्री जी बैठे हुए हैं।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : वे उनका इंतजार कर रही हैं कि हमारी फाइनैंस मिनिस्टर कहां है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, चिराग पासवान जी बैठे हुए हैं। आप लोग थोड़ा शांति बनाकर रखिए।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : कहां हैं इनके मेम्बर्स? कहां हैं प्राइम मिनिस्टर? कहां हैं होम मिनिस्टर? हमारी वित्त मंत्री जी कहां है?

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप बजट पर चर्चा कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : हमारी वित्त मंत्री जी कहां है, जिन्होंने बजट पेश किया? हमें उनको बताना है कि बजट में आपने क्या नहीं दिया और क्या दिया। क्या यह सिनसियरिटी है? देश पूछ रहा है। हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिनसियरिटी क्या है?

(1305/CP/RP)

सभापति महोदया, मैं जब जीतकर आया, तो सबसे पहले मैंने माननीय श्री अंबेडकर साहब की मूर्ति पर नमन करना चाहा। मैं वहां गया, तो वहां मूर्ति नहीं है। वहां से उठाकर कहीं पीछे कर दी गई। ये लोग समझ लें कि ये अंबेडकर साहब की मूर्ति पीछे कर सकते हैं, उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते हैं। ये उनकी सोच को मार नहीं सकते और जो संविधान उन्होंने दिया है, उसे बदल नहीं सकते हैं। लोगों ने इनको बता दिया है कि आप संविधान नहीं बदल सकते, इसीलिए इनको पूरी मेजोरिटी नहीं दी।

'ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न,
छोट-बड़ो सब सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न।'

महोदया, 23 तारीख को बजट पेश हुआ। मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं बजट में जा रहा हूं। पहली बार सदन में आया हूं, इसके लिए जालंधर के लोगों का धन्यवाद है, जिन्होंने मुझे यहां लाकर खड़ा किया, उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नये कपड़े डालकर आया कि आज बहुत कुछ देश में देखने को, बताने को मिलेगा। मैं और हमारे सारे एमपीज़ पंजाब में जाकर प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या-क्या मिला। मैं नए कपड़े में मेले जैसे यहां आया। यहां आकर 'खोदा पहाड़, निकला चूहा भी नहीं'। हमें कुछ नहीं मिला। हमारे साथ सौतेला सलूक किया गया। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। यह सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है। राजनीति वाला चश्मा लगाया हुआ है, राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। अपनी सरकार को बचाने की फिक्र है, कुर्सी को पकड़े हुए हैं। यह बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला है।

पंजाब में जो बाढ़ आई, इनको दिखी नहीं। गरीब लोग जो मनरेगा में काम करते हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 100 दिन के काम की गारंटी थी, ये 100 से 101 दिन या 200 दिन नहीं कर सके। ये उनकी दिहाड़ी बढ़ा नहीं सके। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया। जालंधर, पंजाब की इंडस्ट्री डूब रही है। जालंधर में लेदर इंडस्ट्री है, जालंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। ये डूब रही हैं। उनके लिए कुछ नहीं किया गया। हेल्थ के लिए वहां हॉस्पिटल नहीं दिया। जालंधर को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया हुआ है। वहां गंदा पानी आ रहा है, सड़कें खराब हैं और रेलवे अंडर ब्रिज की बात नहीं की। पंजाब में नशा इतना फैल गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखेंगे, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ। मैं यह भी मांग करता हूं।

'बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो इक क़तरा-ए-खूं न निकला।'

महोदया, 2024-25 के बजट में जो एस्टीमेट दिए गए हैं, उसमें 32 लाख करोड़ रुपये की आमदनी दिखाई गई है और 48 लाख करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है। आमदनी और खर्च मे 16 लाख करोड़ रुपये का घाटा है। जिस घर का 16 लाख करोड़ रुपये का एक साल में घाटा होगा, उसकी बर्बादी तय है। बीजेपी वाले यह तय कर रहे हैं। 14 लाख करोड़ रुपये इस साल कर्ज लेने की बात कही गई है। अगर ऐसे हर साल कर्ज लेंगे, तो देश कहां जाएगा? आज देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो रहे हैं।

(1310/NK/NKL)

ऐसे हालात पैदा करने के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। हर रोज इमर्जेंसी की बात करते हैं। लेकिन आज देश में अनडिक्लेयरड इमर्जेंसी है, उसका क्या? इमर्जेंसी यह भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक सिंगर था, उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। आज तक सिद्धू मूसेवाला के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वे दर-दर भटक रहे हैं, यह भी इमर्जेंसी है। इमर्जेंसी यह भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया और उसे एनएसए लगा कर जेल के अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच-वह अपनी कंस्टीट्यूएंसी की बात नहीं रख पा रहा है, यह भी इमर्जेंसी है। विपक्ष के व्यक्तियों पर केन्द्रीय एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनको जेल के अंदर रखा जाता है, यह भी इमर्जेंसी है। इमर्जेंसी यह भी है कि हजारों किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है, जब वह अपनी मांग रखते हैं। पंजाब क्या देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है। किसान यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, उनसे मिला नहीं जा रहा है, यह भी इमर्जेंसी है। इमर्जेंसी यह भी है, … (व्यवधान) फीलिंग ले लो, ... (*Expunged as ordered by the Chair*) का मूल्य मिला है, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमर्जेंसी यह भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले डेढ़ साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, इमर्जेंसी यह भी है। इमर्जेंसी यह भी है कि हाथरस में एक दलित लड़की का आधी रात जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमर्जेंसी यह भी है कि मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया, इमर्जेंसी यह भी है। इमर्जेंसी यह भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिला पहलवानों के प्रदर्शन को प्रोपगेंडा बताया गया, इमर्जेंसी यह भी है। इमर्जेंसी यह भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमर्जेंसी यह भी है। अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देशद्रोही बताया गया, इमर्जेंसी यह भी है। किस इमर्जेंसी की बात कर रहे हो। … (व्यवधान)

माननीय चेयरमैन जी, मैं पंजाब के एक गरीब परिवार से आता हूं। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी सारी पढ़ाई सरकार ने की। मैं आज यहां खड़ा हूं तो कांग्रेस सरकार की रिजर्वेशन पालिसी का नतीजा है और अम्बेडकर साहब का दिया हुआ संविधान है। स्कॉलरशिप मिलती

रही, कांग्रेस पार्टी ने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी, उससे पढ़कर मैंने पीएचडी की है, यह देन कांग्रेस पार्टी की है।

जब बीजेपी की सरकार वर्ष 2014 में आयी, सबसे पहले इन्होंने सबसे बुरा काम किया, स्कॉलरशिप में पहले केन्द्र का 90 परसेंट हिस्सा था, उसे 60-40 के रेशियो पर ले आए और सरकार ने दलितों के पेट पर लात मारी। आज फर्स्ट क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक के गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, उसे इस सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। ये दलितों के पेट पर लात मार रहे हैं। मॉनोरिटी के लिए भी फर्स्ट क्लास से आठवीं क्लास तक की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। जब यह सरकार वर्ष 2014 में बनी तो प्रधानमंत्री जी ने देश की इकोनॉमी देखने के लिए दो मापदंड रखे। एक रखा डॉलर की कीमत और दूसरा पेट्रोल और डीजल की कीमत। पिछले दस साल में डॉलर की कीमत 25 रुपये बढ़ गयी है।

(1315/SK/VR)

माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस सरकार के समय इसकी कीमत सिर्फ 13 रुपये बढ़ी थी और इस सरकार के समय में डबल बढ़ गई है। वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी बोले थे, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, जब डॉलर की कीमत ज्यादा होने से रुपये की कीमत गिर गई थी, उस समय इसके बारे में माननीय मोदी जी ने बोला था – "क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है। यह जवाब देना होगा। आपसे देश जवाब मांग रहा है। समझ नहीं आ रहा, प्रधान मंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी-कभी तो लगता है कि रुपये और सरकार के बीच कम्पीटिशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है?" … (व्यवधान) माननीय मोदी जी ने कहा था – "जिस देश का रुपया कमजोर होता है, उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधान मंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है? आज देश की इकोनामी डूब रही है। देश का रुपया कमजोर हो रहा है तो क्या प्रधान मंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है?" … (व्यवधान)

दूसरी बात पेट्रोल की कीमत की आती है। माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2014 में कहा – "पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मनमोहन सिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देश डूब रहा है।" पिछले दस सालों में पेट्रोल की कीमत 23 रुपये बढ़ गई है और डीजल की कीमत 35 रुपये बढ़ गई है, जबकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में क्रूड ऑयल की कीमत 20 डॉलर प्रति बैरल कम हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है या आपकी कंपनियों या आदमियों की आमदनी बढ़ रही है? क्या बढ़ा रहे हो? देश का पैसा किसे दे रहे हो? गरीब लूटा जा रहा है।

माननीय सभापति जी, जब कोई गाड़ी में पेट्रोल फुल कराने जाता है, 50 लीटर तेल डलवाता है तो 2000 रुपये सरकार को चले जाते हैं। चार रुपये प्रति किलोमीटर देश का हर व्यक्ति सरकार को चलने के लिए देता है, इसका मतलब है कि एक किलोमीटर चलो तो चार रुपये सरकार को गए जबकि सरकार 14 लाख करोड़ रुपये के घाटे पर बैठी है और फिर ये कहते हैं कि बजट में बहुत कुछ मिला है।

सभापति जी, मैं एक एयरपोर्ट पर गया। वहां एक आदमी आया, उसने मुझे गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया और कहा – अभिनंदन है आपका। मैंने कहा – भैया, आप कौन हो और मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे हो? वह बोला - हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं। मैंने कहा – भैया, आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? वह बोला – अब यह एयरपोर्ट हमारा है, अब हम इसके मालिक हैं, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। मैंने कहा – यार, चलो ठीक है आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में गया और वहां फिर मुझे बुके मिला। मैंने पूछा तो उसने कहा – आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे हैं। मैंने कहा – यह इंडियन एयरलाइंस का जहाज है, आप क्या कर रहे हो? आप कौन हो? वह बोला – "यह जहाज अब हमारी कंपनी का है, मोदी जी ने हमें बेच दिया है।" मैं पूछना चाहता हूं कि क्या-क्या बेचोगे? देश को कितना बेचोगे? … (व्यवधान) मैं सात एयरपोर्ट्स पर गया। लखनऊ, अहमदाबाद, बैंगलुरू, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम और मुम्बई, ये सात के सात एयरपोर्ट्स अडानी जी के हैं। … (व्यवधान) 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं। … (व्यवधान) पुत्र की शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं और हजारों-करोड़ रुपये शादी पर लगे हैं। … (व्यवधान) मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई थी। … (व्यवधान)

(1320/MK/SAN)

आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या-क्या पका था? दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला था, उसको कितने पैसे दिए गए? दो साल से पुलिस मुझसे पूछ रही है। इस शादी में हजारों-करोड़ रुपये लगे हैं और प्रधानमंत्री जी बुके लेकर जा रहे हैं और वे उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है। गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों-करोड़ रुपये की शादी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं है। आप क्या-क्या बेचेंगे? … (व्यवधान) आपने सारे एयरपोर्ट्स और जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं हैं। आप इसको बेचने की गलती मत कीजिए। देश को बर्बाद करने की गलती मत कीजिए। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हैं, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े ख़ैर-ख्वाह बोलते हैं और देश को बेच रहे हैं। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन?

"जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को,
वे नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को ।"

सभापति महोदया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने पहले व्यापार पर कब्जा किया और व्यापार के माध्यम से देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता पर काबिज हुए और फिर सत्ता के माध्यम से, आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पर अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण कम्प्लीट कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : सभापति महोदया, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। … (व्यवधान) बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे। लेकिन, मैं आपको कह दूं कि वे उस दिन नहीं मरे, वे उस दिन मरे जिस दिन ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह कर रही हूं कि आप पर्सनल टीका-टिप्पणी न करें।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : सभापति महोदया, वे मुझे तंग कर रहे हैं। आप उनको बैठने के लिए बोलिए। … (व्यवधान) वे पंजाब से आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुझे तंग करते रहें।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री सुनील तटकरे जी।

… (व्यवधान)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) : सभापति महोदया, इन्होंने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी दी थी। कांग्रेस के लिए नहीं दी थी। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ये अपनी जायदाद पूछें, ये यहां गरीब की बात कर रहे हैं? ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (व्यवधान) ... (*Expunged as ordered by the Chair*) कहां की हैं, यह पहले बताएं।

माननीय सभापति : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि व्यक्तिगत टीका-टिपण्णी न करें।

… (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : महोदया, मी टू में ये, सारे केसों में ये, सबसे ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ये। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : माननीय सभापति महोदय, मैं बोलूंगा। … (व्यवधान) आप अपने आदमी को बैठाइए।

सभापति महोदया, मैं अंतिम बात कहकर बैठ जाता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज … (व्यवधान) अरे भाई सुनिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि आप सब अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

1319 बजे

(इस समय श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित की जाती है।

1320 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/SJN/SNT)
1401 बजे

लोक सभा चौदह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सामान्य बजट – सामान्य चर्चा
और
जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट – सामान्य चर्चा
और
जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र – अनुदानों की मांगें - जारी

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट के लिए रुक जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am raising a Point of Order.

माननीय अध्यक्ष : आप किस नियम के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं?

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am raising a Point of Order under Rule 352.

माननीय अध्यक्ष : नियम 352 तो मुझे मुंहज़बानी याद हो गया है।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, while our hon. Member, Channi ji was speaking, he was speaking about general politics. At that point of time, the MoS from the Treasury Benches intervened. Hon. Chair allowed him to intervene. That is okay. But while intervening, he personally made allegations against the hon. Member, Shri Channi. As per Rule 352, is it applicable? It is clearly against the rules. A Minister is violating the rule. And that Minister even crossed the border. He tried to attack the Members. How can a Minister attack a Member? This is actually against the customs, conventions, and decorum of this House. You are the person responsible to maintain the decorum of the House. We need an action. He has to apologise.

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी भी यहां विराजे हैं। रक्षा मंत्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं।

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीचेस को उठाकर देख लें कि किसने क्या बोला है। यदि

किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, तो उसे सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाए। हम सब पूरे सदन में शांति बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्यवाही चले।

माननीय अध्यक्ष : एक और विषय होना चाहिए। आज तय हो जाना चाहिए। चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, आप सब वेल में न आएं।

… (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरूधुनगर) : महोदय, पहले मंत्री आए थे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट के लिए रुक जाइए। मैं जो कह रहा हूं, आप पहले मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी और सदन के उपनेता ने कहा है, चैंबर में भी कहा और यहां पर भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है और सार्वजनिक रूप से भी कहा है, कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो या उस दल का हो, मैंने माननीय मंत्री जी के लिए तो विशेष रूप से बता दिया है।

हम सदन की गरिमा को कम न करें, ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा कम न हो। कुछ भी टिप्पणी करना हो, कोई विषय है, तो आप चैंबर में आकर मुझसे मिलिए। आप विषय बताइए। आगे उस विषय पर सार्वजनिक रूप से बात करेंगे। चैंबर में भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे, लेकिन हमें यह मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वह रिकॉर्ड में भी नहीं जाता है, अनरिकॉर्डेड भी रहता है और आपस में डिबेट चलती रहती है। कई माननीय सदस्य कुछ भी टिप्पणी करते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको किसने बोलने की इजाजत दी है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य आसन के बारे में कुछ भी अनरिकॉर्डेड बोल देता है। अगर रिकॉर्डेड बोला होता, तो मैं एक्शन जरूर लेता। किसी भी सूरत में आसन के लिए रिकॉर्ड में कुछ बोलेंगे, तो मैं कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन अनरिकॉर्डेड बोल देते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा और आसन पर बैठने वाले सभापति तालिका के सभी सदस्य भी यही कोशिश करेंगे।

(1405/SPS/AK)

सभापति तालिका पर सब दल के लोग बैठते हैं। जब सब दल के लोग सभापति तालिका पर बैठते हैं तो वे वैसे ही मर्यादा रखते हैं, चाहे वे किसी भी दल के सदस्य हों। किसी भी दल का सदस्य हो, लेकिन जब वह सभापति तालिका पर बैठता है तो वह उसकी उतनी ही मर्यादा रखता है। यह अपेक्षा है कि हम भी इसका ध्यान रखें।

श्री सुनील तटकरे जी।

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : सर, मैं अपनी स्पीच कंटीन्यू करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी स्पीच कन्क्लूड कर लीजिए।

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : स्पीकर साहब, आपने जैसा बोला है, आपका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है और हम करेंगे। आप हाउस के कस्टोडियन हो, हम आपकी हर बात मानेंगे। मैंने बजट पर फिस्कल डेफीसिट के बारे में बोला है, गिर रहे रुपये की कीमत के बारे में बोला है, पेट्रोल-डीजल की ज्यादा कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई के बारे में बोला है, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है, उसके बारे में भी बोला है। इसमें दलित वर्ग को इग्नोर किया गया है और महिलाओं को इग्नोर किया गया है। कुछ राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है, बल्कि पॉलिटिकली लुभाया गया है। एक्चुअली में उनको कुछ नहीं मिला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा कि जो बोलूंगा, कानून के दायरे में रहकर बोलूंगा।

स्पीकर साहब, आज देश श्रीमान् राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। अलग-अलग वर्ग के लोग उनको आकर मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे होकर उनके पास आए और उन्होंने अपनी तथा इंडिया अलाइंस की तरफ से उनकी पूरी डिमांड का भरोसा दिया है। इंडिया अलाइंस, कांग्रेस पार्टी आज किसानों की डिमाण्ड्स के साथ है और पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। किसान क्या मांग रहे हैं? वे चीजें बजट में नहीं आई हैं, जिनका किसानों से वादा किया गया था। जब वहां एजिटेशन हुआ था, उसमें 736 लोग मरे और शहीद हुए। पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार, जिसमें मैं मुख्य मंत्री था, हमने 736 परिवारों को नौकरियां दीं। जितने लोग ऐजिटेशन में मरे, हमने सबको नौकरियां दीं और साथ में उनके परिवारों को पांच लाख रुपये कम्पन्सेट दिया, लेकिन आज तक केन्द्र सरकार ने उनकी तरफ नहीं देखा है।

माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वह चीज मांग रहे हैं, जिसका केन्द्र सरकार ने उनके साथ लिखकर कमिटमेंट किया था कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। यह गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है? किसान क्या चाहता है? … (व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : स्पीकर साहब, इन्होंने जो बात कही है, उसको ऑथेंटिकेट करें। वह गलत बोल रहे हैं। वह टोटली बेबुनियाद बातें बोल रहे हैं। चन्नी जी, हवाई बातों से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चन्नी जी, कांग्रेस और इंडी अलाइंस की रोज की कहानी कि लोगों को गलत बोलकर भ्रमित करना। बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वह गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों, हमारे अन्नदाताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : स्पीकर साहब, देश का किसान, जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो तो उसमें क्या गलत मांग रहा है?

(1410/MM/UB)

क्यों उनका कर्ज माफ नहीं हो रहा है? आप पूंजीपतियों का लाखों-करोड़ों रुपये का कर्ज माफ करते हो। लेकिन, आप किसान, गरीब और मजदूर का दो-दो और तीन-तीन लाख रुपये का कर्ज क्यों माफ नहीं करते हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं? इसमें आपको क्या आपत्ति है? अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। एनएसए लगाकर चार किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वे धरने पर बैठे थे। क्या यह खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है?… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: सर, माननीय सदस्य एकदम बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। इनको आज ही अपनी बात को अथोंटिकेट करना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना।

… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : इनका आरोप है- ‘किसान आंदोलन की वजह से’, इस बात को ये अथोंटिकेट करें। … (व्यवधान) सर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे अथोंटिकेट करेंगे। मैंने उनको बोल दिया है कि वे अपनी बात को अथोंटिकेट करें।

… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : ये सदन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।… (व्यवधान) ‘गलत एनएसए लगाया है’ इस बात को भी अथोंटिकेट करें। नहीं तो, इनके ऊपर प्रिवलेज की कार्यवाही होनी चाहिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जो भी बात बोल रहे हैं, उसको आपको प्रमाणित भी करना है।

… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : सर, किसान प्रधान मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। … (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, पार्लियामेंटरी सिस्टम के बारे में सभी को मालूम है और इसके बारे में किसी को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है।… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, क्या एक भाषण के बीच में तीन-तीन मंत्री बोलेंगे? …(व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, जब कोई मेम्बर अपनी बात बोल रहा है और अगर वह कोई गलत बात बोलता है, तो यहां से कोई केबिनेट मिनिस्टर, जिसने मंत्रालय को संभाला है और संबंधित विषय के बारे में जानकारी रखता है, उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई एलिगेशन लगाया है, तो उसको अथोंटिकेट करना चाहिए तो इसमें ये सब क्यों खड़े हो रहे हैं? …(व्यवधान) पार्लियामेंटरी सिस्टम है कि अगर कोई मेम्बर गलत बयान देता है तो ट्रेज़री बैंचिज़ से अथोंटिकेशन मांगना एक परम्परा है।… (व्यवधान) इस पर सारे कांग्रेस वाले क्यों खड़े हो गए हैं? … (व्यवधान) वैसे भी सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना… (व्यवधान) ये तो पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं… (व्यवधान) इन्होंने क्यों गलत बात सदन में बोली है… (व्यवधान) इस मामले को प्रिवलेज में रेफर किया जाना चाहिए।… (व्यवधान) इन्होंने गलत बात सदन में कही है और सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।… (व्यवधान) यह गलत बात है।… (व्यवधान) मैं बीजेपी और पूरे सदन की तरफ से मांग करता हूं कि इस मैटर को प्रिवलेज को रैफर किया जाना चाहिए।… (व्यवधान) हवा में बात करके आप सदन को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं।… (व्यवधान) आप यहां गलत बात नहीं बोल सकते हैं।… (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : स्पीकर साहब, किसान प्रधान मंत्री जी से, सरकार से मिलना चाहता है। वे पंजाब से चले हैं।… (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Piyush Goyal ji said that it is to be authenticated but it should be in his knowledge that लोक सभा में अथोंटिकेटिड नहीं होता है, यह राज्य सभा में होता है। यह उनको जानने का विषय है। It is not authenticated in Lok Saba. He is not aware of the fact. He should withdraw. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, सुदीप दा बहुत सीनियर आदमी हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन, स्पीकर के डायरेक्शन 115 (1)(2)(3)(4) यह कहता है कि कोई मेम्बर यदि गलत बयानी करता है तो कोई मंत्री या मेम्बर उसको सुधार सकता है और स्पीकर उसको अथोंटिकेट करने के लिए कह सकते हैं।… (व्यवधान) इसलिए इस रूल के बारे में सुदीप दा को पता होना चाहिए कि उनको अथोंटिकेट करना है, यह रूल कहता है। इस रूल के आधार पर उनको अथोंटिकेट करना है।… (व्यवधान)

(1415/YSH/SRG)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बहुत समय हो गया है। आपकी पार्टी का समय समाप्त हो जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं उनका समय काटने के बाद का समय बता रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे दिक्कत नहीं है। आपकी पार्टी का समय खत्म हो रहा है तो आपके और मैम्बर्स को मौका नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे गुरु की वाणी यह कहती है कि जब कोई सच बोलता है तो जो झूठा होता है, उसको आग लग जाती है। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बोलने नहीं देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसानों के साथ आपकी दुश्मनी क्या है?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, किसान सरकार से मिलने के लिए दिल्ली आए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बजट का विषय नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : सर, बजट का विषय इसलिए है, क्योंकि हमें कर्जा माफी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई किससे मिलने आया, क्या इस पर आप सदन में चर्चा करेंगे? यह सिस्टम है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं समय देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो समय नहीं भी दे सकता हूँ।

... (व्यवधान)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान में पंजाबी नहीं हैं? हरियाणा में कंक्रीट का पक्का बैरिकेड लगा दिया गया है और किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने किसान को गोली मारी। उसे सामने से मारा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किसान आपका दुश्मन क्यों है?

अध्यक्ष महोदय, आप चाहते है कि मैं नहीं बोलूं तो ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : मैं नहीं चाहता कि आप न बोलें, लेकिन बजट पर बोलें। सामान्य डिबेट करें।

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : चलिए, 'तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने ग़म से कम ख़ाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम ख़ाली न हम ख़ाली।'

(इति)

1417 hours

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Sir, I thank you for giving me an opportunity to start the debate on the General Budget on behalf of the Treasury Benches. I have no words to express my gratitude to the NDA leaders. I am the only one from the NCP Party. But I have been given the opportunity to start the debate.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस तरह से घूम-घूमकर बैठेंगे?… (व्यवधान) क्या ये सीट चेंज करते रहेंगे? पहले वहां जाकर बैठ गए, फिर यहां आकर बैठ गए।… (व्यवधान) आप इन्हें अपनी सीट पर जाने के लिए बोलिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी सीट्स का आवंटन नहीं हुआ है। वह सीट भी एन.डी.ए. की है और मंत्रीगण की सीट है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आपकी भी सीट नहीं है। अभी सीट्स का आवंटन नहीं हुआ है।

… (व्यवधान)

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Sir, I have no words to express my gratitude towards the most towering leader, Shri Narendra Modi Ji. … (*Interruptions*). The whole of India is headed by him. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Sir, I would like to express my feeling … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Now, I will talk in my Marathi language till the Marathi language is given the status of classical language.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके नेता बैठने के लिए बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

(1420/RAJ/RCP)

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

*SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Hon'ble Speaker Sir, today all of us are the part of this 18th Lok Sabha. The opposition Parties have too much hatred and malice against Narendra Modi ji that we have been witnessing for the last-couple of days.

I have been in politics for the last 40 years and it is for the first time after Jawaharlal Nehru ji that somebody has secured power for the third consecutive term. The opposition tried hard to set a false narrative about constitution. … (*Interruptions*) Don't disturb me. Listen to me. … (*Interruptions*)

I am talking about Maharashtra and I talk straight forward. I feel a sense of pride that Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji has secured power for the third consecutive term.

Shri Jawaharlal Nehru ji had also served this country as a Prime Minster for three consecutive terms. But in those days, this social media was not there.

Sir, I did not say a word, what objectionable did I say.

… (*Interruptions*) …..

---

*Original in Marathi

HON. CHAIRPERSON: Please keep silence.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कल्याण जी, कृपया, बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : यह क्या बोल रहे हैं?…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) … *(Not recorded)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee ji, you are a senior Member.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कल्याण जी, आप कृपया बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रक्षा मंत्री जी, आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कल्याण बनर्जी जी, मैं आपको व्यवस्था दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कौशलेन्द्र जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सुदीप दादा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की मर्यादा है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कल्याण बनर्जी जी, आप जहां बैठना चाहे, वहां बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : संसदीय कार्य मंत्री जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप जहां बैठना चाहे, वहां बैठ जाएं, मैं रूलिंग दे रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सभापति महोदय।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप जहां बैठना चाहे, वहां बैठ जाएं, मैं रूलिंग दे रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : अध्यक्ष महोदय।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने कहा कि मैं कहीं भी बैठ सकता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कह रहे हैं कि मैं कहीं बैठना चाहता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप वहीं बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कल्याण बनर्जी जी, सदन में जानबूझ कर आप इस तरह का व्यवधान मत उत्पन्न कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

…(व्यवधान)

1424 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500-1520/KN/PS)
1500 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजे पुनः समवेत् हुई।
(डॉ. काकोली घोष दस्तीदार पीठासीन हुईं)

सामान्य बजट – सामान्य चर्चा
और
जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट – सामान्य चर्चा
और
जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र – अनुदानों की मांगें - जारी

माननीय सभापति : श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे जी, आप बोलिये।

*SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Hon'ble Chairperson, over 140 crore people of India believe in Modi Ji's leadership and they have elected him for the third consecutive term. This reality is hard to digest for them. They were pretty sure about securing power this time but 140 crore people have shattered their dream. The way they are raising hue and cry on petty issues, that is not a healthy tradition for our democracy. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बजट पर बोलिये।

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे (रायगढ़) : मैडम, मैं बजट पर ही बात कर रहा हूं। क्या वे लोग शुरू से ही बजट पर बात कर रहे थे?

*The opposition benches are making allegations that in this Budget, the priority has been given to Bihar State only. But they do not remember the history. There had been a great freedom struggle under the leadership of Shri Jai Prakash Narayan Ji in this country. I was a student in those days. When there was an anarchy in this country, he led agitations. Karpuri Thakurji, another great leader from the State of Bihar, protested against the Emergency and we cannot forget that black episode of Indian democracy. If we have given priority to Bihar, why do they feel offended? They are also claiming that nothing has been given to the State of Maharashtra. But I want to mention here that in the very first Cabinet meeting, Vadhavan Port Project worth Rs. 78,000 crore has been cleared. … (*Interruptions*)

If you do not want to listen, please keep quiet. You people have also talked like this. The State Government under the Chief Ministership of Hon'ble Sharad Pawarji was dismissed because he was not ready to accept the leadership of Sanjay Gandhi. I just want to flag this issue as they have no moral grounds to talk about the Constitution. Shri Yashwantrao Chavanji served in the Ministries like Finance, Defence, Home and External Affairs as a Cabinet Minister, but the Congress party gave ill treatment to him in his later years.

---

* Original in Marathi

The Congress party also insulted Ex Chief Minister Late Vasantdada Patil ji, so he tendered his resignation. We consider this as an insult of Maharashtra and we will never forget it.

Hon. Modi ji has given funds for the development of railway network in Maharashtra Nanar Project worth Rs 2 lakh crore. It was about to be implemented, but who stopped it? This project could have provided employment to 10 lakh people. But, due to political tussle, we lost that big project. Now they are also opposing Vadhavan Port Project.

During elections, you made the issue of our Constitution and misguided the voters. But still the BJP managed to win 240 seats, and succeeded in securing power for the third time. You are jealous of this success. You people miserably failed even in winning 100 seats, hence you are completely frustrated. Our Hon. Prime Minister has recently visited Raigad Fort and I feel a sense of pride for it.

(1505/VB/SMN)

We successfully landed on the moon under his Prime Ministership. In the year 1971, when we liberated Bangladesh, Atal Bihari Vajpayee ji had called the then Prime Minister of India Smt. Indira Gandhi, 'Durga'. But when we successfully completed the lunar operation, the Opposition parties were not ready to give the credit to Shri Narendra Modi Ji but to the scientists.

I would challenge the Opposition parties to prove that the personal welfare schemes run by Modi Government are meant for a particular caste or religion. In fact, these schemes are being implemented for everyone and everybody. But they are trying to polarise the voters in the name of caste, creed and religion. We have brought this Budget to empower women, unemployed youth and farmers but not for any single State. Today, we are running a coalition Government in Maharashtra under the leaderships of Shri Eknath Shinde, Shri Devendra Fadanvis and Shri Ajitdada Pawar for the overall development. But they are only criticizing us for smaller issues. Mumbai is a capital of Maharashtra and also a commercial capital of India. During this NDA regime, Mumbai has received the highest amount of assistance.

I hail from Konkan Region. The Atal Setu Project worth Rs. 22,000 crore has been completed during this regime only. The credit goes to Shri Narendra Modiji as he had provided sufficient funds for this project. A metro rail network has been developed in Mumbai, Pune and Nagpur too. Some other infrastructure projects have also been completed. Road connectivity has improved a lot. Only Mumbai-Goa Highway is incomplete and I hope it will be completed soon.

(1510/SM/PC)

Today, I would like to request that the Konkan Railway Corporation should be merged with the Indian Railways so that it could be developed like other railway networks. I am sure that the Government would definitely look into it for the overall development of the Konkan region. We have got 720 KM long coast line.

Madam, 4 Bharatratna Awardees named Maharshi Dhondo Karve, P.V. Kane, Dr Babasaheb Ambedkar and Acharya Vinoba Bhave were born in my Lok Sabha constituency. I consider myself lucky that these 4 great personalities belong to my region. I do not know, whether I will be there are not, but I am pretty sure we will be a developed nation in the year

2047 just because of Modiji's development agenda. The Government should develop a memorial for these four 'Bharat Ratnas'.

Maharashtra's former Chief Minister Yashwantrao Chavan had played a key role in the development of Maharashtra. Now, the NDA is also committed towards overall development of Maharashtra. Do not oppose for the sake of opposition. You should go through the budget and verify how much of fund have been allocated for the Metro Rail Project in Mumbai. At the same time, we are facing some critical issues of onion-growing famers regarding the MSP and Onion Export Policy. There was a meagre increase in MSP during UPA regime but during Shri Narendra Modi regime, it has increased manifold. Justice should be done to the farmers who grow onions, sugarcane, soya bean etc.

(1515/CS/RP)

A lot has been done for the farmers but a lot is needed to be done in future because ours is an agriculture dominant country. In the name of reservation, some anti-social elements are trying to tarnish the social fabric of Maharashtra. In coming years, only NDA can help for the upliftment of Maharashtra. The Mahayuti Government in Maharashtra has brought Laadki Bahin Yojana for the welfare of women. I believe that we will definitely secure power in Mahrarasthra in October-2024 elections.

I would like to request the Union Government to confer Bharat Ratna Award on Ex Chief Minister Yashwanrao Chavan. Padma Shri award should be awarded to late Barrister AntulayJI.

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : आप बैठिए। आपस में बात मत कीजिए। आप इधर देखकर बात कीजिए। आप बैठो।

… (व्यवधान)

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे (रायगढ़) : देखिए, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ।… (व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत के किसानों के लिए कुछ न्याय देने का प्रयास एनडीए की सरकार के माध्यम से हुआ है।… (व्यवधान) आगे कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है।

(1520/NKL/IND)

*I can speak Hindi and English equally well but, I prefer to speak in Marathi and I will continue to speak in Marathi till the classical language status is accorded to Marathi language. Sant Dnyaneshwar and Sant Tukaram have explained about the importance and sweetness of Marathi language. During the general elections, you, the people, in the name of Constitution and today you are portraying this Modi Government as anti- Maharashtra. But, 13 crore people of Maharashtra will never trust you. The Modi Government has cleared the Vadhavan Port Porject and around 10 lakh people would get employment through it.

You should not mislead and misguide the people. Today the BJP has given me this opportunity to speak on the Budget. I am really thankful to them.

Jai Hind. Jai Maharashtra.

(ends)

* Original in Marathi

1522 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Budget. It is good that the Finance Minister is here.

Yesterday, Shri Abhishek Banerjee from our Party had enunciated all the objections we have to the Budget, particularly with regard to the dues to the State of West Bengal on account of MGNREGA and Indira Awaas Yojana. The Government has always been strangely silent on this demand of West Bengal. I again reiterate the same. This has proved to be the most divisive Budget in recent times. It is because a Budget is supposed to present the future plans of the Government. But this is a Budget which is called as the 'AB Budget – Andhra-Bihar Budget'. … (*Interruptions*) They have allotted Rs. 59,000 crore to Bihar and Rs. 15,000 crore to Andhra Pradesh for a new Capital. At least three Chief Ministers of the Congress Party, the Chief Minister of Punjab, and the Chief Minister of Tamil Nadu have opposed the Budget. And, of course, the Chief Minister of West Bengal has called this Budget as an exercise to save the Government. She also said that this Budget gave zero to West Bengal. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Please do not disturb.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Yes, the Chief Minister of Kerala has also opposed the Budget.

Madam, I read the Budget Speech several times very carefully. It is a copy-paste job. The Congress has already complained that they have taken some ideas from their Nyay Patra.

Just have a look at Point No. 26 which relates to education loans. It is the exact programme launched by the West Bengal Government for students. The amount of Rs. 10 lakh is also the same. … (*Interruptions*) You are not even original. … (*Interruptions*) I do not expect the Finance Minister to be like Dr. Manmohan Singh, as she is not a Ph.D. from Oxford, or like Mr. Chidambaram who has got the Management degree from Harvard. She is from our own JNU. … (*Interruptions*) But the problem is that she is bereft of new ideas which is why this Budget reads very dull. … (*Interruptions*)

(1525/VR/RV)

Then, you realize that all the notes in the Budget have come from the PMO, whatever the PMO has said – she has no original idea – she has put it in the Budget by way of copy and paste method.

Now, this year, the Finance Minister vowed to spend Rs.2 lakh crore over five years on five skills, which are part of what she called the 'Prime Minister's Package', aimed at spurring jobs and imparting skills to 4.1 crore youth. This marked a shift in strategy from the previous Governments, preferred reliance in letting multiplier and trickle-down effects. Formerly, they said, you give a lot of money, something will trickle down. But earlier they did not give any direct handouts to any section of society. The trigger, why the Budget has changed course, is due to the BJP's electoral reverses, now there is a Government without a majority. Abhishek called it 'shaky Government', I would call it further, 'brittle Government', just like a glass which will break at any time.

The Finance Minister tried to address the perceived disenchantment among the youth, the salaried class, the farmers and the small entrepreneurs. One important thing – Madam, you should take note of it – that just before the elections, the revelations came about the donations received for electoral bonds. The BJP alone got 50 per cent of all electoral bonds received by all political parties. Which meant what? This is a Government of the moneyed-class, as some people say of Adani's and Ambani's, who contributed to your elections. *....(Interruptions)* They contributed even to you – (*Expunged as ordered by the Chair*) Please do not forget. *....(Interruptions)*

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैडम, ये क्या बोल रहे हैं?… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Did you see the revelations?

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : आप जब बोलेंगे, तब जवाब दे दीजिएगा।

आप बैठिए, इन्हें बोलने दीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैडम, इन्होंने मेरा नाम लिया है ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No name will be taken.

....(Interruptions)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : मैडम, अडाणी किसी का नाम नहीं है, यह टाइटल है।… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैडम, मैं बोलूंगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इन्हें अपना भाषण खत्म करने दीजिए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैडम, इन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए रूल कहता है कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने का अधिकार है।... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): But in spite of all this, the stock market has reacted badly. It was probably because of the Capital Gains Tax. So, in spite of all this, the capitalists are not happy.

Now, Madam, I will emphasise what the basic problems of the Indian economy are, and whether they have been addressed by the Finance Minister or not. According to data from the Centre for Monitoring Indian Economy, unemployment rate rose to a high of 9.2 per cent in June 2024. The female unemployment rate was higher than the national average of 18.5 per cent in June 2024. Now, we have been doing very poorly in terms of employment generation. You may be knowing, Madam, that there have been job losses in the IT sector. With artificial intelligence (Artificial Intelligence) coming in, there is fear of further job losses in what was seen as the most profitable part of the Indian economy.

The second big problem in the Indian economy is rising inflation. The annual consumer inflation rate in India rose to 5.08 per cent in June 2024, well above the market expectations.

(1530/SAN/GG)

Prices accelerated steeply for food - 9.36 per cent - which is responsible for nearly half of the weight of Indian consumer basket.

One company called Kantar did a study and found that in 2024-25, 34 per cent households reported that they are finding it difficult to manage their expenses, indicating that a third of India is still under severe financial stress.

The other problem is, Madam, the shrinking informal sector. This is what has sustained the economy for so long, but informal sector is in a grave crisis. As NSSO data shows, India's 65 million informal or unincorporated sector enterprises employed 110 million workers. They are suffering very badly. What we call MSMEs are also suffering.

The other big problem is falling private investment. The Finance Minister, in our presence, handed over a tax bonanza to the corporate sector, but the private investment has been falling. The Government has been hoping that large Indian corporations would step in and ramp up investment. They introduced production linked incentive schemes for big businesses, but all these incentives have failed to motivate private investments. They will spend money on their son's marriage, but they will not invest in new enterprises. That is a big problem of the Indian economy.

Lastly, we have the problem of shrinking labour productivity. Labour productivity contracted in FY23 compared to the preceding year, thus highlighting India's lack of competitiveness in industrial sectors. There is what is called extreme disparity in wealth and income distribution which has pushed the economy to a state of 'gated stagflation'. That is what the economy is today. The Finance Minister must resort to Keynesian prescription of boosting aggregate demand by allocating more Government funds for the social sector and targeted welfare programmes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Increased Government spending will boost household consumption which will stimulate private investment. The Finance Minister has not gone this route at all.

Madam, let me now come to the very important study of the social sector. How much money has the Government doled out to the poor? The allocation for school education has increased only by a nominal amount of Rs. 5,000 crore and for higher education by only Rs. 3,000 crore. In both the cases, the estimated recoveries are substantially higher compared to previous year, indicating higher fees and self-financing schemes in educational institutions. Allocation for health and family welfare has barely increased by Rs. 1,500 crore. So, health and education, as Dr. Amartya Sen is fond of saying, are the foundations of the economy and there, we are not having enough money. There is hardly any increase in food subsidy too, despite the need for expanding coverage to the current population level.

Madam, lastly smaller yet critical schemes – please listen to this, Madam – that address vulnerable population have not got much attention. There is only a slight increase to Rs. 12,467 crore for the Poshan Scheme, that is, school mid-day meal scheme.

(1535/SNT/MY)

That is actually less than the actual expenditure on this scheme. The other thing is that budgetary allocation for anganwadis – Madam, you are familiar with all these things – is only Rs. 21,200 crore. It was only Rs. 20,554 crore last year. What does it mean? There is clearly no hope for higher salaries for anganwadi workers which has not been revised since 2018. It is shameful that you have no sympathy for the poor anganwadi workers. … (*Interruptions*)

The other thing I want to mention is the budget for National Social Assistance Scheme. Madam, you are an MP. Old people come to you for widow pension and disabled pension. Look at this. The budget for National Social Assistance Programme, which gives social security pension to the elderly single women and disabled, remains unchanged – not a rupee is added – at Rs. 9,652 crore. This is a reduction in real terms taking inflation into account. Madam, please consider this.

Lastly, I will come to the new package. They say it is the Prime Minister's package for employment and skilling, which includes Government sponsored internships, formalisation of jobs through incentives for Employees Provident Fund Organisation enrolment and skill development programmes. These schemes do not seem, Madam, may I say, very impressive when one looks at the budgetary allocation. You say that you are taking care of unemployment but the entire package has an allocation of Rs. 2 lakh crore over a period of five years. How much per year is Rs. 2 lakh crore amount for five years? It comes to Rs. 40,000 crore per year for employment generation.

Further, the private sector is required to spend money towards this package from CSR funds. Earlier, private sector used to develop a school, a hospital, etc. Now, the Prime Minister is taking in the money from CSR

fund. By allowing this, CSR fund through which companies contribute to society in some minimal way is now mandated to be used towards subsidising wages for themselves. How will this economy survive? Rather than discussing damping demand, stagnant wage, and what can be done to revive employment, the announcement only includes supply side schemes towards incentivising the private sector. You are like Milton Friedman. You are indulging in supply side economics. You are of the view that if you give more incentive to the private sector, they will create employment. Different versions of this have been tried earlier and failed. Whether this package will be any different, it remains to be seen.

Madam, as I was saying earlier, this is a disappointing, anti-poor people scheme. One question is this. Madam, you have only discovered this now. You have been a Minister for seven years though you are not a trained economist. You are lucky that way. … (*Interruptions*) She is not a trained economist. What is wrong in saying that? She is no Manmohan Singh. She is not even Chidambaram. She is not even Anantha Nageswaran. Why did you not act upon demands made by Bihar, Andhra Pradesh, and Odisha earlier?

(1540/AK/CP)

Why are you thinking of them now? It is only because of the political compulsions. In your brittle and unstable Government they are the crutches on which you lean, and your economy and Budget is going haywire or is lopsided because of all these things. India is more unequal now than in the 1920s. It is an unequal society that we have. During colonial rule we were still somewhat more equal than we are today.

The Finance Minister, of course, has not dealt with inflation. There are only 10 words on inflation, which is the most important problem affecting everybody. I will just give one or two figures and wind up because my friend Shrimati Satabdi Roy Banerjee is due to speak and she is naturally feeling disappointed as I go on and on. I will wind up.

They were saying that Rs. 11.11 lakh crore is given for infrastructure. Good! They think that is the real panacea or ready medicine for all the ills affecting us. Is it so? One infrastructure project will take five to 10 years to complete. There is an infrastructure project in your area, namely Dum Dum - Barasat Metro Line. How many years it has taken now? It is nowhere near completion. The problem with an infrastructure project is that it has long-term spill-off and no short-term spill-off. This does not appeal.

I will give a figure. They say that Mr. Ashwini Vaishnaw is a great Railway Minister, and that he has introduced Vande Bharat trains. In FY 2024, the Railways are at 5.42 per cent of the Budget. It is known that the Budget is Rs. 48 lakh crore and revenue is Rs. 32 lakh crore. Now, Railways have come down from 5.42 per cent to 5.3 per cent. As regards Civil Aviation, young Mr. Rammohan Naidu was waxing eloquent in the morning. … (*Interruptions*)

Madam, I am winding up. Even on Aviation, the allocation is 0.05 per cent of the Budget; and on shipping, the allocation is 0.05 per cent. As regards social sector spending, on health it is only 1.85 per cent of the Budget. On Rural Development, which is most important, it is only 5.51 per cent of the Budget. As regards higher education, you want to educate the people, privatise education and people will learn on their own, but the Finance Minister’s prescription is higher education is 0.99 per cent of the Budget. The allocation for school education has come down from 1.61 per cent to 1.51 per cent of the Budget. … (*Interruptions*)

Madam, this Budget will not give relief to the poor in the country. This Budget will not spur investment. This Budget will not take from the rich and give it to the poor. This Budget will not stop conspicuous consumption by those who indulge in marriage feats. This Budget is for poor people who just look and gape at whatever happens in Mumbai -- all the stars descending in Mumbai.

With that, I end my submission on the Budget. Thank you, Madam.

(ends)

(1545/UB/NK)

1545 hours

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Madam, Chairperson, as I rise to speak in support of the Budget, I seek your indulgence. From the turn of the century for almost two decades, I had the opportunity and I was privileged to speak many times on the Budget in both the august Houses. But I have been away for a while for about five and a half years, and now back as a member of this house, it is my great privilege to speak on this most important Budget, but it is almost akin to a maiden speech.

Madam, I compliment hon. Finance Minister Nirmala Sitharaman ji on this historic Budget. It is 'historic' because not only is it her seventh successive Budget, but the first one in the historic third consecutive term headed by Prime Minister, Narendra Modi ji. Madam, I wish to put this Budget in the context of what has happened in the last ten years.

I will speak on the Budget, but this context is important. Just a few minutes ago, we heard a pining for the colonial era. Before that, we have heard weird allegations that this Government is like the British Raj, which has just been contradicted by my previous speaker who was pining for the colonial era of the 1920s. There are terms to describe this kind of an attitude, but I will remain parliamentary. So, the parliamentary term for it in social sciences is referred to as a 'Westernized Oriental Gentleman', a wog. That is because while you pine for the former masters and the degrees that they give from their countries and denigrate ours, those former masters do not respect you. They refer to you when they are charitable as wogs.

The context of the last ten years is as follows. When the hon. Prime Minister Modi formed his first Government ten years ago, he inherited from the previous Government a huge backlog of undone reforms. In fact, in the words of my friend, the hon. Member from Thiruvananthapuram, you may call it a long laundry list of unattempted reforms starting with GST, going on with the Bankruptcy Code, and we could keep going on and on.

This Budget is both very wide in its scope, but also very deep in addressing the reforms that are necessary to take Bharat forward. For the last five years from outside this House, I have admired Nirmala Sitharaman ji's previous Budgets when, during the second Modi government, she consolidated

on the deep fiscal reforms that were initiated in the first Modi Government by my friend, the late Arun Jaitley.

In the second term, during Nirmala ji's Budgets being presented, India consistently remained the fastest growing large economy in the world. Now, sometimes questions are raised what the importance of being the fastest growing large economy is. How does it benefit the *aam aadmi*? How does it benefit the average *Bharatiya*? It is because this growth has enabled the massive increases in allocations and the massive improvement in outputs and results that have been demonstrated in the last ten years. This has been commented upon by a wide variety of experts around the world. I will refer to some of them.

Now, if you look at just a few weeks ago, looking at the data coming out for the financial year that we just completed and entered this financial year, these are the words of some of the pink papers in both India and abroad.

(1550/SRG/SK)

I quote one, but this has been repeated many different times. I quote; “In 2024, India has experienced significant economic growth with exports reaching a record high of USD 776 billion at an 11.8 per cent increase. The unemployment rate has dropped to a record low of 3.1 per cent, and business activity and job creation are at an 18-year high, reflecting a robust economy.”

Madam, some of my friends in the Opposition Benches get a little triggered when we cite some of these statistics. So I will have to issue a trigger warning. But the data indicates, if you look at the job creation data, for example, I will tell you where it is manipulated. The manipulated data comes from certain organizations where the head of the organization is the head of your manifesto drafting committee. When you cite organizations where the head of that organization is the head of your manifesto drafting committee, that is biased. This is not biased. These are RBI data. These are reflected by the World Bank and by the IMF and India’s pink paper. … (*Interruptions*)

Madam, just in the manufacturing and services sector, in the last 10 years, 89 million jobs have been created; compare this with only 66 million in the previous 10 years. Look at the Economic Survey that preceded the Budget just a couple of days ago. The Economic Survey points out that the percentage of youths who are deemed employable has improved from 34 per cent to 51 per cent in the last 10 years. This work is being taken forward with many other steps to be mentioned in this Budget which I will come to later.

Madam, I think while increasing these allocations - I will refer to some of the increased allocations in infrastructure and other areas – for example, my previous speaker just mentioned about allocations to health. I think the House deserves to know that in the last five years under the leadership of Shri Narendra Modi Ji, Nirmala Ji allocated a compounded annual growth rate of allocation to the health sector of 9.5 per cent which is a new record. The system has to have a capacity to absorb, and that is why, it has to be stepped up gradually. You cannot beat this high CAGR commitment to health. But one of the most impressive parts of the Modi Government, especially in the last five years is how the fiscal deficit has been managed despite these high allocations for the growth of India. I refer to the fiscal deficit, it gets referred to a lot, but I want to take a moment to go behind why it is important. In this House, not just in the Treasury Benches, also in the Opposition Benches, there are many friends with whom I have personally sat and engaged in discussions with multilateral and global financial institutions, and they point out that the single biggest factor they look at when giving a country rating is the fiscal deficit, and that is what impacts inflation, that is what impacts our exchange rate to which some of our friends have been referring.

The fiscal deficit which was inherited 10 years ago at 10.5 per cent was continually brought down in Modi Ji's first term until it reached 3.4 per cent, and then the whole world was turned upside down because of the COVID-19 pandemic and India managed it far better than all other countries. But yes, of course, we saw a rise of fiscal deficit to 9.2 per cent. But the roadmap that has been shown since then by the hon. Finance Minister has been rigidly adhered to coming down year after year to 6.7 per cent, 6.4 per cent, 5.9 per cent, 5.8 per cent, 5.6 per cent and 4.9 per cent this year, and her commitment to bring it back down to 4.5 per cent next year is extremely commendable.

(1555/RCP/MK)

One of the challenges of high growth rate is that sometimes it does create inequalities. That is an allegation that some of our friends have been wrongly making. I will tell you why. This is because inequality is something that is measured. There is something called the Gini Index which measures inequality in a society across all countries. The reality is that India's Gini Index which started out 10 years ago in the mid-thirties has remained in the mid-thirties. Inequality has not changed by economic parameters. Why is this particularly

impressive? … (*Interruptions*) The important thing is that the Gini Index of India is far better than other BRICS countries like China and Brazil which means despite being in the same economic strata, we are a far more equal society. What is even more impressive is that our Gini Index compares more favourably than highly developed countries which have been allocating huge sums to welfare such as the United States, such as the UK. The reason that our Gini Index has been so impressive is because of the allocations, the outputs and the results of many of the aspects of the last 10 Budgets and particularly this historic Budget. Let me give you an example.

To maintain equality in a society, if you provide *roti, kapda aur makaan*, that is what helps maintain equality. Coming to the Pradhan Mantri Awas Yojana – it is just a comparison – in the years before the last 10 years, there were schemes like the JNNURM and the Rajiv Awas Yojana which sanctioned a total of less than thirteen-and-a-half lakh houses. By comparison, since 2015, the Pradhan Mantri Awas Yojana has sanctioned 42 million houses, and this year 30 million more houses are going to get built. Take for example the Jal Jeevan Mission, another very key aspect of the various Budgets of the Modi Governments I, II and III, especially in the last few years. … (*Interruptions*) Take a look at this. I will give you the statistics. The Jal Jeevan Mission just a few days ago … (*Interruptions*) Please have the patience to listen. The Jal Jeevan Mission has achieved a milestone of 150 million rural tap connections up from just 30 million five years ago. There is five times growth in just five years. This translates to 2.28 lakh villages and 190 districts achieving the Har Ghar Jal milestone. Similarly, Ayushman Bharat, which provides health coverage to hundreds of millions of Indians, the world's largest such programme, again this year has got an allocation of Rs.7,300 to take it forward.

There have been some comments on this historic Budget's focus on Purvodaya. I think, it is important to discuss this. Now, the Prime Minister is on record as having a deep commitment to the North East and the East which he has repeatedly explained that unless these previously neglected regions get developed, Bharat is not going to get developed. That is why he has visited the North East a record number of times more than all his predecessors. The Budgets that have been allocated for the East and the North East have been a witness to this transformation. Now, I will come to the point where you might really want to get excited.

(1600/PS/SJN)

Madam Chairperson, the Eastern States had traditionally been neglected by the Centre. But what is more tragic is that within the East, there was discrimination from one State to another despite the Ministers from those eastern States having had a role in Delhi.

Madam Chairperson, more than 20 years ago, I first spoke on the Budget. In those days, the Railway Budget was different, and it was a separate one. I myself was shocked to find some of these statistics. I still remember the statistics more than 20 years later. … (*Interruptions*) My friends, please reflect on this. Twenty years ago, when I first spoke on the Budget, I found that West Bengal had the country’s highest rail track density. And I remember the number. It was 42 kilometres per square kilometre. Right next door to West Bengal was my State of Odisha which had the lowest number in the country. It was 14 kilometres per square kilometre. Every year, we used to appeal to the Centre to increase our allocation. We used to keep getting a few piddly hundred crores of rupees. And our appeal was, ‘At least, please give us a 1000-crore rupees’. In the first Modi Budget ten years ago, we were gobsmacked when the allocation straightway went five times to Rs. 5,000 crore. We did not then have a Railway Minister from Odisha. The Modi Government does not believe that ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas’, is determined by proportionate representation, but it is for all India. Madam, I thank the hon. Railway Minister. This year the allocation for railways for Odisha is Rs. 10,500 crore. This will go a long way towards bringing Odisha up to the national average and beyond.

Madam Chairperson, when we talk of ‘Purvodaya’, even West Bengal is included. Yes, there has been a lot of talk about Bihar and Andhra Pradesh. Some of our friends from other Parties in the other House created a ruckus because they wanted to know how much has been allocated despite the hon. Finance Minister specifically covering a wide ray of investment opportunities. And just yesterday, from what has

been presented in the Parliament, it looks like our long-awaited Coastal Highway Project, which is going into the DPR stage, is moving forward, and that is something like two and a half times of what the Railway Minister has given us. This will be a total transformation for Odisha.

Madam Chairperson, I want to refer to a couple of important voices that have been celebrating India's success. These are the global voices.

1603 hours (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

Madam, I will first mention that many … (*Interruptions*) I apologise. I did not realise that there has been a change in the Chair.

Respected Chairperson, Sir, the Modi Government believes in finding win-win solutions which are fiscally and environmentally sustainable. There are those of our friends in other Parties, who run some States; who run their States into the ground because of freebies which they cannot fund. Then, they keep running to the Centre asking for special funds. The Modi Government works differently. Look at electricity. The massive thrust on renewable energy as well as on solar energy has been something of a world record set-up. If you look at it, 10 years ago, India inherited a total installed capacity of 2.6 gigawatts. It is something that has been cherished and celebrated around the world. But today, this photovoltaic capacity, the solar cell capacity, installed is 85.5 gigawatts.

(1605/SMN/SPS)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please wind up in a minute.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is another such win-win solution and it was important that the hon. Finance Minister mentioned that more than 1.28 crore applications have been received for this because this proves that this is a yojana which is getting uptick, which is getting enormous interest. And, not only will these households get 300 units of free electricity but the extra electricity that will be generated and sold from their rooftops goes into

their accounts. This is something that is being again talked about a lot everywhere else.

Sir, as I start coming to the end of my speech on the Budget, I want to talk about the digital transformation that has happened under the Modi Government one, two and three, which is the talk of the world.

Now, look at the start-up environment. Ten years ago, we had a total of some 350 start-ups. This has grown 300 times in the last 10 years and now, India has more than 90,000 start-ups, third highest in the world, and these have been made possible by the various policies of the Modi Government and the budgetary support for such development.

Sir, the World Bank has made the following comment. I think it is worth mentioning.

> "Without the digital payment infrastructure such as Jan Dhan Bank accounts, Aadhar and mobile phones, the JAM trilogy, India may have taken 47 years to achieve the financial inclusion which it has achieved only in six years. This is the kind of transformation that is happening".

Sir, in the limited time available to me, I will not be able to go into each and every aspect of the Budget but suffice it to say that the thrust on infrastructure continues and this is again the talk of the world and this year's allocation of Rs. 11,000 crore continues that initiative which is transforming India, creating jobs and keeping us as the fastest growing economy.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Yes, I will just make this one last point and I will conclude.

Sir, one of the most transformational infrastructure initiatives that was started under the late Shri Atal Bihari Vajpayee Ji in the first NDA Government was the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana scheme.

Sir, I represent the coastal district of Odisha, Kendrapara, where many areas used to get completely cut off during the monsoon, and children could not go to school and the citizens could not go to hospitals but the PMGSY concrete roads made it possible that even something which may be 15 kilometres away becomes easily accessible on a bicycle. It has transformed lives but there are still areas that are left behind and I compliment the hon. Finance Minister that in this historic third Modi Government, she has proposed the fourth phase of PMGSY which is going to create connectivity to another 25,000 habitations and it transforms places like Kendrapara, places around the country, especially in the North East, and the previously neglected areas where many habitations, many villages used to be deprived of the basics of life, which are now being made available to them.

Sir, I could go on and on. I will just conclude by saying that sometimes our friends in the Opposition tried to blame us for their own faults. Sir, whether the infrastructure which is facing problems, was built during their time or whether the crisis in the banking sector, the transformation in the NPAs in the banking situation is noteworthy. I will conclude with that.

Some Rs. 64,000 crore worth of assets have been seized which was not happening and it may be paining some of our friends because the parties of nepotism, parties of corruption obviously had a stake in all those defaults.

Now, some Rs. 15,000 crore have been returned to banks and in this Budget, the hon. Finance Minister pointed out that Rs. 3,30,000 crore has been returned to the creditors so far because of the policies of the Modi Government.

With that, I conclude my speech in favour of the Budget.

Thank you.

(ends)

(1610-1620/SM/MM)

1610 hours

*()DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): (Hon Chairman Sir, thank you for this opportunity. I thank our DMK leader and hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru *Thalapathi* M.K. Stalin for making me to get elected from Chennai South Parliamentary Constituency for the second consecutive term and enter into this Parliament. Our leader Thiru *Thalapathi* M.K. Stalin is such a great personality with so much generosity and pride as he presents the Budget every year for the people who voted him to power and also to those who did not vote for him. I also thank the people of Chennai South Constituency for electing me. I thank the people of Tamil Nadu, who gave a huge victory to INDI Alliance with all 40 seats in Tamil Nadu and Puducherry just crushing the day dream of those who were claiming to win more than 400 seats. Hon. Chairman Sir, Sengol, the sceptre is placed prominently in this House. Long ago we gave up monarchy and started practicing democracy. The essence of democracy, as enshrined in the Constitution, states that we have to treat the people of all the States equally without any bias, favouritism or hatred. But forgetting those ideals, this Budget is presented without a single mention of words like Tamil Nadu and Tamil. That is why, I wish to say in my mother tongue Tamil that I am alive because of my mother tongue and I would not even want elixir from heaven in exchange.)

> "Oh my dear precious mother tongue, I survive and thrive because of you. I would not plunge even for the nectar from heaven."

(I started my speech in Tamil which is 3000 years old, and I continue to speak in Tamil. While presenting this Budget, our hon Finance Minister said and I quote,) "The Government is determined to ensure all Indians regardless of religion, caste gender and age, make substantial progress and realizing their life goals and aspirations". (We are Tamils living in Tamil Nadu which is a State in India. Are we not Indians? Why are we ignored? Everyone is here saying with pride that the hon. Finance Minister has presented this Budget consecutively for the seventh record time. It gives us immense happiness. But the hon. Prime Minister visited Tamil Nadu eight times and even then he could not make a Candidate of his Party or an ally to win an MP seat from Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu have been victimised for the reason that they upheld democracy, federalism and religious harmony. This is not our statement. Rather this is the statement made by eight crore Tamils living in this country. You have never thought of Bihar and Andhra Pradesh during the last 10 years of your regime. Now you have given them in abundance. But you are not bothered to give at least something to Tamil Nadu. During April 2024, Bihar paid only Rs.1992 crore through GST to the Union Government whereas Tamil Nadu paid Rs. 12,210 crore. But the Union Government has given Rs. 37,500 crore to Bihar. On the contrary, Tamil Nadu has received nothing. The amount allocated is just zero. Is this the Vasudaiva Kudumbam or the Global Family that the Prime Minister talks very often? Is this the justice rendered by the Viswa Guru? The hon. Finance Minister made a mention about Andhra Pradesh five times in this Budget. The word 'Bihar' was mentioned five times in this Budget. Not even once she mentioned about Tamil Nadu in this Budget. Not even Tamil Nadu, States like Telangana, Karnataka are also not mentioned.

* () Original in Tamil

Even Kerala did not find a mention. Now I am reminded of a saying from *Ho Chi Minh* who fought for the freedom of the people of Vietnam. He said everything will start for the South. In his footsteps, our great leader *Muthamizh Arignar* Kalaignar had said “South has the strength to complete everything that is started”. Therefore, as a continuation of our struggle, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has decided to boycott the meeting of NITI Aayog which even stated that Tamil Nadu has the prestige of being No. 1 in the country in 13 important fields. The hon. Chief Minister of a neighbouring State has also decided to boycott this NITI Aayog meeting. Disaster relief fund has been provided to our friendly States like Sikkim, Arunachal Pradesh and Uttarakhand. We do not have any ill-will towards the fund allocation to such States. Our Tamil Nadu Chief Minister looks at all these States with a sense of brotherhood. He sends Rs.10 crore to Himachal Pradesh as relief fund. He has given disaster relief assistance to Kerala during floods. Thiru M.K. Stalin has sent relief assistance to the affected people of Manipur by ensuring that it reaches their places of stay. When a rail accident took place recently in Odisha, a 24-hour round-the-clock Control Room by Tamil Nadu Government was set up to safely bring out the stranded rail passengers. We have done all these things. We are not blaming anyone. When the people of Chennai suffered losses and lived in pain and anguish due to heavy rains and floods, many Union Ministers visited the affected areas. We sought Rs 37,000 crore as flood relief assistance. But we got only Rs. 276 crore that too a legitimate amount. Is this the Vast Bharat or Akand Bharat the Prime Minister often talks about? The hon. Prime Minister often quotes Mahakavi Bharathiyar and Thiruvalluvar. “Let us say with pride this is our country, Bharat”, Bharathiyar said. In a letter addressed to Nellaiyappar, Mahakavi Bharathi says “My brother, what can I do? I am saddened when someone says there is a language that is so special than Tamil. I do not accept the statement that some others are even stronger than Tamils.” This is not to bring inequality or a bifurcation. I am not at all talking on these lines. But as far as our rights are concerned, we have to raise our voice to protect our rights. “Your enemies decide what weapons you hold in hand”, says Che Guevara. We are here to voice our concern and to get back our rightful due. This Budget is presented just to appease the Alliance Parties. I will say) it is not an all India Budget. It is an Alliance Budget (because Tamil Nadu, which is not part of the NDA alliance and which has not made them at least to secure one MP seat, has been completely ignored. There is no prominent or big scheme for Tamil Nadu in this Budget. Whether it is the Highway project or the Railway project or the Metro Rail Project of Coimbatore and Madurai Cities, all are kept in abeyance. I wish to say that many schemes that were announced by the hon. Finance Minister are just a copy of the schemes of our Dravidian Model of governance. Up-gradation of 1000 ITIs and Thozhi- the friendly hostels for Women, are being implemented successfully in Tamil Nadu. Hostels for workers and labourers and other schemes are also implemented in Tamil Nadu. The hon. Finance Minister as a matter of gratitude for emulating such schemes from Tamil Nadu should have allotted adequate funds for the State of Tamil Nadu. For example, if you take Chennai South Constituency, our hon. Union Minister laid the foundation stone in Chennai Kalaivanar Arangam for the Second Phase of Chennai Metro in the year 2010. The hon. Prime Minister, in the year 2011 announced that Rs 63,000 crore will be allocated for implementing this project. Till now not even a single rupee was allocated for this project by the Union Government. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu with a kind heart has allocated Rs 33,000 crore and the work has begun. Already the State of Tamil Nadu is under financial burden.

Now if you see the Prime Minister Awas Yojana, the hon. Finance Minister has announced that three crore houses would be constructed under this Scheme in the next five years. But there is no mention about increasing the amount of financial support given by the Union Government for construction of each house under this Scheme. If the Union Government provided Rs 1.5 lakh for construction of a single house under this Scheme, the State Government has to spend from Rs. 12 lakh to Rs.14 lakh per house. Even though the State Government spends the maximum amount under this Scheme, the name of the Scheme is Prime Minister Awas Yojana. How is it justified? Stamp duty falls under the State List. The Union Government has instructed the States to reduce this stamp duty. Our Chief Minister of Tamil Nadu asks a valid question. If you want the States to reduce the stamp duty, are you not supposed to pay compensation to the States for making such a reduction in stamp duty? Due to the levy of GST, Tamil Nadu is facing a loss to the tune of Rs 20,000 crore per annum. Our hon. Chief Minister is asking the Union Government that how much money has been given by them as compensation to Tamil Nadu. Not only our Chief Minister of Tamil Nadu, but also all the people of Tamil Nadu are also asking the same question. This Budget is on five important aspects. The hon. Finance Minister calls this) it is a Prime Minister's package. (In the Interim Budget, she had already mentioned giving priorities to Women, Farmers, Poor and Youth in a broad framework. As a supplement to that, the hon. Finance Minister has now announced about this Prime Minister's package. The Five-Point Policy includes employment, education, skill development, and development of women. If you take employment, 4.1. crore youth will be provided with employment during the next five years. The Finance Minister says Rs. 2 lakh crore will be allocated for skill development initiatives. In the year 2014, the unemployment ratio was 5.44 per cent and that rose to 9.2 per cent in 2024. Recently, in the Ankleshwar city of Bharuch district in Gujarat, a private company organised an interview for providing employment to the local youth. This interview was attended by thousands of youths in a building which was about to collapse. This is the achievement of BJP during their last 10-year rule.

As regards skill development, in the next five years, one crore youth will be provided Internship opportunities in 500 companies. An incentive of Rs 5,000 will be provided by the Union Government. Ten percent of expenditure of this Internship would be borne by the private companies through their CSR funds. That comes to Rs 60,000 crore for a five-year period. This will again benefit the big companies. The MSMEs and the Start-Ups will not be benefitted by this Scheme. The hon. Finance Minister has announced that 20 lakh youth will be given skill development training in the next five years. Hon. Chairman Sir, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru *Thalapathy* M.K. Stalin has been implementing a scheme in Tamil Nadu, which provides skill development training to 15 lakh youth every year. One month wage will be given to the first timers who get jobs in the formal sector. They will first be enrolled in EPFO and only if they get a monthly salary of a minimum of Rs 15,000 and up to Rs. 1 lakh, they may become eligible for this one-month's salary to be given by the Union Government. I wish to remind you that a company can be registered with EPFO only when it has at least 20 employees on pay roll. Therefore, this Scheme will not also benefit the MSMEs. This will rather benefit bigger companies and business magnets. As much as R.3 lakh crore was allocated to the development of women, but the funds for MGNREGA have been totally stopped, which will definitely hamper the growth in the rural areas. The funds for MGNREGA have been completely blocked. You talk about Naari

Sakthi- the women power. Whether this Government has so far provided any relief assistance to the affected women in Manipur? After making big reduction in MGNREGA funds you have not even given any relief assistance to the affected women of Manipur. There is a saying which goes like this. “You read Ramayan but demolish the Vishnu temple”. I wish to point out here one thing to you. Education, employment, skill development and women’s development) … (*Interruptions*)

Sir, I am the second speaker. Just give me five more minutes. (After dismantling all the basic infrastructure, this Budget claims to give a seat at the top of a high structured building. This is just like they are giving false assurances here and there, everywhere, they do it in the Budget also. If it comes to education, are you allocating these many crores of rupees to basic education? But there are so many irregularities in the entrance exams to higher studies like question paper leak. At the height of it, you are providing grace marks, you can call it a mockery and nowhere such things can happen in the world. It has become the biggest farce of this century. It is just a mockery that you are not stopping award of grace marks rather you say you are allocating funds for educational development. That is why, I call this as a BASE Budget without any base.) It is Bihar, Andhra Pradesh, Satisfying, Elbow greasing Budget. It is BASE Budget without any base. (I wish to state about the Budget presented in the British Parliament by the then Liberal Government during 1909-10. Even today that is praised as the People’s Budget. There were increases in income-tax for the richer people in Britain and the tax revenues thus collected were to be used for implementation of social welfare schemes. This was the announcement made during that People’s Budget. This People’s Budget was prepared by the Chancellor of Exchequer Shri David Lloyd George and his friend Shri Winston Churchill who were then referred as Terrible Twins. As against this People’s Budget, this present Budget shows a step-motherly attitude towards many States of the country.)

I would like to quote our DMK Party Supremo, the founder of our Party, our *Peraringnar* Annadurai. (I want to quote some lines from his speech which he delivered as a Member of Parliament when he was in Rajya Sabha.) I quote. “What right has this government to demand more and more taxes when their performance is of such a lower order? I think that this Government, after having taxed the people so much, has not given proper returns or proper account to the nation. Therefore, though I realise that I do not have the power to stop it, I cannot abet a crime of allocating colossal sums to this insufficient, unrealistic, unresponsive and undemocratic Government that is being carried on. But whatever may be the criticism that is offered on this side, they have their numbers and their logic is based on numbers. Therefore, Mr Chairman, offering this criticism we have to go to the other forum and receive justice form only one source, the public and Mr. Chairman we are confident of getting a proper verdict”. These were the words by our great leader C.N. Annadurai. We have had a proper verdict. (Because of the right verdict of the people of Tamil Nadu, BJP which was having majority earlier was reduced to minority government now. Moreover, Tamil is a race which has a distinct character on its own. Hon Finance Minister is very well aware of Silappathigaram. If this Government betrays Tamils and Tamil Nadu, I should remind our hon. Finance Minister the lines of Poet Ilango Adigal in Silappathigaram. “Arasiyal Pizhaithorkku Aram Kootragum”. The meaning is that “those who commit injustice while ruling this country, virtue itself will turn as demon of death.” Thank you.)

(ends)

(1625-1635/VR/KN)

1626 hours

*SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): I thank our leader and honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Sri Nara Chandrababu Naidu and youth icon Nara Lokesh for giving me this opportunity to enter Parliament. People of our country believed in the ability of Shri Narendra Modi to take our country to new heights and that is the reason why they elected him for the third term and as a result we are seeing the Budget Session going on smoothly in the Parliament. I bow my head in respect for our Prime Minister. We considered this Budget, which was introduced yesterday, as a revolutionary Budget. I would like to refer to some important highlights of the Budget introduced by Smt. Nirmala Sitharaman.

Taking into consideration the financial situation of Andhra Pradesh, the Finance Minister announced Rs15,000 crore funds for the development of the capital city Amaravati. An assurance was given to complete the Polavaram project with the help from the Union Government. A special package has been announced for the development of backward regions of Rayalaseema and North Andhra Pradesh. We are happy about this announcement.

For industrial development, Kopparti node in Visakhapatnam - Chennai industrial corridor and Orvakal node in Hyderabad - Bangalore industrial corridors were announced. It was assured that all basic facilities like water, electricity and roads will be provided to these industrial nodes. For this, I would like to thank our honorable Prime Minister and the Finance Minister. It is sad that some are painting this Budget as the Andhra Pradesh - Bihar Budget. In our country every State has a capital city except Andhra Pradesh. In 2014, the honorable Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone for the capital city Amaravati. Through this House, I would like to explain the condition of the people of Andhra Pradesh. In 2014, under the leadership of then Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu 73 per cent of the Polavaram project was completed, but the previous Government

* Original in Telugu

completely neglected it. They could not even complete 3.84 per cent of the civil works. That is the reason why we are given assurance to complete the Polavaram project. That project is a lifeline for the farmers and will help Andhra Pradesh thrive. Due to the previous Government's follies, we could not complete the Polavaram project. Now under the Narendra Modi's leadership, we are sure that we will complete this project on time.

The previous Government in Andhra Pradesh has betrayed the people, in the name of three capitals. They denied the capital city Amaravati for which the foundation stone was laid by our Prime Minister. This shows how bad the administration of the previous State Government was. That is the reason why the people of Andhra Pradesh had given 93 per cent of the seats to the NDA Government in Andhra Pradesh under the leadership of Nara Chandrababu Naidu. The people of Andhra Pradesh believed in the alliance between TDP, Janasena and BJP at both the State as well as at the Central levels. In this direction, Smt. Nirmala Sitharaman had sanctioned Rs15,000 crore for Amaravati. I would like to thank her again for this gesture.

As far as the economy is concerned, Nara Chandrababu Naidu’s Government has handed over Andhra Pradesh to the previous Government with Rs.3.5 lakh crore and in the last 5 years they had borrowed Rs.13.5 lakh crore loans and destroyed our State. In 2014 when Andhra Pradesh was bifurcated there was a deficit budget of Rs.6,000 crore. Even then Nara Chandrababu Naidu recorded a 13.5 per cent growth rate in GDP. The previous Government has brought this growth rate down to nine per cent and pushed our State into bankruptcy. If we look at the per capita income between 2014 and 2019 there was a growth of nine per cent which was dropped to three per cent under the previous Government’s regime. This shows the bad governance of the previous Government and that is the reason why it is the responsibility of the Central Government to save Andhra Pradesh.

The Narendra Modi's Government has taken up an ambitious project Jal Jeevan Mission, through which every household will be provided with tap water connection. But the previous Government has misused and diverted funds meant for Jal Jeevan Mission. They could not even utilise

funds meant for Jal Jeevan Mission and deprived the people of drinking water under that scheme. Now our leader Nara Chandrababu Naidu has resolved to provide drinking water to every household. PM Aawas Yojana is another ambitious scheme of Prime Minister Shri Narendra Modi with an objective to provide houses for homeless people. Between 2014 and 2019 Shri Nara Chandrababu Naidu had constructed several houses under the PM Aawas Yojana but the previous Government neglected those houses by not providing water and electricity, thus depriving the people of those houses. Recently after taking oath as MPs, we had visited our constituencies and provided those houses with all basic facilities under the leadership of our leader Nara Chandrababu Naidu.

As far as woman empowerment is concerned, the NCRB has reported 30,000 missing cases of women in Andhra Pradesh. This reflects the condition of women under the previous Government. In yesterday's Budget, Smt. Nirmala Sitharaman has provided a lion's share for the empowerment of women. I thank the Finance Minister for taking up this step.

When it comes to employment for youth under the previous Government, we did not find even a single opportunity of employment for youth. Not even a single notification for employment was announced by the previous Government. Nara Chandrababu Naidu after forming the Government, within one month has announced 16,000 posts under the DSC. As far as the Government employees are concerned, the previous Government was not in a position to even pay their salaries. In such a scenario, we request the Union Government to save and help Andhra Pradesh. Even the SC, ST, BC sub-plan funds were diverted for the State-sponsored schemes like 'Navratna'.

Sir, now I will talk about my Parliamentary Constituency, Kurnool which is known as the most backward and drought hit region of Andhra Pradesh. I represent Kurnool Parliamentary Constituency and even today Kurnool is known for migrations. In yesterday's Budget, a special package was announced for the backward regions like Kurnool. I thank Smt. Nirmala Sitharaman for that announcement. Even after 75 years of Independence, our Kurnool does not have even a small irrigation project. As a special

package has been announced for the backward regions, I request that in Kurnool, the importance may be given to irrigation projects. Even today Kurnool is deprived of drinking water. By developing different projects like Undralla and Vedavathi we can ensure development of Kurnool. Similarly, we do not even have a single National Highway that passes through Kurnool. I request a highway between Bellary and Kurnool. We are hopeful that this Government would sanction a highway in our constituency. I believe that our State and the nation will be on the path of development under the leadership of Shri Narendra Modi ji. In Kurnool we have only one general hospital. Under the AP Reorganisation Act, an assurance was given by the Union Government to build a cancer unit in this hospital. That work was sanctioned under the Chandrababu Naidu's Government but the previous Government has left those works in the middle and neglected that project. I request that the work may be resumed at the earliest and the cancer hospital in Kurnool may be made functional.

We believe in the leadership of Shri Narendra Modi and Shri Nara Chandrababu Naidu to check the migrations from Kurnool. Let it be works related to the hospital, National Highways, youth or irrigation projects, we request that special attention should be paid to a backward region like Kurnool. I once again plead, on behalf of the people of Kurnool, to help in the development of our constituency. I once again thank you for giving me this opportunity on my own behalf and also on behalf of the people of Kurnool and Andhra Pradesh.

(ends)

1639 बजे

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक जीत पर अपने क्षेत्र की जनता, बिहार की जनता और अपने देश की जनता की तरफ से बधाई देता हूं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं अपने परम आदरणीय मुख्य मंत्री, विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और बिहार राज्य के लिए महत्वपूर्ण तथा विकासपूर्ण बजट आया है।

साथ-साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सफलतापूर्वक देश के विकास के लिए सातवां बजट पेश किया। यह बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। मैं इसका तह-ए-दिल से स्वागत करता हूं। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है तथा विभिन्न परियोजनाओं हेतु 58,600 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है।

महोदय, इस बजट में बिहार में सड़क परियोजना, विद्युत परियोजना, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि प्रदान की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है।

(1640/CS/AK)

महोदय, आज भारत 144 करोड़ से अधिक नागरिक शक्ति के साथ अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। 92 करोड़ से अधिक कार्यशील जनसंख्या (वर्किंग ऐज पॉपुलेशन) के परिश्रम एवं माथे पर बहते पसीने ने देश की अर्थव्यवस्था को 327 लाख करोड़ से अधिक का बना दिया है। 7 परसेंट से अधिक जीडीपी के विकास दर से बढ़ता भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है।

महोदय, बजट 2024-25 में बिहार राज्य में एक्सप्रेसवे और गंगा नदी पर पुल के निर्माण हेतु 26 हजार करोड़ रुपये का आबंटन आवश्यक ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व है। इस बजट में 2,14,000 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी सराहनीय है। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, इस बजट पर अपनी बात रखते हुए सरकार से यह माँग करता हूँ कि हमारे सबेया एयरफील्ड, हथुआ, गोपालगंज, जो कि 473 एकड़ में फैला हुआ है तथा यह उड़ान योजना में शामिल है और इसकी बाउन्ड्री और फेन्सिंग के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा 4 करोड़ 41 लाख रुपये का आबंटन भी हो चुका है। इसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी और रेवेन्यू फिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। वहाँ से करीब 1.5 से 2 लाख की आबादी विदेशों में रहती है और उनसे बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इसलिए मैं सरकार से यह

आग्रह करता हूँ कि इसे बजट में शामिल किया जाए और बोली की प्रक्रिया शुरू करके ऑपरेशनल एक्टिविटीज को शुरू किया जाए।

इस बजट में रेलवे के लिए भी 2.55 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आबंटन हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे के लिए कमर्शियल फिजिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए गोपालगंज के थावे जंक्शन से महानगरों के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा का प्रावधान किया जाए और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। बजट से थावे जंक्शन में पिट लाइन और यार्ड की सुविधा की जाए ताकि महानगरों के लिए हमें ट्रेन मिल सके।

महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है और साथ-साथ टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि एनएमसी से जल्द से जल्द स्वीकृति मिले और बजट भी आबंटित हो ताकि मेडिकल कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

महोदय, एनएच 27, जो कि गोल्डन क्वाड्रीलेटरल का पार्ट है और जो गोपालगंज से होते हुए बिहार के कई जिलों से गुजरता है और जो बिहार को देश के प्रमुख मेट्रो शहरों से जोड़ता है। बजट 2024-25 में मेरा सुझाव है कि बिहार में नए व्यवसाय, निवेश एवं उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रावधान हो और इस दिशा में टैक्स इग्जेम्प्शन दिया जाए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके।

महोदय, सन् 1776 में एक किताब वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई थी, जिसमें एडम स्मिथ कहते हैं कि कमाने वाला खाएगा, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय परंपराओं के अनुसार जो जन्मा है, वह खायेगा और कमाने वाला खिलायेगा। इस तरह इस बजट में बिहार कई पैमाने पर अन्य राज्यों की तुलना में प्रगति में पीछे है। अत: बिहार राज्य को और भी विशेष सहायता मिलनी चाहिए।

महोदय, वर्ष 2024-25 का यह बजट किसान, महिला, युवा और गरीब लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं के लिए अवसर प्राप्त होंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपये का आबंटन से निश्चित ही कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों को नई तकनीकी का फायदा होगा तथा सरकार गाँव-गाँव तक तकनीकी को बढ़ावा देगी।

महोदय, देश का प्रथम बजट, जो कि वर्ष 1952-53 में आया था, उस समय रेवेन्यू रिसीप्ट 404.98 करोड़ रुपये था और एक्सपेंडिचर 401.25 करोड़ रुपये था, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2025 के लिए एक्सपेंडिचर 48.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और रीसीप्ट 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है, जिसके कारण अगले साल हमारे देश का राजकोषीय घाटा भी 4.1 परसेंट से कम रहने का अनुमान है।

(1645/IND/UB)

महोदय, बजट 2024-25 में शिक्षा एवं स्किल बढ़ाने पर 4.8 लाख करोड़ का आवंटन सराहनीय है। लेकिन मैं सुझाव देते हुए प्रो महालानोबिश जो कि जेनस्ली the father of modern Indian बजट के नाम से जाने जाते है, कहते है कि it would be, however, a total mistake to establish a system of education on the model of an advanced country which has little relevance to local needs and would be beyond the means of the national economy. इसलिए education system सबके लिए एवं सस्ती होनी चाहिए।

महोदय, वर्ष 2025 के लिए प्राप्तियां (Receipts) 32.07 लाख करोड़ है। इस सम्बंध में मैं बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर साहब का दिया गया भाषण - वर्ष 1939, नाशिक की बात रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सरकार जो टैक्स के रूप में संग्रह करती है, उसका उपयोग अवश्य ही किसानों के डेब्ट्स, गरीबी को दूर करने के लिए तथा शिक्षा के लिए होना चाहिए, इसलिए महोदय मेरा यह सुझाव है कि शिक्षा हर हालत में सस्ती हो।

महोदय, बजट पर अपनी बात समाप्त करते हुए यह सुझाव देना चाहूँगा कि आज का भारत 144 करोड़ से अधिक नागरिक शक्ति का देश है। जिसके पास कृषि योग्य 156 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जो चीन से 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि से ज्यादा है। भारत का सिंचित क्षेत्र 48% है और चीन का 41% है। सकल बुआई का क्षेत्र भारत का 198 मिलियन हेक्टेयर है जबकि चीन का 166 मिलियन हेक्टेयर है। फिर भी चीन की पैदावार तीन गुना अधिक है। चीन की उत्पादकता 1767 बिलियन डॉलर की है जबकि भारत का कृषि उत्पादन मात्र 407 बिलियन डॉलर है, इसलिए कृषि का और विकास हो, इकॉनोमी का विकास हो और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहर की तरह सारी सुविधाएं मिलें। इसलिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कुछ देर पहले कहा कि यह बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। कहते हैं कि प्रेजेंट पास्ट का आइना होता है। माननीय सदस्य यह भूल गए कि इनके माननीय नेता जब रेल मंत्री थीं और उस समय रेल बजट सेप्रेट होता था, उस समय उन्होंने अपने प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स बंगाल के लिए लेकर गईं और बिहार को नेग्लेजेबल बजट दिया और आज उनकी पार्टी के नेता आज बिहार पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं और उन्हें अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए यह बात नहीं कहनी चाहिए थी।

मैं इस बजट का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1648 hours

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): The hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, introduced the Budget with the idea of the terminology used '*Vikasit Bharat*'. However, there was no feeling of Bharat in the entire Budget. The Government has failed to take the States together. The idea of 'India' has been totally shattered in this entire Budget. This Budget is a classic example of destroying cooperative federalism of our country. But I am glad that the Government took an inspiration from the 'Nyay Patra' of the Indian National Congress. This is the 'Nyay Patra' of the INC.

The Congress's promise of an internship for a yearly stipend is included in the Budget. The Congress's promise of an incentive for corporates to win tax credits for additional hiring against regular quality jobs is included in the Budget which is linked to the EPFO. The Congress's promise of Angel Tax removal is also included in the Budget. We are very glad. In 2019, when the Government came into power, Modi Sarkar had promised two crore jobs every year. By 2023-24, 10 crore jobs should have been given to young people.

(1650/SRG/RV)

But unfortunately, this has not happened. So, we expect that at least the idea that Congress gave would be implemented by this Government.

In 2019, the colleagues from BJP in this august House shouted the slogan, 'मोदी है तो मुमकिन है।' For Manipur, there is pain in our hearts. In Manipur, hundreds of people lost their lives, thousands got displaced. Our Prime Minister went to Pakistan for the birthday reception of Nawaz Sharif, the Pakistani Prime Minister, but till date, he has not gone to Manipur. … (*Interruptions*) It is a shame to the entire country. … (*Interruptions*) 'मोदी है तो मुमकिन है।'

Sir, Terminal 1 of the Delhi Airport collapsed. Roofs of the airports of Jablapur and Rajkot, inaugurated by the hon. Prime Minister

collapsed. In the State of Bihar, 14 bridges which are already in construction have also collapsed. सर, यह सब हो सकता है, 'मोदी है तो मुमकिन है।' … (*Interruptions*)

We get distressed about the terror attacks and targeted killings of Jammu and Kashmir. Later the abrogation of Article 370 happened. The truth is, earlier the attacks were in the borders, but now it has spread to the inner parts of Kashmir. The recent ones were in Reasai, Kathua, Doda and Rajouri districts of Jammu. 'मोदी है तो मुमकिन है।'

There were daily riots in North-East in 2020 when the President of the United States, Donald Trump came here to visit Delhi, the capital of our country. There were riots were in full force. 'मोदी है तो मुमकिन है।' This is an institutional attack against the minorities of this country. This is an institutional attack against the Christians and Muslims of this country. This is happening at a time where you talk about the secular fabric of this country. BJP came into power with 239 seats. When this Government came into power, they were already in the Intensive Care Unit. But with the presentation of this Budget, we clearly understand that it is not in the Intensive Care Unit, but it is surviving with the support of two ventilators in this House. The Budget clearly shows there are two ventilators. Two ventilators run this House.

Sir, there is a very critical point which none of my colleagues has noticed. The MPs from the coastal belt should understand about offshore mining. The Budget talks about the critical minerals mission. There is an announcement of offshore mining. There is no doubt that this is going to increase. There is no doubt that the mining is going to affect the lives and livelihood of lakhs and lakhs fishermen of this country. Offshore mining is going to disturb the flora and fauna. Offshore mining is going to disturb the marine wealth, environment, and the eco-system would be destroyed. There is no doubt, offshore mining is going to happen. Like the corporates have taken over the seaports, airports and telecom industry, offshore is also going to be taken over by the corporates. The

critical mineral mission is going to be an Adani-Ambani Mission … (*Interruptions*) There is no doubt. Along the biggest coastal line which spreads to Gujarat, lakhs and lakhs of fishermen are suffering. Their lives and livelihood is going to be badly affected and the corporates will take over the seashore, no doubt.

The Budget has shown clear discrimination against the State of Kerala. There is no place for Kerala in the Budget. AIIMS for which there has been a big demand was announced by the BJP Government. The people of Kerala gave a mandate for one BJP MP. The Treasury Benches gave us two Ministers, but still no AIIMS. During COVID-19, there was continuous threat of new viruses. The Government has no focus on preventive healthcare. There is no allocation for vaccination drives, public health campaigns, regular health check-ups or screenings.

(1655/RCP/GG)

We are still waiting for vaccination for the nine to 14-year-old girls, as the hon. Minister said, for giving the preventive cervical cancer vaccination to young girls. We are still waiting for that.

Kerala is facing a huge financial crisis. We have a huge financial deficit. But still the Central Government has not announced any special package. In 2018, Kerala faced the most disastrous floods in the history of the State. Certain States like Bihar, Assam, Uttarakhand and Sikkim were given flood packages. We had presented a package of Rs.8,500 crore, but no flood mitigation package was allotted by the Central Government.

In the reply given to me by the hon. Minister of Finance to a Starred Question, she clearly said that after 2015, after the UPA regime, there are no funds allocated for the coastal belt for building the seawalls or the groins in the State of Kerala. No single rupee has been allotted for building the entire seawall. No tourism package has been allocated to Kerala.

The place I come from is the Queen of the Arabian Sea, Kochi. Kochi is a place of the Kochi-Muziris Biennale. Kochi is a place of the Kochi Metro Rail. Kochi has a huge potential for tourism, heritage and culture. But in 16 square kilometres, there would not be any other place in the country where you have 21 different communities living together in harmony including the Jews. Not a single rupee has been given for heritage tourism.

The Budget has been constantly denying the youths of this country. The budget for MGNREGA has not been increased. It is remaining the same. Unemployment in the country is at its peak, particularly the rural unemployment. The Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj has given a report. Only three per cent of the workers received the unemployment allowance in the last five year because no budget for MGNREGA was kept. No action has been taken on the report.

What is the situation of our PSUs? Sushri Jothimani had asked a question. There are 36 PSUs in the process of getting sold. Ten have already been sold. The remaining are under process and they will be sold in the coming years. This is the position of the Government which has been ruling us and this is the Budget which has been announced by the Government.

सर, यह किसान विरोधी बजट है। यह युवा विरोधी बजट है। यह छात्र विरोधी बजट है। यह दलित विरोधी बजट है। यह महिला विरोधी बजट है। यह आदिवासी विरोधी बजट है। यह इस देश के शोषित, दलित, ,पीड़ित, वंचित सभी का विरोधी बजट है। I totally oppose this Budget. Thank you.

(ends)

1658 hours

SHRI C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): Mr. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the general discussion on the Budget presented by the hon. Finance Minister on 23rd July. This Budget is a roadmap in the pursuit of Viksit Bharat. This is the first Budget in hon. Prime Minister Narendra Modi ji's third term and it stands as evidence to the country's inclusive growth, sustainable development and economic resilience. This Budget is going to be a milestone Budget of Amrit Kaal.

I congratulate the hon. Finance Minister for presenting her record seventh Budget in a row. This clearly indicates how the hon. Prime Minister Narendra Modi is giving importance to empowering women. I wish her best of times to come. I am confident that the Finance Minister, under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi ji, makes India the third largest economy in the world and makes this country 'Ek Bharat, Shreshtha Bharat'.

This Budget, as the hon. Prime Minister Narendra Modi ji said, is for Viksit Bharat. This Budget ensures inclusive growth, benefits every section of society and makes this country great again. Many hon. Members have spoken about many things. I do not want to repeat them.

(1700/PS/MY)

But I only want to say that this Budget focusses on 'GYAN' - 'Garib', 'Yuva', 'Annadata', and 'Nari', with a theme focussing on employment, skilling, MSME, and the middle-class.

Hon. Chairperson, Sir, the total expenditure proposed for 2024-25 is Rs. 48.21 lakh crore. The total receipts are pegged at Rs. 32.07 lakh crore. The tax receipts are Rs. 25.83 lakh crore with a fiscal deficit of 4.9 per cent, and inflation is moving to achieve four per cent. If you look at the proposed borrowings, they are less than last year. I compliment the hon. Finance Minister who said that from 2026-27, the fiscal deficit will be on a declining path as percentage of GDP. It means availability of more money and spending more on development and welfare. This is Modi's guarantee.

Hon. Chairperson, Sir, here, I wish to submit that the Government of Andhra Pradesh has given an in-principle approval for setting up of six 1208 megawatt capacity nuclear power plant at Kovvada in Andhra Pradesh. So, I appeal to the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister to look into it and see that the nuclear power plant is set up early at Kovvada.

Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I will just touch upon briefly how Rs. 48 lakh crore is going to be spent on some of the sectors. Sir, Rs. 11.11 lakh crore is given for the capital expenditure which is 3.4 per cent of GDP; Rs. 1.5 lakh crore interest-free loans are given to the States for infrastructure development; Rs. 2 lakh crore is given for employment, skilling, etc., of 4.1 crore youth in the next five years. We are an agricultural country. Therefore, Rs. 1.5 lakh crore is given for agriculture and allied sectors. One crore farmers will be convinced to move towards natural farming. Sir, Rs. 3 lakh crore is allocated for schemes which will benefit women and girls; Rs. 2.66 lakh crore has been allocated for the rural development. As we know that India lives in its villages, so the hon. Finance Minister has allocated money for rural infrastructure. Defence is given Rs. 6.21 lakh crore. Sir, Rs. 2.62 lakh crore is allocated for the Railways, and out of that, more than Rs. 1.08 lakh crore is allocated for the railway safety. The PMAY-Urban 2.0 is given Rs. 10 lakh crore, and the assistance of the Government of India under that scheme is Rs. 2.2 lakh crore.

The Budget announced Phase IV of PMGSY to connect 25,000 more villages with roads. The limit under Mudra loans has been increased to Rs. 20

lakh from Rs. 10 lakh. It benefits the small shopkeepers, micro entrepreneurs, service-providers, etc. And the list goes on.

Now, I come to my State of Andhra Pradesh. This is a very important subject. Sir, five years of *Jungle Raj* is over. People of Andhra Pradesh have given an unprecedented mandate to the NDA. A visionary leader became the Chief Minister again with the guidance, support and helping hand of the hon. Prime Minister Narendra Modi ji. I am confident; the BJP leaders are confident; the Karyakartas are confident; and NDA is confident that Andhra Pradesh will regain its lost glory. The importance of Andhra Pradesh is reflected in this Budget. Never in the history, if I may say so, there are five paras under one heading relating to Andhra Pradesh. This clearly indicates the importance that Narendra Modi ji's Government is giving to Andhra Pradesh.

(1705/SMN/CP)

Sir, this Budget is like oxygen for Andhra Pradesh which is on ventilator because of the wrong deeds of the earlier YSRCP Government. Andhra Pradesh Chief Minister is releasing White Papers on various sectors - Power, Amaravati, Polavaram, Mines and Liquor etc. So far, five White Papers have been released and, I think, three more are going to be released in the Andhra Pradesh Assembly during the current Budget Session. These White Papers will give a clear picture of irreparable damage done by the YSRCP Government in Andhra Pradesh between 2019 and 2024.

Sir, since I have a limited time, I wish to touch upon only a few issues about my State. Now, Andhra Pradesh is handed over to the NDA Government after five years of rule by YSRCP with financial mess, economic bankruptcy, lawlessness at its hilt, rampant corruption, being termed as a mafia ruled State - be it through liquor, sand, land grabbing, etc. The former Chief Minister constructed a palace in Rishi Konda with Rs. 500 crore for himself. There was a debt of Rs. 12 lakh crore on the State. There were attacks on political opponents with nil development.

Sir, one Dalit driver was murdered and the body was door-delivered to his house by an YSRCP MLC. A doctor working in the Government hospital was brutally killed when he had asked for masks during COVID-19. He was also a Dalit. There were 2,686 murders which happened during the YSRCP regime. There were nearly 150 attacks on temples. Centuries old chariot of Lakshmi

Narasimha Swami was set on fire in Antervedi. Three silver lions of Mata Durga's silver chariot disappeared during the YSRCP regime. And, there are umpteen attacks on the temples in Andhra Pradesh by YSRCP and its goons. Attack on Dalits, OBCS, women and minorities is countless. This clearly indicates how a State would become if a person with criminal background, who had spent nearly one-and-a-half years in jail filled with vengeance against a particular group and community, becomes the Chief Minister of a State.

Sir, five crore people of Andhra Pradesh are greatly thankful to the hon. Prime Minister, Modi Ji and the hon. Finance Minister for all the proposals made in this Budget.

Sir, Amaravati and Polavaram are like two eyes of the State and the hon. Finance Minister has made announcements. Both the announcements really touched the hearts of the people of Andhra Pradesh. Some of the important proposals announced are as follows:- Rs. 15,000 crore was given for Amaravati for this year alone and the Polavaram project would be completed by the Government of India.

In the election campaign, the hon. Home Minister said in Dharmavaram that in two years, he would complete the Polavaram project. So, the Government of India is taking care of it.

Grants are given for the backward regions of Rayalaseema and the North-Coastal districts of Andhra Pradesh. Now, Prakasam district has also been added to the list.

(1710/SM/NK)

Sir, I only request the hon. Finance Minister to provide grants to these backward regions on the lines of Bundelkhand region and KBK Districts in Odisha as promised. Nearly Rs. 50,474 crore will be given to Andhra Pradesh under tax devolution. It is nearly 13 per cent higher than the last year. It is 4.047 per cent of the total amount given by the Government of India to the States.

Under the Purvodaya Plan, funds will be given to Andhra Pradesh for human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities. Funds will be given for water, power, railways, etc. Kopparthy Node on Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor will be done. Orvakal Node on Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor will also be done. Vizag steel plant has got Rs. 620 crore; Rs. 150 crore have been given to Visakhapatnam Port Trust; Indian Institute of Petroleum which is in my parliamentary constituency in Anakapalle has got Rs. 168 crore. Capital investment would be given for economic growth, and the list goes on.Sir, kindly allow me to speak in Telugu.

Under the leadership of Shri Narendra Modi, Shir Chandrababu Naidu garu and Shri Pawan Kalyan, I contested from Anakapalle seat of Andhra Pradesh for BJP. I have won with a margin of three lakh votes. Earlier, I was in the Rajya Sabha for two terms. I contested for a Lok Sabha seat for the first time and I have won with a margin of three lakh

votes. It is because the people have confidence on Shri Narendra Modi ji, Shri Chandrababu Naidu garu and Shri Pawan Kalyan.

*Jagan Mohan Reddy asked for one opportunity 5 years ago. People thought that he is a young leader and give him an opportunity. But he *… (Not recorded)* Andhra Pradesh like anything. Let it be land, let it be sand or let it be through liquor. Andhra Pradesh has been pushed to deep debt and there are many outstanding bills. I can speak about this for one more hour. We may control corruption to some extent but if an economic offender becomes chief Minister of a state we have witnessed what can happen, in the last 5 years in Andhra Pradesh. The Union government should take action on all those officials who assisted in irregularities of the previous Government and ensure that such incidents do not happen in any other state. On the basis of white papers released by the chief Minister, action should be taken and investigations should be conducted by both the state and Central Government agencies. CBI, ED and vigilance should investigate these cases and bring back the money looted by these economic offenders. That money should be spent for the development activities in Andhra Pradesh. We should find the money even if they hid that money in any other state or country. Prime Minister Narendra Modi had laid the foundation for Amaravathi in 2014 with an intention to provide the capital city for Andhra Pradesh. But later on Jagan Mohan Reddy became chief Minister and he neglected Amravati, as developing Amravati City would give a good name to Nara Chandrababu Naidu and Narendra Modi. Amravati is a government property but still it was destroyed by Jagan Mohan Reddy. For the first time farmers pooled in 50,000 acres of land to construct a capital city in Amravati. Even those formers were subjected to harassment, as a result people of Andhra Pradesh have given a decisive mandate with 93% strike rate. No where in the country did such election results were seen, even now, they failed to learn from their failures. Though he killed his paternal uncle, he is visiting Delhi for protests. A new government in Andhra Pradesh was formed only 40 days back. People are watching his actions. The government should take action against him and recover the money that he looted from Andhra Pradesh. Enquiry should be conducted and all those officials who are found guilty should be punished. I witnessed 12 budgets in the Rajya Sabha, this is the 13th budget and till now I never saw such benefits for the state of Andhra Pradesh. On behalf of the people of Andhra Pradesh and NDA I thank the honorable Prime Minister and Finance Minister for this budget. Thank you.

(ends)

---

*Original in Telugu

(1715/SK/RP)

1716 बजे

श्री राजीव राय (घोसी) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अगर आप इस बजट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यह बजट कुछ और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों, झूठी बातें और जुमलों का चीख-चीखकर आईना दिखाने वाला बजट है। सरकार की गजब कहानी है कि पिछले दस सालों से दो करोड़ रोजगार और नौकरियां हर साल दे रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि तीन-चार साल में आठ करोड़ नौकरियां और रोजगार दे दिए गए हैं। कमाल की बात है कि 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन वर्षों से दे रहे हैं, यह आंकड़ा 79 करोड़ 99 लाख 999 अभी तक नहीं हुआ, वह 80 करोड़ ही है, दोनों आंकड़े एक साथ कैसे आ सकते हैं? इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। जिस सरकार के काल में 80 करोड़ लोग पांच किलो राशन पर सालों साल जिंदा रहें और सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ और नहीं हो सकती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी।

तुमने कोशिश ही की नहीं ये हालात बदल सकते थे,
तुम्हारे अश्क मेरी आंखों से भी निकल सकते थे,
तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह
दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।

आप देश में झील के पानी की तरह एक जगह ठहरे हुए हो। जब मैं माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण सुन रहा था और पुस्तिका पढ़ रहा था तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं यह बजट बिहार के वित्त मंत्री जी से सुन रहा हूं। … (व्यवधान) सुधाकर बाबू, आप खुश मत हों कि बिहार के लोगों को बहुत कुछ मिल गया। आपको याद होगा, भाइयो और बहनों, 70 हजार करोड़, 80 हजार करोड़, 90 हजार करोड़, एक लाख करोड़ और सवा लाख करोड़, सवा लाख करोड़ रुपये कहां गए? यह रुपया या तो गया नहीं, अगर गया तो सारे पुल गिर गए।

माननीय सभापति जी, मैं दो बातों को लेकर बहुत चिंतित हूं। एक, मैं सरकार के उस महान् सलाहकार के बारे में जानना चाहता हूं जिन्होंने पूर्वोदय योजना को बिहार से शुरू किया। इसमें पूर्वांचल कहां गया? शेरशाह सूरी जी ने कहा था और चंदौली उस जमाने में गेटवे ऑफ पूर्वी उत्तर प्रदेश था और आप पूर्वांचल को छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हार के

बाद इतनी नफरत कि आपने उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, जबकि मैं आंकड़ों के साथ आईना दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से साथियों ने आंकड़े पेश किए हैं, सरकार को भी यह सब समझ में आता है, लेकिन आप पूर्वांचल को छोड़ देंगे और पूर्वोदय योजना की बात करेंगे। आपने बजट भाषण में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। आपका बोरी-बिस्तर पूर्वांचल ने बांध दिया है, इंतजाम कर दिया है। अगर इसी तरह की नफरत दिखाते रहेंगे तो आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश से बोरी-बिस्तर बांध दिया जाएगा, यह लिखकर रख लीजिए और आप किसी घमंड या अहंकार में मत रहिए।

मैं मांग करता हूं कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को पूर्वोदय योजना में शामिल किया जाए। आपने मेरे लोकसभा क्षेत्र में 11 सालों के शासन में कुछ भी नहीं दिया।

(1720/MK/NKL)

हमारे यहां तीन स्वदेशी कॉटन मिलें हैं। परदाहा और रसड़ा की चीनी मिल वर्षों से बंद है। माननीय कपड़ा मंत्री जी और वहां के मुख्यमंत्री जी ने आज से 7 साल पहले उसको चलाने की घोषणा की थी। एक जगह 85 एकड़ जमीन है, एक जगह 25 एकड़ जमीन है, जिन पर लैंड माफिया की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। मैंने सुना है कि वहां पार्टिंग करने की योजना बनाई जा रही है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बजट में मेरी लोक सभा की तीनों मिलों को चालू किया जाए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। अगर किसी भी वजह से मिलों को उस हालत में चालू करना संभव नहीं हो तो वहां वैकल्पिक उद्योग लगाया जाए। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका घोसी है।

आप बाढ़ की बात कर रहे हैं। मुझे वह भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-से वैज्ञानिक ने बताया है कि इनके यहां बक्सर में बाढ़ आएगी तो मेरे गाँव बलिया में बाढ़ नहीं आएगी। यहां पूर्वांचल के सांसद बैठे हुए हैं। मैं तो पीलीभीत से जुड़ता हूं। कौन-सा ऐसा जिला है, जहां बाढ़ नहीं आती है? मेरे यहां मधुबन ब्लॉक का बिनटोलिया से लेकर गजियापुर का पूरा बांध टूट रहा है। गाजीपुर, सेमरा गाँव सालों से डूब रहा है। बक्सर से लेकर वहां तक सारे गाँव डूब रहे हैं। सैंकड़ों एकड़ जमीन चली जा रही है। सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही है। जब बजट को पढ़ते हैं तो ऐसा अहसास होता है कि यह बजट देश के लिए नहीं, बल्कि अपनी उन दो बैसाखियों के लिए बनाया गया है, जिन बैसाखियों के सहारे यह सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और चलेगी नहीं।

सभापति महोदय, एक करोड़ इंटर्नशिप की बात हो रही है। जो लोग दो करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, वे एक करोड़ के इंटर्नशिप पर आ गए हैं। वह भी एक इमैजिनरी फिगर है, छलावा है, झूठ है। आप 500 कंपनियों में नहीं दे सकते हैं। आप अग्निवीर से भी

ज्यादा खतरनाक योजना नौजवानों के लिए ला रहे हैं, जो एक साल में उनको सड़क पर खड़ा कर देंगी। आप तो नौकरी और रोजगार की बात करते थे। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे पूर्वांचल के इलाके को पूर्वोदय योजना में शामिल किया जाए। हमारे यहां जो परदाहा की मिल है, उसमें 85 एकड़ जमीन है। आप वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं। हमारा मऊ तो पूर्वांचल का मेडिकल हब बन रहा है, लेकिन सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। वह प्राइवेट के जिम्मे है। अगर वहां मल्टी स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, स्किल सेंटर, वह बुनकरों का इलाका है, इसलिए वहां साड़ी प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाए। हमारे मऊ की हालत बहुत बुरी तरह खराब है।

मैं आपसे मांग करता हूं कि यह सरकार, जो नौकरी के वादे करती थी, जिन्होंने बार-बार कहा है कि हम हर साल दो करोड़ नौकरी और रोजगार लेकर आए हैं, इस सदन के लोगों को पता होना चाहिए कि नौकरी और रोजगार किस बोरे में रखकर किस खाई में फेंक दी गयी है, जो न तो पढ़ी जा रही है और न ही दिखाई दे रही है। आप झूठे दावे बंद कीजिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप झूठे वादे करते हैं। आप बजट में हर साल बातें करते हैं, लेकिन पिछली बजट की बात नहीं होती है। वे पैसे कहां गए?

"आप अपनी बातों से इस आवाम पर कुछ इस तरह अहसान करते हैं,
आँखें तो छीन लेते हैं, और चश्मे दान करते हैं"

हमें आपके दान के चश्मे नहीं चाहिए। आप हमारी आँखों को छिनना बंद कर दीजिए। अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां, जो मेरा इलाका है, मैं हमेशा कहता हूं, बदहाल बुनकर, बेहाल किसान और बेरोजगार नौजवान, इन पर सरकार तत्काल संज्ञान ले और जो गाँव कटानों में डूब रहे हैं, चाहे वह गाजीपुर का गाँव हो, बलिया का हो, मऊ का हो, आजमगढ़ का हो, गोरखपुर का हो या कुशीनगर हो, उसके लिए व्यवस्था कर दी जाए। जितने गाँव डूब गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। आपने मुझे समय दिया, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थीं, लेकिन समय के अभाव में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन, मुझे उम्मीद है कि सरकार संवेदना के साथ सुनेगी, समझेगी और हमें भी आगे बढ़ने का मौका देगी । धन्यवाद।

(इति)

1724 बजे

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो वित्त संकल्प अपने सामने रखा है, उसके ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। खासकर, उन्होंने जो चार बातें कही थीं, युवा, महिला, किसान, इन विषयों को लेकर मैंने सोचा कि पहली बार जब उन्होंने बेरोजगारों की बात की, कुछ स्कीम भी लेकर आई हैं, उसके ऊपर पहली बात यह है कि उसकी जो नींव है, उसको पहले समझना चाहिए।

(1725/SJN/VR)

सर, आज हमारे पास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने हमारे सामने जो वास्तविकता रखी है, Unemployment ratio rises to 9.2 per cent in June 2024. हमारे यहां 9.2 प्रतिशत बेरोजगारी है। उस पर उन्होंने ये कहा है कि अगर रुरल रोजगार का रेट देखेंगे, तो वह 9.3 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) ने कहा है कि हमारे यहां 83 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में आप यहां पर जो बजट रख रहे हैं, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं?

अगर उसका सबसे ज्यादा किसी पर असर पड़ता है, तो युवा, महिला और किसानों पर पड़ता है। हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। अब युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। अगर आप देखेंगे, तो सरकार पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे करती है। वह कहती है कि उनका प्रतिशत निकालने का जो रवैया या जो तरीका है, वह गलत है। वह कहते हैं कि सिर्फ 5.2 प्रतिशत है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में अर्बन एरियाज़ में बेरोजगारी दर के बारे में बताया है। रुरल एरियाज़ में वर्ष 2020-21 में 3.3 प्रतिशत और अर्बन एरियाज़ में 6.7 प्रतिशत है।

हमारे पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। Unemployment rate on usual status of persons aged 15 years and above in both rural and urban area along with last three years is 3.3 per cent to 6.7 per cent. In respect of rural areas in 2021-22, it was 3.2 per cent and in respect of urban areas in the same period, it is was 6.3 per cent; and the same in 2022-23 was 2.4 per cent and 5.4 per cent respectively.

अभी उसका इंडिकेटर क्या है। जब आईएलओ कहती है कि इतने प्रतिशत है। इस तरह की रिपोर्ट देकर वे हमारे देश में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, share of educated youths among all unemployed people also increased 11.5 per cent from 54.2 per cent in 2000 to 65.7 per cent in 2022. अगर आप देखेंगे, तो इतने युवा बेरोजगार हैं। मैंने जान-बूझकर पहले इसकी नींव रखी है। हम क्या करना चाहते हैं? आप कौन-सी स्कीम लेकर आए हैं? जब आप सारी स्कीम्स देखेंगे, तो उसमें आपको यह नजर आएगा।

पहले बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालय में जाता था और अपना नाम रजिस्टर करवाता था। तब हमारे पास रियल डेटा आता था। अब हम ईपीएफओ के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो इम्प्लॉयी

प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके आधार पर तय करते हैं कि इतने लोग बेरोजगार हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी ईपीएफओ होता है। ये कहेंगे कि हमने रोजगार दिया है। मेरा रोजगार शब्द पर ऑब्जेक्शन है। नौकरी की बात करो, रोजगार की बात मत करो।

अभी भी आप अपनी स्कीम में कह रहे हैं, वे जो स्कीम लेकर आए हैं, अगर आप उस स्कीम में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। जो स्कीम्स लाई गई हैं, कुल चार स्कीम्स हैं, कंपनियों में कैसे अप्रेंटिसशिप पर रखेंगे, उनको क्या-क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर आप इन सभी में देखेंगे, तो हर स्कीम दो वर्ष की है। ये तो अग्निवीर योजना हो गई। वह दो वर्ष के बाद क्या करेगा? आप क्या देने वाले हैं? एक लाख रुपये महीना देंगे। एक व्यक्ति जिसकी प्रतिमाह एक लाख रुपये तन्ख्वाह है, उसको 15,000 रुपये देंगे।

मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको क्यों देना है? वह तो प्रतिमाह 1,00,000 रुपये तन्ख्वाह ले रहा है। उसको क्यों देना है? उसको 5-5,000 रुपये करके तीन महीने में 15,000 रुपये देंगे। अगर कोई एक वर्ष के बाद नौकरी छोड़कर चला गया, तब क्या करेंगे? तब कंपनी से पैसे लेंगे, यानी सरकार की निधि से कुछ नहीं जा रहा है। जिम्मेवारी भी नहीं है, बाकी सब सीएसआर फंड से होगा। इन सारी चीजों को देखेंगे, तो आप जो ये सब कर रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सही में बेरोजगारी को खत्म करना है या नहीं करना है।

(1730/SPS/SAN)

आप बेरोजगारी पर सोचिए। मैं ट्रेड यूनियन में काम करता हूं और अनिल देसाई भी मेरे साथ वहीं काम करते हैं। नौकरी कहां आई हैं? आपने कहा 500 कंपनियां हैं, लेकिन कंपनियां कहां हैं, यह तो बताइए? आप नौकरी कहां लगवाने वाले हो? मुंबई जैसे शहर में सब गए हैं। हमारे महाराष्ट्र में से सारी चीजों को लूटकर ले गए। वहां से वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरवेज गई, बल्क ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया। सारे कारखाने और उद्योगों को आप गुजरात लेकर चले गए। रोजगार कहां हैं? वहां कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं, आप यह तो बताइए? आप रोजगार कहां देने वाले हैं? यह बुनियादी सवाल है। आप यह कीजिए, तब आप कहिए। मैंने इसलिए कहा है कि यह कुछ नहीं है, यह अग्निवीर है।

सर, मैं आगे आपको बताता हूं कि आपने सारे पब्लिक सेक्टर बेच डाले। नौकरियां कहां है? पढ़े-लिखे बच्चे कहां जाएंगे? दसवीं और बारहवीं कक्षा की मेरे पास रिपोर्ट है। आप उस रिपोर्ट में देखेंगे कि जो कम पढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी संख्या से दसवीं या बारहवीं कक्षा पास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और ग्रेजुएट वालों की संख्या है। क्या आप उनको बैंकों में लेने वाले हैं? आप किसी भी बैंक में जाकर देखिए, वहां अंधेरा छाया हुआ है। अभी एआई आएगा तो और भी तकलीफ आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप देश की आबादी के बारे में सोचिए। 140 करोड़ लोगों में कितने लोग बेरोजगार हैं। आप कहते हो कि चार करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, लेकिन दो वर्ष के बाद क्या वह अग्निवीर बनेगा, यह पता नहीं चल रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट, ऑयल आपने सारी कंपनियां बर्बाद कर दी हैं।

सर, मैं हाल ही में जर्नी कर रहा था तो रेल में मुझे दो कर्मचारी मिले। मैंने कहा कि क्या करते हो, एक ने कहा कि मैं जेनरेटर ऑपरेटर हूं, दूसरे ने कहा कि मैं हाउस कीपिंग करता हूं। उसने कहा कि जब मैं नौकरी पर लगा था तो उस वक्त मुझे 45 हजार रुपये तनख्वाह मिली थी। दो वर्ष के बाद वेंडर चेंज हुआ, मेरी तनख्वाह सीधे 16 हजार रुपये हो गई। उसके बाद फिर दो वर्ष के बाद नया वेंडर आया तो मेरी तनख्वाह 18 हजार रुपये हो गई है। अब एक और नया वेंडर आया गया है तो तनख्वाह 24 हजार रुपये हो गई है। सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। हम यहां पार्लियामेंट में बैठे हैं। … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) यहां सीआईएसएफ है। हमारी इनसे दुश्मनी नहीं है, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हमें यह समझने तो दीजिए। अभी सारा काम बीवीजी करता है। राष्ट्रपति भवन में बीवीजी है, पार्लियामेंट की सफाई बीवीजी करता है, लेकिन … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) आप सीआईएसएफ को लगाना है तो चौराहे पर लगा दीजिए, अंदर क्या है? … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) मोदी साहब है तो मुमकिन है। … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

सर, मद्रास की नोकिया कंपनी एक दिन में मन में आया बंद कर दी। वे 40 हजार लोग कहां जाएंगे, यह नहीं पता है। हम नया बता रहे हैं, लेकिन जो बंद हो रहा है, वह कौन बताएगा? आज हमारी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हिकल आ गए हैं। हमारी जो पुरानी पेट्रोल और डीजल इंजन के जो व्हिकल थे, उनके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हिकल में मूविंग पार्ट्स नहीं है। उनमें मूविंग पार्ट्स होने की वजह से एन्सिलरीज कंपनियां होती थीं, लेकिन आज सारी एन्सिलरीज कंपनियां बंद पड़ी हैं। कोल्हापुर की एन्सिलरीज कंपनियां बंद पड़ी हैं। वहां लोग बेरोजगार हो गए है और उम्र 40-45 साल हो गई है। रोजगार कहां हैं? मैं आपके रोजगार शब्द को देखता हूं कि रोजगार कहां हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौन सी नौकरियां देते हो? इस देश में रोजगार करने वालों के लिए, नौकरी करने वाले के लिए, काम करने वाले के लिए, मजदूरों के लिए हमने क्या कानून बनाए हैं? हमने यह कानून बनाया है कि जिस कंपनी में 300 और 300 से कम कर्मचारी हों, अगर कंपनी का मालिक चाहता है कि उसे बंद करना है तो उसको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, वह बंद करेगा।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : कृपया, अपनी बात कन्क्लूड कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, उसकी मर्जी है और कहेगा कि मेरी मर्जी। उसके बावजूद हमारे टर्म्स क्या हैं? उसमें कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स टर्म हैं। कैजुअल क्या होता है, कैजुअल का मतलब है कि एक दिन का काम करवाया, फिर छोड़ दिया। हमारे नेवल डॉक में देखिए क्या है? मुझे पिछले हफ्ते लोग मिलने आए थे, उनकी 25 वर्ष तक कैजुअल एम्प्लॉई की लगातार सर्विस हो गई, उसमें ब्रेक नहीं है।

(1735/MM/SNT)
यह क्या तरीका है? मैंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, मैंने वेस्टर्न कमांड को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या हुआ सर! पत्र लिखने के बाद इमिडिएटली वेस्टर्न कमांड सतर्क हुआ और उन्होंने सोचा कि हम जल्दी से जल्दी वेंडर बुलाएंगे। इसको थर्ड पार्टी को दे देंगे। 25-25 साल से नौकरी करने वाले लोगों को आप वेंडर के पास भेजोगे! आपकी जिम्मेदारी छूट गयी। मर जाओ, किधर भी जाओ। मझगांव डाक में फिक्स्ड टर्म इम्प्लॉयी को दो-दो बरस लगते हैं और अब फिर से फिक्स्ड टर्म में लग गए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please conclude.

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, अभी तो मुझे बोलते हुए 5-7 मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूं। अभी तक आप सारे राजनीतिक भाषण सुनते आए हैं। मैं उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं जान-बूझकर नहीं बोल रहा हूं।

दो वर्ष का फिक्स्ड टर्म रखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपको दो वर्ष के लिए फिक्स्ड टर्म पर रखा था और आपको 25 हजार रुपये तनख्वाह दे रहे थे। अब, नया वेंडर आ गया है। इम्प्लॉयी और इम्प्लॉयर फिर से फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वे कहेंगे कि पिछली बार 25 हजार रुपये दिए थे, अब नहीं दे पाएंगे। अगर 20 हजार रुपये में करना है तो करो, नहीं तो जाओ। सात-सात बार फिक्स्ड टर्म पर मझगांव डॉक, गवर्नमेंट पीएसयूज़ में लोग 14-14 साल से काम कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, मैं नाम लेकर जान-बूझकर बोल रहा हूं। लोग दस-दस साल से काम कर रहे हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? तनख्वाह बढ़ाने के लिए वेंडर को बोलो तो वह कहता है कि मैं तनख्वाह बढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन बैंक मुझे नहीं दे रही है। हजारों कर्मचारियों का यही हाल है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री अरुण भारती जी।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं...
(व्यवधान) सर, इतना महत्वपूर्ण विषय है। बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे दिए गए हैं। मैं बीएसी कमेटी का भी सदस्य हूं। ... (व्यवधान)

श्री अरुण भारती (जमुई) : धन्यवाद सभापति जी। सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : हम से कम संख्या वालों को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया गया है... (व्यवधान)

श्री अरुण भारती (जमुई) : सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे बोलने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाएगा।... (व्यवधान) सर, सबसे पहले मैं जमुई की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पहली बार मुझ पर और तीसरी बार मेरी पार्टी पर विश्वास करके मुझे भारत की संसद में भेजा है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए, आपको बोलने के लिए समय मिलेगा।

... (व्यवधान)

श्री अरुण भारती (जमुई) : बड़े गर्व और जिम्मेदारी के साथ बजट पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने का मुझे जो मौका मिला है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देता हूं... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सर, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सांसद हैं, इनको बोलने का दो मिनट का समय दे दीजिए।… (व्यवधान)

श्री अरुण भारती (जमुई) : महोदय, मैं बिहार से आता हूं जो कि भगवान जैन, भगवान बुद्ध, माता सीता, गुरू गोविंद सिंह जी, आचार्य चाणक्य… (व्यवधान) सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं, कृपया मुझे बोलने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हो, यह बहुत जरूरी है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा। अभी आप बैठ जाइए।

अरविंद सावंत जी, आप कृपया अपनी बात एक मिनट में कनक्लूड कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, इसमें सारी बातें हैं। आपने अभी नीट परीक्षा की बात सुनी। यूपीएससी, हमारे यहां खेडकर नाम की महिला पकड़ी गयी है। आप एमपीएससी देख लीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन के तहत मुंबई में इंकम टैक्स में 1200 लोगों की भर्ती हुई। 1200 में केवल तीन महाराष्ट्र से हैं, बाकी कहां से आए? स्टाफ सिलेक्शन कमिशन के एग्ज़ाम्स की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, इसकी जांच कीजिए। किसी प्रांत से हमारी दुश्मनी नहीं है। पूरे भारत वर्ष से नहीं, केवल दो राज्य से सारे लोग आ गए। यह कमाल की बात है। मैं इसकी जांच करने की मांग करता हूं।

आखिर में, मैं दो मुद्दे यहां रखना चाहता हूं। एनसीएलटी में कितने केसेस पड़े हैं, इसका आपने जिक्र किया है। जेट एयरवेज़ के बारे में एनसीएलटी में भी कह दिया है कि उनकी ग्रेच्यूटी और पीएफ दे दो, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। मुंबई में हयात रिजेंसी होटल बंद पड़ा हुआ है। लोग 30-30 साल सर्विस करने के बाद बेकार हो रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन मुद्दों को लेकर अगर सरकार युवाओं की बेरोजगारी की बात करती है तो मुझे यही बताना है। एक मुद्दा और आता है और वह है पेंशन। दस बरस से लड़ रहा हूं। ईपीएस पेंशन, 95 में 800-1200 रुपये मिलते हैं।

(1740/YSH/AK)

सर, उनसे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इसलिए मैं आपसे महाराष्ट्र के तीन मुद्दों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पहला मुद्दा छत्रपति शिवाजी महाराज का है। ये महाराष्ट्र में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद भाजपा के साथ और हमने वही छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पर खड़ा करने के लिए कहा तो रेलवे के चेयरमैन कहते हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी नहीं है तो सरदार वल्लभभाई पटेल जी का स्टैच्यू कैसे लग गया? विश्वेश्वरैया जी का स्टैच्यू कैसे लग गया? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू लगाने के लिए पॉलिसी नहीं है? आपकी लैंड पॉलिसी भी अब तक खराब रही है।

दूसरा, मराठी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू लगाया जाए। इसके अलावा आज हम देश में जो रेल घुमा रहे हैं, वह पहली रेल इस देश में नाना शंकरसेठ द्वारा लाई गई थी। मुम्बई सेन्ट्रल स्टेशन उनके नाम पर हो, इसकी मांग मैं पिछले 10 वर्षों से करता आ रहा हूँ। इस पर सरकार थोड़ा सा आगे बढ़ी है, लेकिन वह काम अब भी नहीं हुआ है। मेरी इतनी सी ही प्रार्थना है कि आप इन कामों को कीजिए और तब जाकर आप बजट की बात कीजिए, नहीं तो बाकी सब बेकार है।

(इति)

1741 बजे

श्री अरुण भारती (जमुई) : सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे बोलने का पर्याप्त मौका दिया जाए। सभापति जी, आज बजट की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करता हूँ, जिनको तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र जमुई की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर पहली बार और हमारी पार्टी पर तीसरी बार अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुझे बड़े गर्व और जिम्मेदारी के साथ बजट पर अपनी पार्टी का जो रुख और पक्ष रखने का मौका मिला है, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सभापति जी, मैं बिहार से आता हूँ, जो भगवान जैन, भगवान बुद्ध, माता सीता, गुरु गोविन्द सिंह जी, आचार्य चाणक्य, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी और स्वर्गीय रामविलास पासवास जी की भूमि है। बिहार, जो संस्कृति, कला और ज्ञान की नगरी थी, जहां अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, वही बिहार हर स्तर पर आज के दिन चुनौतियों से लड़ रहा है। इसका कारण पूर्व की केन्द्र सरकारों का बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है। बिहार को मुख्य धारा से वंचित रखने का उनका जो षड़यंत्र था, जो कि कांग्रेस सरकार ने केन्द्र में किया था और फिर जंगलराज की सोच वाली आरजेडी की सरकार थी। उनके शासनों ने बिहार को कम से कम दो दशक पीछे धकेल दिया था। इस बात को मैं एक शायरी के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ।

"ये मंजर भी देखा है तारीख की नजरों ने
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है।"

उनकी गलतियों की कीमत आज पूरा बिहार भुगत रहा है और उन्हीं गलतियों को अगर सुधारकर बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का काम इस बजट ने किया है तो यह बहुत सराहनीय है। विपक्ष के साथी बहुत असहज महसूस करते हैं कि बिहार पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई।

सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि बिहार ने तो कभी प्रश्न नहीं किया कि बजट में अन्य राज्य की सरकारों को क्या सौगात मिली। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2021 के बजट में केन्द्र सरकार ने 25 हजार करोड़ का इकोनॉमिक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल को दिया था।

1 लाख करोड़ रुपये से 1100 किलोमीटर के राजमार्ग की राशि केरल को दी गई थी, जहां पर एनडीए की सरकार नहीं थी, लेकिन जब बिहार को इस बजट में कुछ दिया जा रहा है तो आपत्ति हो रही है। यह आपत्ति किसलिए है, यह हमारी भी समझ से बाहर है। जो कमजोर राज्य होते हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है कि यह बजट एक समावेशी बजट है, न्यायोचित बजट है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में न्यायसंगत बजट है और इसकी जरूरत बिहार को कई दशकों से थी। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। हमें हर बार उलाहना दी जाती है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन ऐसे पिछड़े राज्य को आगे लाने के लिए विकास की राह में अगर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो यह बहुत सराहनीय योगदान है।

(1745/RAJ/UB)

क्या आप नहीं चाहेंगे कि बिहार भी विकसित हो, बिहार के लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिले? यह बजट न केवल विकसित भारत की सोच को आगे ले जाने का काम करता है, बल्कि हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी के विकसित बिहार बनाने की सोच, 'बिहार फर्स्ट – बिहारी फर्स्ट' को साकार करने की तरफ एक सकारात्मक कदम है, उस सोच को धरातल पर उतारने की पहल भी है।

मैं नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने इस बजट में बिहार को जो प्राथमिकता दी है, हम जिस 'बिहार फर्स्ट – बिहारी फर्स्ट' सोच की बात करते हैं, हमें उसका अंश इस बजट में दिख रहा है। अब हमारे बिहार में गंगा माता के साथ विकास की गंगा भी बहेगी, क्योंकि केन्द्र सरकार ने बिहार के साथ न्याय किया है। बिहार को उसका जो लंबे समय से पेंडिंग था, वह अधिकार दिया है।

बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद वर्ष 2024 में माननीय प्रधान मंत्री जी को दिया था, उस भरोसे पर वे पहले बजट में ही खरे उतरे हैं। मोदी जी ने हमेशा बिहार के विकास की चिंता की है। उन्होंने विश्व पटल पर बिहार को सम्मान दिया है। जी-20 समिट में नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र पूरे विश्व ने देखा था। एनडीए की सरकार ने बिहार के साथ सामाजिक न्याय किया, जब स्व. कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। हमें इस बजट के माध्यम से आर्थिक न्याय दिया गया। बिहार को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। सरकार ने पूर्वोदय योजना की घोषणा की है, जिससे बिहार के ऑल राउंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जेनरेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपर्चूनिटी के माध्यम से बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे।

सभापति महोदय, क्या-क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा लेकिन मैं थोड़ा बीते हुए समय के बारे में बताना चाहूंगा। लगभग दो दशक पहले बिहार के एक तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जिनके बारे में बिहार में एक कहानी चलती है कि जब वहां की जनता उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमें सड़क की जरूरत है तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अच्छा है, तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है, क्योंकि जब तुम अपराध करोगे और तुम्हारे गांव में सड़क होगी, तो पुलिस तुम को पकड़ने, गिरफ्तार करने के लिए आ जाएगी।…(व्यवधान) अगर वहां रोड नहीं होगा, तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने कैसे आएगी?…(व्यवधान)

जिस प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यह सोच थी, अब वहां पर इस बजट के माध्यम से एक्सप्रेस वे बनेंगे, गंगा नदी पर नए पुल बनेंगे।…(व्यवधान) सवाल करने वाले कहां थे?… (व्यवधान) जिस वक्त हमें एक्सप्रेस-वे की जरूरत थी, तो सवाल करने वाले कहां थे?… (व्यवधान) ऐसे बेहतर एक्सप्रेस-वे से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जाएगा, व्यापार सुगम बनेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ेगा, जो हमारे 'बिहार फर्स्ट – बिहारी फर्स्ट' की सोच को भी साकार करता है।

सभापति महोदय, मैं इस बजट के माध्यम से 26 हजार करोड़ के रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की घोषणा के लिए सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। इस बजट में पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेस वे, बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेस वे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क योजना से जोड़े जाएंगे। गंगा नदी में एडिशनल दो लेन्स का ब्रिज बनेगा, वह शामिल है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कुछ ऐसा कहने वाला हूं, जहां थोड़ी-सी आपत्ति आएगी। मेरे लोक सभा क्षेत्र जमुई में चुनाव के वक्त जंगल राज की सोच वाले जो विपक्षी थे, उन्होंने मुझे बार-बार बाहरी कहा।

(1750/KN/SRG)

उन्होंने बोला- यह तो बाहरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहारियों को बाहरी किसने बनाया? किसने उनको तिरस्कृत होने के लिए बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह शिक्षा हो या फिर जान-माल की इफाजत हो? ये बताएं।

महोदय, दशकों बाद ऐसा बजट आया है, जिसमें रोजगार के अपार अवसर बनेंगे। चाहे वह रोजगार के लिए प्रधान मंत्री जी के पांच योजनाओं के पैकेज के माध्यम से हो या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, जैसे कि 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट हो। बिहार में एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स हों, नए एयरपोर्ट्स हों, खेलकूद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात हो, तो यह उम्मीद जगती है कि अब हम बिहारी भी वापस बिहार जाने के बारे में सोच सकते हैं, ताकि हम बिहारी ही कहलाएं, बाहरी नहीं कहलाएं।

महोदय, सरकार द्वारा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 21400 करोड़ की लागत से नया पावर प्लांट पीरपैंती में बनाया जाएगा। नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेज बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। केन्द्र सरकार ने जो सौगात दी है, कैपिटल इनवैस्टमेंट से एडिशनल एलोकेशन को जो सपोर्ट मिलेगा, उसका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। बिहार जैसे राज्य में विकास के लिए अधिक बजट की जरूरत है, जिसके लिए बिहार सरकार द्वारा एक्सटरनल असिस्टेंस फ्रॉम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

Sir, the data shows that Bihar alone accounts for 17.2 percent of the flood-prone areas in India. In recent decades, the flood intensity has increased and so has the extent of flood-prone areas.

महोदय, बिहार में बाढ़ और सूखाड़ का एक ऐसा चोली-दामन का साथ है, जो हमारे नियंत्रण में न होते हुए भी एक बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजाओं के लिए जो 11500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, यह हमारे लिए एक बहुत ही राहत भरा कदम है। कोसी-मेची राज्य लिंक और अन्य सिंचाई परियोजनाएं हमारे किसानों की आजीविका की सुरक्षा और कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मैं सरकार का विशेष अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने बाढ़ के विषय में एक निर्णायक कदम लिया है। वित्त मंत्री जी ने भाषण में यह भी बताया कि किस प्रकार बिहार में बाढ़ नेपाल के कारण आती है। बिहार को एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के माध्यम से 11500 करोड़ रुपये का आवंटन दिया जाएगा, जिससे कोसी-मेची इंटर-स्टेट लिंक and 20 other ongoing and new schemes including barrages, river pollution abatement and the irrigation projects के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा… (व्यवधान)

सर, मुझे थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त सर्वे एंड इनवैस्टिगेशन ऑफ कोसी रिलेटिड फ्लड मिटिगेशन तथा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी उसमें लिए गए हैं। बाढ़ के कारण बिहार में सिर्फ जान और माल का नुकसान ही नहीं होता है, बल्कि रेवेन्यू का भी लॉस होता है। क्योंकि जो बजट प्रदेश में विकास कार्यों में प्रयोग हो सकता है, उसका प्रयोग सरकार मुआवजा देने में करती है। फ्लड कंट्रोलिंग और इंटरलिंकिंग के माध्यम से न सिर्फ बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि हम विकास कार्यों के लिए बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट भी कर सकेंगे।

महोदय, हमारा बिहार जो तत्कालीन मुख्य मंत्री के राज में जंगल राज, संगठित अपराध के लिए जाना जाता था, अब पर्यटन के मामले में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाएगा। राजगीर और नालंदा की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन को लेकर हमारी पार्टी की सोच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी साकार करने का काम किया जाएगा।

(1755/VB/RCP)

बिहार राज्य में भारत की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाने वाले कई स्थान हैं, लेकिन पूर्व की किसी भी सरकार ने बिहार में पर्यटन को प्रमोट करने की बात नहीं की। मुझे गर्व है कि यह सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ में लेकर चल रही है।

इस बजट में बिहार के लिए हर क्षेत्र में घोषणा करके सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि इंडिया जैसे इंडिया जैसे फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री में प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी और जस्टिस भी शामिल है और बिहार को अपेक्षा, जो इतने दिनों से की गई थी, मोदी जी की सरकार में उन सपनों को पूरा किया गया है।

विपक्ष के साथी पूछते हैं कि बिहार में का बा? तो, मैं उनको बताना चाहूंगा कि बिहार में अब बहार बा, बढ़त रोज़गार और व्यापर बा, विकसित होत जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर और कटिहार बा, बजट में परियोजना के बौछार बा, जिसे देखके विपक्ष अब लाचार बा, क्योंकि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी**) :** थैंक यू।

श्री अरुण भारती (जमुई) : सर, मुझे अपनी बात कम्प्लीट करने दी जाए।

HON. CHAIRPERSON:**:** Please conclude in last 30 seconds.

श्री अरुण भारती (जमुई) : अगर मैं बिहार में विकास की बात करूँ और बाकी एलोकेशन की बात करूँ, तो पिछले 10 वर्षों में केन्द्र सरकार ने हमारी पूरी मदद की है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, बाकी सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा। Please understand.

श्री अरुण भारती (जमुई) : सर, मेरी मेडन स्पीच है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in 30 seconds.

श्री अरुण भारती (जमुई) : सर, बिहार में रेलवेज में 71 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं, 12 नई लाइनें, 4 गेज़ कन्वर्ज़न और 18 डब्लिंग लाइनें दी गई हैं।

सेन्ट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआईएफ) के माध्यम से हमारे राज्य को पिछले चार वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के रोड के प्रॉजेक्ट्स दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केन्द्र से लगभग 1 लाख 73 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

पिछले 10 वर्षों में, मैं बिहार में नये मेडिकल कॉलेजेज की बात करूँ तो वहाँ 8 नये मेडिकल कॉलेजेज शुरू किये गये हैं।

माननीय सभापति : अब समाप्त करें। धन्यवादा।

श्री अरुण भारती (जमुई) : महोदय, इसमें मैं एक व्यक्तिगत एक्सपीरिएंस साझा करना चाहूंगा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से मेरे लोक सभा क्षेत्र जमुई के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई थी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जमुई में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। जमुई एक आकांक्षी जिला है, वहाँ अभी यह हुआ है।

माननीय सभापति : श्री धैर्यशील माने जी, आप शुरू करें।

श्री अरुण भारती (जमुई) : सर, एक पैराग्राफ और है।

HON. CHAIRPERSON: Thank you. I will give you one more chance again.

श्री धैर्यशील माने जी।

(इति)

1758 बजे

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : माननीय सभापति महोदय, अभी बिहार के सदस्य बोले, उसके बाद महाराष्ट्र का मौका आया है।

मैं आपका अभिनन्दन करना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में सारे राष्ट्र को आगे ले जाने का, एक समूचा राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा और उसे साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक बजट को आपके मद्देनज़र रखा है। कई लोग इसको छोटी नज़र से देखते हैं। बिहार को इतना मिला, आंध्र प्रदेश को इतना मिला। अगर विकास-यात्रा में ये दो राज्य छूट जाएं, तो जो संकल्प माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लिया है, वर्ष 2047 में इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का, वह सपना और ध्येय पूरा करना है, तो सारे देश को एक साथ लेकर चलना होगा।… (व्यवधान)

अगर कोई माँ है, उसके कई बच्चे हैं, तो जो सबसे छोटा बच्चा है या कमजोर बच्चा है, उस पर माँ ज्यादा ध्यान देती है। … (व्यवधान)

सरकार ने अगर पिछड़े राज्यों के लिए कुछ करने की कोशिश की है, तो उससे आपका पेट क्यों दुखता है? इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र हमेशा अव्वल राज्य रहा है, शायद आपको महाराष्ट्र के बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र हर क्षेत्र में, इस देश के राजस्व में भी अव्वल रहा है, आर्थिक राजधानी भी रही है। महाराष्ट्र ने हमेशा ही राष्ट्र की उन्नति का काम किया है, कभी उसको पीछे खींचने का काम नहीं किया गया।

(1800/PC/PS)

इस बार भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र राज्य की सरकार केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। मैं कुछ आंकड़े संसद के सामने देना चाहूंगा। आप सिर्फ बजट पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बजट से पूर्व महाराष्ट्र राज्य को क्या मिला है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : माणे जी, कुछ सेकेंड्स के लिए रुकिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it is 6 o’clock right now and I have a long list of speakers. If the House allows, I extend the time of the House till 8 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Mr. Mane, please continue.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : सभी की सहमति के साथ सभागृह आठ बजे तक चलने वाला है। बजट पर हो रही चर्चा में बोलने वालों में बहुत से नए सांसद हैं, जिन्होंने पहली बार संसद में पैर रखा है। मैं उन सभी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि आप एक सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा इस माध्यम से बने हैं।

मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे दूसरी बार यह मौका दिया है कि उनकी बात मैं यहां, संसद में रख पाऊं। लेकिन सर, मुझे एक खेद भी है। मैं जब पहली बार संसद में चुनकर आया था, तो एक क्वॉलिटी एट्मॉस्फेयर था। आज विपक्ष के वरिष्ठ नेता जिस तरह का व्यवहार इस सभागृह में कर रहे हैं, जिस तरह से बात रख रहे हैं, उस ओर से आकर यहां बैठने की कोशिश कर रहे हैं। … (व्यवधान) यहां आकर बैठने के लिए जनता से चुनकर आना पड़ता है, ऐसे ही यहां आकर ट्रेजरी बेंच में नहीं बैठ सकते। … (व्यवधान)

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उदाहरण आप यहां, संसद में रख रहे हो? … (व्यवधान) I am not yielding at all. … (*Interruptions*) I am not yielding. … (*Interruptions*) निश्चित रूप से यह संसद सभी की है, अपनी बात रखने का आपको भी मौका मिलेगा, आप जरूर अपनी बात रखिएगा। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mane ji, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE (HATKANANGLE): Sir, I would like to address the Chair, लेकिन वहां से जो आवाजें आती हैं, वे कानों से निकल नहीं पातीं।

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले) : सर, देश के इस सर्वोच्च सभागृह में आते वक्त हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारे राष्ट्र को हम सब मिलकर, विपक्ष हो या सत्तापक्ष हो, हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं।

मैं कुछ बातें बोलना चाह रहा था। 76,000 करोड़ रुपए का बजट में उसका प्रोविजन नहीं था, उसके पहले ही महाराष्ट्र को केंद्र शासन ने दिया हुआ है। मेरे एक साथी कल बोल रहे थे कि 'कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, मौसम बदलने वाला है'। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रामविलास पासवान जी संसद के सदस्य हुआ करते थे। उनकी पार्टी आज सत्तापक्ष के साथ है। उनको देश की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। … (व्यवधान) जिस तरफ मौसम जाने वाला है, उसका रुख क्या है, यह देश जानता है और इसीलिए श्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार पंत प्रधान बनाया है, प्रधान मंत्री बनाया है। … (व्यवधान) देश का रुख जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ है, कुर्सी की पेटी बांधने वालों के साथ नहीं है। … (व्यवधान) हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों की राजनीति करते हैं और इसीलिए विपक्ष हारने के बाद भी जोश में है। … (व्यवधान)

सत्तापक्ष जीतने के लिए हमें कोई दादा लोगों के सामने नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो योजनाएं बनाई थीं, मोदी जी की गारंटी चली है और इसीलिए एनडीए की सरकार फिर बनी है। … (व्यवधान) इसका जीवंत उदाहरण यह सभागृह है। … (व्यवधान) लेकिन ये लोग अपने जमाने में खुश हैं। … (व्यवधान) एक पुराना सीरियल हुआ करता था – 'मुंगेरी लाल के हसीन

सपने'। ये लोग अपने हसीन और रंगीन सपनों में तल्लीन हैं। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश का भविष्य उचित हाथों में देने का काम इस देश की जनता ने किया है। ... (व्यवधान)

मेरी पार्टी शिवसेना ने जो किया है, उसको आपने मद्देनजर रखना चाहूंगा। मैं मराठी में अपने लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा।

*Hon'ble Chairman, for the sake of their knowledge. I, would like to explain it in Marathi. They should be aware of the Budget provisions made for Maharashtra. This Budget is not meant for a particular class but for the farmers, women, youths, skilled artisans. It is for employment generation and infrastructure development. It is for women and girls' empowerment. Around Rs 3 lac crore have been allocated for youths.

एक सांसद, जो अब चले गए हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से नौकरियां जा रही हैं। आप जाओ जो उद्योगपति महाराष्ट्र में आने वाले हैं, उनके घर के सामने बम रखने का काम करो। ... (व्यवधान) ऐसे में महाराष्ट्र में उद्योग कैसे आएंगे? ... (व्यवधान) नानार जैसा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने वाला था, उसके सामने आपने आंदोलन किया। ... (व्यवधान) लोगों की मनीषा को बिगाड़ दिया। ... (व्यवधान)

(1805/CS/SMN)

महाराष्ट्र में 2 लाख नौकरियाँ बनने वाली थीं, उसका विरोध करने का काम इन लोगों ने किया। आज ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में उद्योग नहीं आ रहे हैं। मेट्रो कार शेड के लिए उन्होंने विरोध किया।... (व्यवधान) आज भी जो 76 हजार करोड़ रुपये पोर्ट के लिए आए हुए हैं, उसका भी ये महाराष्ट्र में विरोध कर रहे हैं। इन्हें महाराष्ट्र की उन्नति से कुछ लेना-देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राज्य को अपने हिस्से के लिए यहाँ यूज करना है।

*Around Rs 10 lac crore have been given to Maharashtra during this regime. Around 4.4 lac crore for Airport development, sufficient funds for Atal Setu Project, Rs 11000 crore for Palkhi Procession, Rs 5800 crore for Railway projects, Rs. 2600 crore for fisheries and around Rs 10,000 crore package for Sugar Mills have been given to Maharashtra. For flood control and management, around Rs 3000 crore package has also been given through World Bank. I would also like to mention that for the conservation of forts in Maharashtra, the ASI should monitor and control the encroachments in fort areas.

Sir, I am sure, in coming years too, the Union Government under Prime Ministership of Shri Narendra Modi ji and Chief Ministership of Shri Eknath Shindeji, Maharashtra will continue to progress at fast place.

With these words, I conclude

Jai Hind. Jai Maharashtra.

(ends)

* Original in Marathi.

1808 बजे

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : महोदय, आपने मुझे बजट के ऊपर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, देश भर के अंदर एक मैसेज इस सरकार द्वारा दिया गया था कि सबका साथ, सबका विकास। इस मुद्दे पर 10 साल से ये सरकार के अंदर हैं और इस बार के बजट से पूरे देश भर के अंदर जो एक मैसेजिंग जाने का काम हुआ है, उसमें मुझे एक ही लाइन लगती है कि जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं और यह इस बजट में नजर आता है।

सरकार कहीं न कहीं कुर्सी को बचाने के लिए, इस बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उससे देश का एक आम आदमी, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, देश के अलग-अलग कोने-कोने में बैठे हुए लोग मन में सोचते जरूर हैं कि इस बजट के अंदर इस देश के किसान के लिए क्या है, इस बजट में देश के युवाओं के लिए क्या है, इस बजट में देश के दलित और मजदूर के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में इस बदलते हुए हिन्दुस्तान के लिए, इस विकसित भारत के लिए क्या है? जीडीपी की ग्रोथ रेट जो वर्ष 2023-24 में रही, वह 8 परसेंट के आसपास रही। सबने इसके बारे में बात कही है। मैं राजस्थान के चुरू लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं किसान और किसानी की बात करूँगा। उन लोगों का साथ मिला है, उन लोगों का आशीर्वाद मिला है, कोई एक बार नहीं, सात बार मिला है, इसलिए मैं उनके बारे में बात करूँगा। कृषि की जीडीपी ग्रोथ रेट हिन्दुस्तान के अंदर 1.4 परसेंट रही। आप 8 परसेंट की बात करते हो, किसान और किसानी 1.4 परसेंट रही। अभी हमारे एक साथी ने बहुत बड़ा दिल करके यह बात कही कि शायद महाराष्ट्र को इतनी बड़ी जरूरत नहीं, पर राजस्थान को बहुत बड़ी जरूरत है।

(1810/IND/SM)

महोदय, कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर राजस्थान के एक आम आदमी की नजरें हैं कि इस बजट में शायद हमें भी कुछ मिलेगा। वह बात जनता के मन में एक आस के रूप में थी। आपकी ही सरकार, आपके ही मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने चुनाव के दौरान गांव-गांव जा कर वायदे किए। ईआरसीपी के तहत 16 राज्यों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। यमुना लिंक का पानी जो राजस्थान की शेखावटी बेल्ट की सबसे बड़ी एक आस है, उसकी हम उम्मीद रखते थे। जिसके बारे में क्लेम किया गया, उसे 'भगीरथ' का नाम दिया गया। चुरु, झुंझुनू, सीकर के अंदर एक लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी और सीकर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का यह प्रोग्राम था। इसकी कोई चर्चा न भारत सरकार के बजट में दिखी और न ही कोई चर्चा राजस्थान के बजट में दिखी। इरीगेशन का कोई भी प्रोजेक्ट 10 सालों से इस देश में नहीं आया। हम किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। एक भी बड़ा बिग टिकट कनाल प्रोजेक्ट नार्थ इंडिया में देखने को नहीं मिला। जनसंख्या ज्यादा हुई है और इसलिए पानी की खपत बढ़ी है लेकिन कैसे एक्सेस वॉटर ऑफ रेन को टैप कर सकते हैं, इस सोच के साथ यमुना लिंक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। वर्ष 2018 में उसकी डीपीआर बनी। 22 हजार करोड़ रुपये का

प्रोजेक्ट था। एक नई उम्मीद होती और किसान को इस प्रोजेक्ट का बहुत फायदा मिलता। यह प्रोजेक्ट बदलते हुए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तस्वीर बन सकता है, हम रेन वॉटर को टैप करके रबी की फसल में किसानों को गैप फंडिंग कर सकते हैं और पानी दे सकते हैं, इसके लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया था। वर्ष 2018 से यह प्रोजेक्ट पेंडिंग है। राजस्थान की सरकार ने आते ही क्लेम किया कि हमने हरियाणा से बात कर ली। हरियाणा के उस समय के मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारे एग्रीमेंट की कोई क्लीयरिटी नहीं है और इस बजट में हम उम्मीद करते रह गए कि 22 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो जो एक्सेस वॉटर या जो पानी बाढ़ द्वारा वेस्ट हो जाता है, उस पानी को टैप करके राजस्थान जैसे राज्य के अंदर ला सकते थे। जितना बड़ा मेरा चुरू क्षेत्र है, उतना बड़ा हरियाणा है। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश में खेती के रूप में हरियाणा और पंजाब ने जो मजबूती प्रदान की है, इससे नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रेवोलूशन की रिक्वायरमेंट है जहां हम ऑयल सीड्स और पल्सेज के ऊपर इम्पोर्ट करने पर डिपेंडेंट हैं, अगर राजस्थान के इस क्षेत्र को पानी मिल जाता तो चुरू लोकसभा क्षेत्र और पूरी शेखावटी बेल्ट पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत रखता है।

महोदय, मैं खेती की बात करूंगा। अनेकों प्रोजेक्ट्स की बात हुई है। यदि आप अपनी स्कीम्स को चेक करेंगे तो हर स्कीम में या तो बजट घटा दिया गया या बजट इनटेक्ट पड़ा हुआ है। किसी प्रोजेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई हैंड होल्डिंग नहीं। हम योजनाएं लॉंच कर देते हैं लेकिन हैंड होल्डिंग नहीं होती है।

महोदय, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, लगता है कि आप घंटी बजाने वाले हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please conclude now. मैं मुस्कुरा कर घंटी बजा रहा हूं।

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Please give me only one minute.

महोदय, वर्ष 2023 का खरीफ फसल का क्लेम आज तक राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। आने वाले सात दिनों में हम वर्ष 2024 का क्लेम भर चुके होंगे। किसान परेशान है। राजस्थान में धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है। एक-एक साल बीत जाता है लेकिन क्लेम का डिस्बर्समेंट नहीं होता है। रिलायंस इंश्योरेंस कम्पनी को चुरू का ठेका दिया हुआ है। कोई न कोई आपत्ति क्लेम पर लगा दी जाती है। आज मंत्री जी ने कहा कि हमने कुछ लिखकर दिया ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर आपने क्या लिखकर दिया है। किसान को क्या गारंटी दी? किसान इतने बुरे हाल में हैं और एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। आप देश में करोड़ों रुपयों का बजट बांट रहे हैं, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। कृषि क्षेत्र देश में बहुत रोजगार भी पैदा करता है और बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। पिछले साल मिलेट ईयर की बात हुई, लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा गया। बाजरे की खरीद राजस्थान की सरकार आज तक नहीं कर पा रही है। आप बाजरे को मिलेट के रूप में शामिल करना चाहते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में ग्वार का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ग्वार को एमएसपी में शामिल करने के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा।

HON. CHAIRPERSON: There are so many speakers and they are all sitting here.

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Please give me only two minutes.

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

(1815/RV/RP)

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सर, मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर आपने मुझे कम समय दिया।

सर, मैं ऑयलसीड्स एण्ड पल्सेज के बारे में बात करूंगा। पिछले साल हमने 1.4 लाख करोड़ रुपये के 160 लाख टन खाद्य तेल आयात किया। पाम ऑयल के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी गयी। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? हमारे चुरू लोक सभा क्षेत्र से लगा हुआ शेखावटी क्षेत्र है, नागौर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तक का पूरा बेल्ट है। यहां सरसों की सबसे बड़ी पैदावार होती है। यहां किसानों को इसके भाव नहीं मिल रहे हैं। वहां के किसानों को इसे बोने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है। हम कैसे इसे बैलेंस-आउट करेंगे, इसका पता नहीं चल रहा है।

सर, आपने नैचुरल फार्मिंग की बात की है। आप एक करोड़ सर्टिफिकेशन्स देंगे। नैचुरल फार्मिंग, ज़ीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की फसलों को कौन परचेज करेगा? हमारे पास इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आज किसान नैचुरल फार्मिंग के अपने प्रोड्यूस को किसके पास जाकर बेचेगा? क्या मार्केट में उसके भाव मिल रहे हैं या नहीं, इसको कोई देखने वाला नहीं है।

सर, इस देश में अनेक स्कीम्स बनी हैं, पर आज तक उनकी कोई हैंडहोल्डिंग नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना बना दी गयी। जब एक योजना में एक गांव का विलेज डेवलपमेंट प्लान बना तो 22 करोड़ रुपये का प्लान बना। मैं चुरू लोक सभा संसदीय क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। वहां मनरेगा में काम करने के लिए 325 करोड़ रुपये मिलते हैं। एक सरपंच को काम करने के लिए एक साल में सवा से डेढ़ करोड़ रुपये मिलते हैं। डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से 22 करोड़ रुपये की वह वी.डी.पी. कब पूरी होगी? वह 22 सालों के बाद पूरी होगी। हम कैसे गांवों का विकास कर पाएंगे, आप इस बात को सोचकर देखिए। अभी शिक्षा के बारे में इतनी बात चली।… (व्यवधान)

सर, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि योजनाएं बहुत-सी हैं, पर उन योजनाओं पर काम नहीं हो पाता है, हैंडहोल्डिंग नहीं हो पाती है और इसलिए योजनाएं फेल हो जाती हैं।

सर, आज ही राजस्थान की एक न्यूज़ है। राजस्थान के चुरू में 16,000 बच्चे सरकारी स्कूल्स से ड्रॉप-आउट्स हो गए, सिर्फ इस बात के लिए कर दिया कि चुरू में 1700 से ऊपर रूम्स की जरूरत है, हजारों रूम्स की जरूरत है। 'पी.एम. श्री', 'स्टार्स' जैसी योजना चलाई गयी। इनके बजट में कटौती कर दी गयी। 'स्टार्स' स्कीम मात्र 1200 करोड़ रुपये की योजना है, जिसमें हम रूम्स बना सकते हैं। जब तक हम दोनों चीज़ों को एड-ऑन नहीं करेंगे, हमारे गांवों का तब तक विकास नहीं हो पाएगा।

महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एमपीलैड फण्ड्स को 3900 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। एक एम.पी. का कोटा 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का है। कम से कम इसको तो डबल कर दिया जाए, ताकि हम गांव में घुसने लायक रह जाएं।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1818 बजे

श्री विवेक ठाकुर (नवादा) : सभापति जी, आज आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2024-2025 के वार्षिक बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए अपने हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ-साथ, आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को भी सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आज यहां बोलने का मौका दिया है।

महोदय, मेरा नवादा संसदीय क्षेत्र, जो ऐतिहासिक मगध का हिस्सा है, वहां की महान जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा है।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में एनडीए ने तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। मैं विपक्ष के अपने उन साथियों को भी बधाई देना चाहूंगा, जो आज बैसाखी के सहारे इस सदन में पूरे एक दशक के बाद विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

महोदय, अंग्रेजी भी बड़ी विचित्र भाषा है। आप किसी भी पहलू को उठाएंगे तो उसके लिए उसमें शब्द जरूर मिलेंगे। इस चुनाव के बाद एक संज्ञा दी गयी, इसे 'मोरल विक्ट्री' बता रहे हैं। इस पर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है –

खुद की हैसियत होगी तो दुनिया क़द्र करेगी,
किसी के इर्द-गिर्द खड़े होने से क़िरदार ऊंचे नहीं होते।

(1820/GG/NKL)

सभापति जी, एक दशक तक सरकार चलाने के बाद तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के बाद सरकार बनाना आसान नहीं होता और वह भी उस परिस्थिति में, जब इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में कोरोना महामारी ने पूरे देश और दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर लिया था। कोरोना महामारी के बाद विश्व में अर्थव्यवस्थाओं का जो हाल हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है।

1820 बजे (श्री दिलीप शइकीया <u>पीठासीन हुए</u>)

आज भी पूरी दुनिया की अनेक इकोनॉमीज़ संघर्ष कर रही हैं और भारत ने पिछले क्वार्टर में 8.2 प्रतिशत के ग्रोथ-रेट को प्राप्त किया है, जो आदरणीय प्रधान मंत्री के दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है।

महोदय, एनडीए की यह जीत सामान्य नहीं है। यह जीत महत्वपूर्ण तो है ही, कोरोना महामारी के बाद अगर आप वैश्विक राजनीति को देखेंगे तो आपको यह नज़र आएगा कि अधिकतर राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। चाहे अमरीका हो, ब्राज़ील हो, इज़राइल हो, जर्मनी हो और हाल ही में आपने इंग्लैण्ड में भी देखा है। इन सबके पीछे प्रमुख कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था में संकट ही था। वहीं, भारत में हमने देखा कि भारत की जनता ने प्रधान मंत्री और उनकी आर्थिक नीतियों पर तीसरी बार विश्वास करते हुए पुन: उन्हें सत्ता में काबिज़ किया है।

सभापति महोदय, यह वर्तमान बजट भी उन्हीं सकारात्मक आर्थिक नीतियों का परिचायक है। मैं तो बड़े अचंभे में रहा, इस बजट के पेश होने के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं। अगले

दिन जब मैंने सुबह कई अखबारों को देखा तो अक्रॉस सैक्टर्स, चाहे वह फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हो या सामान्य न्यूज़पेपर हो, जब उनकी हेडलाइंस और विचारों को पढ़ा और यहां पर जब रिएक्शंस को देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी और गैप कैसे है?

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या हेडलाइंस अखबारों में छपी हैं। 'The Budget is unruffled by 2024 election results'; 'The job of job creation done well'; 'Spending gets rural springboard'; 'Future-proofing the Indian Economy'; 'अनुभव पर आधारित व्यवहारिक बजट'; 'वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार'। ये तो सारे अखबारों की हेडलाइंस थीं।

सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिन प्रायोरिटीज़ का ज़िक्र इस बजट में किया है, वे नौ प्राथमिकताएं देश के नवसृजन का आधार बनाने वाली हैं। ये प्रायोरिटीज़ हैं - Productivity and resilience in Agriculture; Employment and Skilling; Inclusive Human Resource Development and Social Justice; Manufacturing and Services; Urban Development; Energy Security; Infrastructure; Innovation, Research and Development; and Next Generation Reforms. अब इससे बाहर कुछ बचता है कि देश के पैमाने पर अगर आप चिंता करें। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि यह बजट सीमित हो कर रह गया है, बिहार और आंध्र प्रदेश पर, पूर्वोत्तर पर, पूर्वोदय पर। इतना संकुचित पूरे राष्ट्र के बजट को कर दिया गया है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर भारत के इतिहास से आप बिहार को हटा देंगे तो दुनिया का कोई ज्ञान, कोई एक कलम नहीं उठ पाएगी कि भारत का इतिहास कहां से आरंभ करें और कैसे लिखना शुरू करें।

सभापति जी, मैं बिहार के जिस क्षेत्र से सांसद हूँ, वह मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मगध एक ऐतिहासिक राज्य रहा है। हम सभी ने इतिहास की किताबों में इसका वर्णन सुना भी है और पढ़ा भी है। सम्राट अशोक का साम्राज्य, जो मगध से चलता था, वह ईरान, थाइलैण्ड और अफ़गानिस्तान आदि सब तरफ फैला हुआ था। परंतु आज मगध की स्थिति कुछ अलग है। मगध अपने शौर्य और वैभव का भी स्थान इतिहास में पाता है और अपनी बर्बादी की गाथा भी एक काल खण्ड में बनाता है। आज मगध विकास की राह जोह रहा है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि रहे, श्रीकांत वर्मा ने अपने काव्य संग्रह 'मगध' में मगध की स्थिति का जो वर्णन किया है, उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। वे कहते हैं कि – 'यहां मैं मगध को देखता हूँ। यहाँ वह लुप्त हो जाता है। लेकिन न तो मगध है और न ही मगध। आप भी खोज रहे होंगे। भाई! यह वह मगध नहीं है, जिसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा है। यह वह मगध है, जिसे आपने भी मेरी तरह खो दिया है।'

सभापति जी, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मगध की ऐतिहासिक विरासत को बचाने का कार्य इस बजट के माध्यम से किया है। इसलिए हम बिहारवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। चाहे वह गया का विष्णुपद मंदिर हो, बोधगया को अंतराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समान गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को विकसित करना हो, राजगीर में पर्यटन के विकास की

बात हो, गया-वैशाली एक्सप्रेस वे, जो नवादा होते हुए गुज़रेगा। एक इंडस्ट्रियल हब गया में बनाने की बात है। सिर्फ गया में नहीं, यह कोलकाता-अमृतसर कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जिस राज्य से गुज़रेगा, वहां हर जगह एक-एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात है। चेन्नई-वाइज़ेग कॉरिडोर की भी घोषणा हुई। लेकिन चर्चा सिर्फ गया की है और कोलकाता-अमृतसर कॉरिडोर के नाम से भी नहीं है। यह सब कुछ बिहार तक आ कर सीमित हो गया है। अगर पार भी कर रहा है, वहां बन भी रहा है तो शोर किस बात का है?

सभापति जी, विष्णुपद मंदिर हिंदु धर्म की रीतियों का पड़ाव है। गया जी में मरणोपरांत पिंड दान और तर्पण करने वाले देश के अलावा विश्व के कोने-कोने से करोड़ो लोग आते हैं।

(1825/MY/VR)

क्या इसका विकास होना गलत है? शोर काहे का है? इन सभी के माध्यम से मगध क्षेत्र के वैभव को पुन: प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। गया और मगध इस सरकार के विकास एवं विरासत का अद्भूत मिश्रण है, जिसकी चर्चा इस बजट में की गई है।

सभापति जी, केवल मगध ही नहीं, पूरे बिहार के विकास हेतु सरकार ने सहायक कदम उठाए हैं। चाहे वह बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे हो, पटना-पुर्णिया एक्सप्रेस वे हो, चाहे वह 2400 मेगावाट का पावर प्लांट पीरपैंती में लग रहा हो। बिहार के विकास में, विशेषकर उत्तरी बिहार में विकास में प्रमुख बाधक कोसी वाली बाढ़ थी। हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि बाढ़ तो पूरी दुनिया में आती है, पूरे देश में आती है, हमारे क्षेत्र में भी आती है। अरे, आती तो है, अमेरिका में भी आती है, इसे कौन नहीं जानता है! इसमें ज्ञान क्या है? लेकिन, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बिहार का बाढ़ कितनी दास्तान, कितने सिनेमा, कितनी कहानी, कितने कविताएं लिख कर जा चुका है और आप उसको हल्का बना रहे हैं। साल दर साल जो वर्णन किया जाए, वह रोंगटे खड़ा करता है और इसका प्रबंध आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। अगर पहली बार ठोस प्रबंधन हुआ है तो यह सराहनीय कदम है। इसी को कवि दुष्यंत ने कहा होता, जो हमारे प्रधानमंत्री पर सीधे चरितार्थ होता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदल जाए।

सभापति जी, हमारे विपक्षी साथी यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को जान-बूझकर फायदा पहुंचाया गया है। अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। भेदभाव क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा। देश में जब कांग्रेस की प्रथम सरकार बनी तो उसने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की नीति लाई और उसने बिहार को तबाह कर दिया। भेदभाव तो बिहार के साथ आज नहीं, बल्कि दशकों पहले इसकी यात्रा आरंभ हो गयी थी। जो आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि बिहार या पूर्वोत्तर के विकास के बिना आर्थिक समानता संभव है क्या! यदि उनका उत्तर हाँ में है तो उन्हें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति से मैं समझाना चाहूंगा-

"शान्ति नहीं तब तक, जब तक सुख भाग न नर का सम हो,
नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो।"

इसलिए, बजट में हमें जो भी मिला है, वह हमारे हक का है। हम बिहारवासी को न किसी का हक लेने आता है, न किसी का हक मारना आता है।... (व्यवधान)

सभापति जी, इस सदन का यह मेरा मेडन स्पीच है। इन लोगों को बिहार का विकास देखा नहीं जा रहा है। ये वही लोग हैं, जो बिहार में बाढ़ आने के बाद कहते थे, भारती जी ने ठीक ही कहा कि वे कहते थे कि भाग्यशाली हो कि आपके घर के दरवाजे पर माँ गंगा आयी है, आप आरती उतारो।

सभापति महोदय, दशकों से जो विनाश का तांडव हुआ है, उसका वर्णन मैं नहीं करना चाहता हूं। ये वही लोग हैं, उसकी भी चर्चा हुई कि सड़क बनाने पर पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। मेरे विपक्ष के साथी चाहते हैं कि हमारा बिहार बाढ़ में डूबा रहे और विकास से दूर रहे। केंद्र की सत्ता में तो आप लगातार दस सालों वर्ष 2014 तक रहें, आप ही कर देते, हम उसका स्वागत करते, लेकिन किया क्यों नहीं? जब आज हो रहा है तो आपत्ति और कुंठा किस बात की।... (व्यवधान)

महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने बाढ़ का पावर प्लांट चालू करवाया, पटना का एम्स दिया, रोड बनने का काम शुरू हुआ। बिहार में एनडीए की सरकार जब नीतीश जी और सुशील जी के नेतृत्व में बनी तो बिहार मॉडल की बात शुरू हुई। आपके समय की ख्याति बिहार के विकास से कोसों दूर थी और किन कारणों से ख्याति हुई, यह जगजाहिर है। कल आपके पार्टी के कप्तान का जो बयान आया है, बड़ा दुखद था। उन्होंने कहा कि दो थाली है, एक में पकौड़ा और दूसरे में जलेबी है। बिहार और पूर्वात्तर अगर विकास के रास्ते पर चला है तो इतनी बड़ी आपत्ति है, यह सब दुर्भाग्य हैं। बिहारवासियों ने दशकों पहले गुहार लगायी, बंटवारा हो गया, कुछ भी नही बचा है। बाढ़, सुखाड़, स्कैम, क्राइम, इसके अलावा कुछ भी हमारे बिहार में नहीं बचा था।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विवेक ठाकुर (नवादा) : सभापति जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं सुबह से ही इंतजार कर रहा था। बस, मेरी बात खत्म हो रही है। मैं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब बिहार आगे बढ़ेगा और मेरा देश भी आगे बढ़ेगा।

सभापति जी, इस बजट के माध्यम से पूर्वी भारत की जो बात की गई है, यह समझना पड़ेगा कि हमारे बिहार का एवरेज इनकम गोवा से भी दस गुना कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की बात कही है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। सत्ता में आए तो आज नहीं वर्ष 2014 से ही पहला फोकस उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत किया है। कल मेरे दोस्त विप्लव जी ने भी इस पर बड़ा विस्तार से बताया कि पूर्वात्तर भारत में किस तरह से काम हो रहा है।

सभापति जी, आप तो खुद इसके साक्षात गवाह हैं।

(1830/CP/SAN)

पूर्वोत्तर नीति से पूर्व के सूर्योदय का वक्त अब आ गया है और वह सराहनीय है। इसी पर राष्ट्र कवि ने कहा था :

"हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा,
सूर्य को उगना पड़ेगा, सूर्य को उगना पड़ेगा,
फूल को खिलना पड़ेगा।
हो समय कितना भी भारी, हमने न उम्मीद हारी,
दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा।
सब थके हैं, सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले,
साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा।"

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विवेक ठाकुर (नवादा) : महोदय, मेरी मेडन स्पीच है। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

महोदय, मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सांसद हूं। मेरा एक सुझाव है। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जो आरम्भ हुआ है, वह एक क्रांतिकारी कदम है। हमारे यहां नवादा, शेखपुरा, बरबिघा, ये सब जो क्षेत्र हैं, वहां 300-400 फीट तक पानी की गहराई चली गई है। इन सबको और जो पुराने चिन्हित हैं, उन सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को सीएसआर के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इससे इन सभी क्षेत्रों को बड़ा ही फायदा होगा।

महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अंत में आपका आदर करते हुए आपकी अनुमति से इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक बात जरूर कहूंगा। सरकार बनने के बाद निरन्तर कैपेक्स में बढ़ोत्तरी हुई है। इस वर्ष भारत सरकार का कैपेक्स 11.11 लाख करोड़ रुपये का है। पिछले तीन वर्षों में यह दोगुना होकर जीडीपी के 1.7 से बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गया है। आजादी के बाद इस वित्तीय वर्ष में यह सर्वाधिक है। 10 वर्ष पूर्व जब हम सरकार में आए थे, तब कैपेक्स मात्र 2,29,128 करोड़ रुपये था, जो आज 11 लाख करोड़ हो चुका है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप 30 सेकेंड्स में अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री विवेक ठाकुर (नवादा) : ... (व्यवधान) पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने फिस्कल डेफिसिट का 5.8 पर्सेंट का टार्गेट रखा था और 5.6 पर्सेंट एचीव किया था। यह सम्भव है, मोदी है तो मुमकिन है।

(इति)

1833 बजे

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : महोदय, मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे देश की संसद में जाने का अवसर दिया। मैं बक्सर की महान जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जिताकर मुझे बिहार के हक की लड़ाई के लिए यहां भेजा है। मैं इस बजट से भारी निराश हूं। विशेष रूप से गरीबी खत्म करने के लिए इस बजट में कुछ नया नहीं है। वित्त मंत्री ने बेरोजगारी कम करने का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि इस देश में 30 हजार किसान और कृषि मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि इस बार बजट में उन्होंने कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना का उल्लेख किया है। लेकिन, मैं तथ्य पर बोलना चाहता हूं कि योजना बिहार में इसके लांच के बाद कभी नहीं पहुंची। वर्तमान में बिहार में एक भी छात्रावास नहीं है। जबकि केरल, महाराष्ट्र, तमिनलाडु जैसे राज्यों में क्रमश: 129, 77 और 54 छात्रावास हैं। केंद्र सरकार पहले से विकसित राज्यों को उठाने की कोशिश कर रही है और बिहार जैसे गरीब राज्यों की उपेक्षा कर रही है। जिन्हें केंद्र सरकार का ध्यान सबसे अधिक चाहिए, वहां केंद्र सरकार का ध्यान कम जा रहा है।

प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री आवास योजना के लांच पर वर्ष 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया था, लेकिन वे अभी भी समय-सीमा बढ़ा रहे हैं और अतिरिक्त 3 करोड़ घर जोड़ रहे हैं। क्या सरकार यह स्वीकार कर रही है कि वे गरीब भारतीयों को घर देने में विफल रही है? सरकार ने घोषणा की है कि वह 12 औद्योगिक मेगा पार्क्स का निर्माण करेगी। मुझे डर है कि सभी औद्योगिक पार्क्स विकसित राज्यों में जाएंगे, जैसा कि हम केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में देखते हैं। उदाहरणस्वरूप अगर बुलेट ट्रेन चली भी तो अहमदाबाद से मुंबई चली गई, जबकि देश के प्रधान मंत्री वाराणसी से सांसद हैं। वे चाहते तो अहमदाबाद से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चला सकते थे, लेकिन ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को कितने औद्योगिक पार्क्स दिए जाएंगे?

(1835/NK/SNT)

इस तरह की योजनाओं में गरीब राज्यों के लिए आरक्षण होना चाहिए। सरकार ने बजट में कहा, आईबीसी कानून के जरिए से अधिक कंपनियों का समाधान किया गया। लेकिन उस राशि को छुपाने का प्रयास किया, इसका उल्लेख नहीं किया, इस कारण इस देश में कितने लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने एक दशक पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, वे अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए देश के संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा एक लंबा आंदोलन चलाया गया था। 736 किसानों की शहादत के बाद इस देश के कृषि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा लिखे गए पत्र पर कि हम आने वाले वक्त में किसानों के हक में न्याय का फैसला करेंगे, आज तीन साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आपने अपने बजट में प्राकृति खेती की शुरूआत की बात की, इस कदम के कारण देश में अनाज के उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, इस बात की यहां चर्चा नहीं की गई। जलवायु परिवर्तन

के कारण होने वाली आपदाएं किसानों पर भारी पड़ रही हैं, देश में अनाज का उत्पादन घटता जा रहा है। गेहूं के उत्पादन घटने से गरीब लोगों को हर साल हर महीने दो किलो गेहूं दिया जाता था, उसको घटाकर एक किलो करने का सरकार ने निर्णय लिया, यह दुखद विषय है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लांच किया गया था, लेकिन वह लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हमारे युवाओं का लगभग 51.25 प्रतिशत ही रोजगार योग्य है। इसका मतलब है कॉलेज से सीधे निकलने वाले लगभग दो छात्रों में से एक युवा भारतीय आसानी से रोजगार पाने योग्य नहीं है। इससे बड़ा दुखद विषय हो ही नहीं सकता। भारत की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वह उस स्तर की नहीं हैं, जो रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। भारत की बेरोजगारी दर महामारी से पहले की तुलना में अभी भी अधिक है। बिहार को बजट में मिली परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए 58 हजार 900 करोड़ रुपये का सरप्राइज मिला, लेकिन उन्होंने अन्य राज्यों को भी गुप्त रूप से परियोजनाएं देने का काम किया, उसकी चर्चा बजट में नहीं है। 58 हजार 900 करोड़ रुपये कितनी रकम होती है। गुजरात में दो सेमी-कंडक्टर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने राजकोष से 70 हजार करोड़ रुपये का अनुदान केवल एक योजना के लिए देने का काम किया। अभी महाराष्ट्र के एक सांसद महोदय की बात मैं सुन रहा था कि देश की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए दस लाख करोड़ रुपये की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को देने का काम किया। बिहार को केवल 58 हजार 900 करोड़ रुपये देने पर जिस तरह से हाय तौबा मचायी जा रही है, यह कभी भी बर्दाशत के बाहर नहीं है। बिहार की 14 करोड़ आबादी जो देश की 10 प्रतिशत आबादी के बराबर है, क्या उसको हक नहीं है। हमारे यहां हाईवे की बात हो रही है। प्रति लाख आबादी में महाराष्ट्र में 15 किलोमीटर राष्ट्रीय सड़कें बनायी गईं, गुजरात में 11 किलोमीटर प्रति लाख बनायी गई, वहीं बिहार में अभी मात्र 5 किलोमीटर ही सड़कें बनी हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है। 24 हजार 400 करोड़ रुपये के पीरपैंती बिजली घर की चर्चा सदन में हुई है। इस योजना को यूपीए-II में मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकृत किया था। यह नई परियोजना नहीं है, रिब्रांडिंग, रिपैकेजिंग सत्तारूढ़ दल की एक नई परंपरा है।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए, आपके पास पांच मिनट का समय था। आप तीस सेंकड में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, हम दोनों सदस्य बोलेंगे, तीन मिनट दिये जाएं। क्या आपको लगता है कि केवल बिहार को ही ये परियोजनाएं मिलीं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इससे ज्यादा परियोजनाएं दूसरे विकसित राज्यों को गई हैं। बिहार के लोगों को झांसा देने के लिए इसका उल्लेख बजट में इसलिए कर रहे हैं कि वर्ष 2025 में बिहार में विधान सभा चुनाव होना है। यह चुनावी राजनीति के हथकंडा का हिस्सा है न कि स्पेशल पैकेज का सवाल है। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर खर्च में पिछले साल की तुलना में कटौती देखी जा रही है। यह लगातार घटता जा रहा है। सरकार शिक्षा के लिए उपकर वसूल रही है, लेकिन आबंटन

नहीं बढ़ा रही है। वर्ष 2004-05 में जब शिक्षा उपकर नहीं था तो उस समय तत्कालीन सरकार 2.3 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रही थी।

(1840/SK/AK)

शिक्षा पर छ: प्रतिशत खर्च होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनकम टैक्स में शिक्षा उपकर जोड़ा गया और इसके जरिए पिछले साल 65 हजार करोड़ रुपये मिले तो फिर मेन बजट से पैसे क्यों घटते जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इस देश में नॉलेज पावर बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़, उच्च शिक्षण संस्थाओं और प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है, लेकिन इस सरकार में बैठे लोग इस तरफ उदासीन हैं। आप 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये में से 65 हजार शिक्षा शेष को निकाल दें तो फिर बचेगा ही कितना? इसका मतलब है कि आंकड़े वर्ष 2003-04 से नीचे जा चुके हैं, मैं इस बात की तरफ इंगित करना चाहता हूं। वर्तमान में जीडीपी का लगभग ढाई प्रतिशत शिक्षा के लिए आबंटित किया गया जो कि इस महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए अपर्याप्त है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षा में सुधार और जीडीपी का कम से कम छ: परसेंट का आबंटन आवश्यक है। लेकिन छ: परसेंट कहां है? हम केवल ढाई परसेंट पर हैं।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में बड़ी कटौती की। कई क्षेत्रों में उत्पादन गिर रहा है, बजट 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कम से कम बिहार राज्य के बजट के लिए एक बार तो धन्यवाद तो दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

मैं बिहार के भविष्य में विकास के लिए केंद्र सरकार से वर्तमान बजट में विशेष प्रावधान की मांग करता हूं। मैं बिहार में किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु पुरानी जर्जर मंडियों का पुनर्निर्माण एवं नई मंडियों के निर्माण की मांग करता हूं। नवानगर, बक्सर और मोतिहारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक जोन को विशेष आर्थिक क्षेत्र की मान्यता देनी चाहिए। राजगीर, बोधगया की तर्ज पर बक्सर और वैशाली धार्मिक पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना चाहिए। बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, जो कि नई सुविधाओं से बने हों, के लिए बजटीय आबंटन करना चाहिए। रीजनल कनैक्टिविटी योजना के अंतर्गत रक्सौल एवं पूर्णिया एयरपोर्ट को विकसित करना चाहिए। मैं आरा, मुंडेश्वरी रेल परियोजना वाया भभुआ रोड के लिए बजटीय आबंटन की मांग करता हूं।

(इति)

1843 hours

*SHRI MALVINDER SINGH KANG (ANANDPUR SAHIB): Hon. Chairman Sir, I am grateful to you that you have given me the opportunity to speak on Union Budget 2024-25.

Sir, I have read the Budget speech of Hon. Finance Minister ma'am. This Budget is undemocratic, unconstitutional and anti-federal structure. Discrimination has been meted out to Punjab. This Budget is against the spirit of Federalism of the Constitution framed by Dr. Baba Saheb Ambedkar ji.

Hon. Chairman Sir, I am happy to note that the word '*Annadata*' or provider of food has come in this Budget speech. The BJP had defamed the same '*Annadata*' by calling them names like Pakistani, Urban-naxal and anti-national etc. When the issue of providing food to 80 crore people has come up, the Hon. Finance Minister in her Budget speech has used the word '*Annadata*'. I welcome this. However, let me say that the State of Punjab plays a crucial part in providing foodgrains to 80 crore people. Punjab contributes 50% foodgrains in the Central pool. However, in the entire speech of Hon. Finance Minister, the State of Punjab has not been mentioned even once. Hon. Chairman Sir, this is very unfortunate.

What should have happened was that our farmers who were protesting since long, should have been granted Minimum Support Price. Sir, but MSP on foodgrains has not been granted to farmers which is very unfortunate. When Modi ji was CM of Gujarat at that time, the then PM had said that farmers should get MSP guarantee. But, in the last 10 years, the BJP Government has refused to accept this demand of farmers.

Hon. Chairman Sir, the Budget speech talks about employment. But, in the last 10 years, our youth have become more unemployed. Unemployment has increased by leaps and bounds. The Agniveer Scheme is pushing the youth towards unemployment and organized crime.

---

* Original in Punjabi

In my constituency in district Mohali, an Agniveer who had served the army for 2 years, has been caught stealing things red-handed. He gave the statement that we have no future. I have said this because hon. Members and hon. Ministers are here. This is the condition of youth today.

In Haryana, elections are going to take place. The Haryana Chief Minister had to announce a special package for Agniveers to avoid trouble. The Haryana CM is also against this Scheme. So, I urge upon the Government to withdraw the Agniveer Scheme.

Sir, the Budget Speech talks about Kolkata to Amritsar corridor. We do not oppose it. But, if Mumbai-Karachi trade link is there, why Amritsar-Lahore trade link is not there? So, the Central Government should open the Wagah border trade route with Pakistan. It will benefit the entire North India, including Punjab, Haryana, Himachal, Rajasthan etc.

Sir, discrimination has been done against Punjab. Andhra Pradesh has been given a package of Rs. 15,000 crores.

Sir, give me some more time. This is my first speech. I want to make two more points. Rs. 15,000 crores have been given to Andhra Pradesh for the construction of its capital city at Amravati. But, step-motherly treatment has been meted out to Punjab. In 1966, the Reorganization Bill was passed. After 58 long years, Punjab has not yet been given its capital city of Chandigarh. I urge upon the Central Government that Chandigarh should be given to Punjab as its capital city because this city came up when the villagers of Punjab were displaced from this land.

Sir, floods had wreaked havoc in Punjab last year. I don't oppose any package given to any State including Bihar. But Punjab suffered a loss of over Rs. 1680 crores. The Budget does not mention this loss suffered by Punjab. I request the Indian Government to announce a special package to Punjab to compensate for this loss…

(ends)

1848 बजे

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया। मैं सारे हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस यूनियन बजट के साथ आज जम्मू-कश्मीर के बजट पर बहस हो रही है, इसलिए मेहरबानी करके, जम्मू-कश्मीर का कोई आदमी इससे पहले नहीं बोला, हम दो-तीन एमपीज हैं, एक मंत्री हैं, एक जेल में हैं, इसलिए हमें अपनी बात कहने के लिए टाइम मिलना चाहिए। वहां पर कोई असेम्बली नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तवक्कात थी। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका बहुत एहतराम है। वह सीनियर लीडर है और पिछले कई सालों से यह महकमा देख रही हैं। लेकिन, कितना बेहतर होता कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ भी बात करतीं, वहां के एमपीज के साथ बात करतीं, वहां के ट्रेडर्स के साथ बात करतीं और फिर यह बजट यहां पर आता । इसकी वहां पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई है। जो भी एक्सरसाइज की गई है, वह ब्यूरोक्रेट्स की लेवल पर की गई है। यह बदकिस्मती की बात है कि पिछले सात साल से वहां पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। पिछले दस सालों से कोई असेम्बली के इलेक्शन नहीं हुए हैं। हम ब्यूरोक्रेट्स की मर्सी पर हैं। उनके रहमो करम पर है। वहां करप्शन अपने उरूज पर है, वहां दफ्तरी तवालत अपने उरूज पर है।

(1850/SJN/SRG)

वहां बेरोजगारी अपने उरूज पर है, महंगाई अपने उरूज पर है। यह कितना बेहतर होता कि इन चीजों को देखने के लिए, इस बजट को यहां पेश करने से पहले अगर माननीय वित्त मंत्री जी खुद जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ इसका जायज़ा लेतीं, तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से इस बजट को समझ सकती थीं।

इस बजट के बारे में आज यहां पर कहा गया है कि हम जम्मू-कश्मीर को इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वहां असली हकीकत यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के पिछले साल के कई हजार करोड़ रुपयों के बिल्स पेंडिंग हैं। उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है। इस वक्त कहा जा रहा है कि इस बजट में जितना भी पैसा दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जो पुरानी लाइबिलिटीज़ हैं, वह उसको भी कवर कर पाएगा। वहां की हालत यह है कि मुलाज़िमों को पेंशन नहीं मिल रही है, जीपी फंड का पैसा नहीं मिल रहा है।

मैं बड़े वसूक़ से इस पूरे हाउस के नोटिस में यह मामला लाना चाहता हूं कि वहां की जो असली हालत है, उसके बारे में यहां सबको पता चलना चाहिए। उन्होंने यहां पर बजट तो पेश किया है, लेकिन मैं आपको वास्तविकता के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां मुलाज़िमों की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है, बेरोजगारों की हालत क्या है।

मैं आपको यह बताऊं कि जो अनंतनाग जिला है, वह जम्मू-कश्मीर का सबसे पुराना जिला है। मैं अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र से लोक सभा का सदस्य हूं। वहां पर एक मेडिकल कॉलेज तो कायम हुआ है, वह पिछले छः, सात या उससे भी ज्यादा सालों से चल रहा है, लेकिन वहां एमआरआई की सुविधा तक नहीं है। इतने बड़े हिस्टोरिक टाउन के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। वहां पर जो क्रिटिकल स्पॉट्स हैं, उनके ऊपर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर के बजट में उसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। जो सबसे पुराना और मशहूर जिला है, उसमें एक बाईपास बनाने की जरूरत है। जो पहलगाम का टूरिस्ट स्पॉट है, जहां से अमरनाथ की यात्रा निकलती है, वह इसी जिले से

होकर गुजरती है। जब वहां इतने यात्री पहुंचते हैं, तो उस जिले में घंटों जाम लगा रहता है। इस बजट में इतने महत्वपूर्ण जिले के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है।

मैं आपके नोटिस में यह भी लाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ बहुत अच्छा काम कर रहा था। जो कश्मीरी डॉक्टर्स हैं, वे अपने काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वे जिस लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं एवं जिस मेहनत से इस संस्थान को चलाया जा रहा था, अफ़सोस और परेशानी की बात है कि जिस तरह से हमारे स्टेट को खत्म किया गया, उसी तरह से उस संस्थान की अटानोमी भी खत्म कर दी गई है। आज उसको हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर दे दिया गया है। एक संस्थान जो पूरे जम्मू-कश्मीर की ख़िदमत कर रहा था, वहां पर पूरे तरीके से काम मुतासिर हो रहा है। वहां हजारों पद खाली पड़े हैं।

जम्मू-कश्मीर का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन जिसको अब आप यूटी कहते हैं, लेकिन हम अपने लफ़्ज़ से उसको यूटी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम स्टेट की बात करेंगे। उस संस्थान की हालत खराब हो रही है। उसको अटानोमी भी खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आपने जम्मू में एक एम्स बनाया है, आपने उसकी शुरुआत की है, हम उस फैसले का ख़ैर-मक़्दम करते हैं, लेकिन कश्मीर के संस्थान की अटानोमी खत्म करके वहां के हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।

इसके साथ ही साथ जो हिली जिले हैं, राजौरी और पुंछ के जो बॉर्डर जिले हैं, इस बजट में उन जिलों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। होना यह चाहिए था कि ये जो बॉर्डर और हिली जिले हैं, उनके लिए पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी और जलशक्ति जैसे महकमों के लिए ज्यादा एलोकेशन किया जाता। वह मेरा संसदीय सेगमेंट है। वहां सड़कों की इतनी बुरी हालत है। उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, स्टेट के लिए जो एलोकेशन हो रहा है, वह उस बुनियाद पर नहीं हो रहा है, जहां पर उसकी जरूरत है। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि एक हाउस कमेटी बनाइए और वह उसको देखे। वहां पर जो बीकन के प्रोजेक्ट्स हैं, राजौरी और पुंछ के दोनों बॉर्डर जिले हैं।

(1855/SPS/RCP)

मैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला। मैंने उनको यह भी कहा कि वहां पर बीआरओ का कार्य न होने के बराबर है। जम्मू से पुंछ तक का 220 किलोमीटर का स्ट्रैच है, उसकी बुरी हालत है। मैं ऑनरेबल चेयर से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे यहां पर कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स हैं, उनको पिछले कई सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, उस पर कोई पेशे रफ्त नहीं हो रही है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ दम हाल हांजीपुरा से मोहोर के साथ एक सड़क का प्रोजेक्ट था, वह प्रोजेक्ट पिछली सरकार में शुरू हुआ था। उसका काम बंद पड़ा हुआ है। उस प्रोजेक्ट की वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स हैं, उनको वेजेस नहीं मिल रही है।

महोदय, इसके साथ-साथ एक बात और है, जिसके लिए मैंने सप्लीमेंट्री पूछने की कोशिश भी की थी कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान हवाई जहाज की यात्रा सबसे महंगी है। अगर वहां टूरिस्ट जा रहा है तो उसका मतलब यह नहीं है। पेशेंट है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और अगर मुझे इतना किराया रोज देना पड़ेगा तथा आप जो मुझे दे रहे हैं, वह तो एक-दो महीने में खत्म हो जाएगा। एयरलाइन्स का इस पर कंट्रोल नहीं है। खास तौर पर श्रीनगर वाले रूट पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस एयरलाइन की जो मर्जी हो, वह किराया लेती है, लेकिन वहां पर इंसाफ के साथ काम नहीं लिया जा रहा है। वहां पर हमारे

हाइडिल प्रोजेक्ट्स हैं, वे नहीं चल रहे हैं। सरकार की ना एहली की वजह से वे नहीं चल रहे हैं, उल्टे वहां पर बहुत ज्यादा बिजली फीस बढ़ाई गई है और बिजली की फीस वसूल करने के लिए एफआईआर की जा रही है। हम एक जम्हूरी हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं। अगर आप बिजली फीस पर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है?

महोदय, ट्राइबल्स के बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है। मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूं। जो यहां पर यूनियन बजट पेश हुआ है, न इसमें ट्राइबल्स के लिए कुछ है और न जम्मू कश्मीर के बजट में ट्राइबल्स के लिए कुछ कहा गया है। ट्राइबल्स के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। इस सरकार में मुझे कोई भी यह नहीं बता सकता है कि ट्राइबल्स के लिए क्या हो रहा है? हमें कोई बताए कि ट्राइबल्स के लिए पैसा आया तो क्या चार किलोमीटर की सड़क बनी, क्या उनके लिए कोई हॉस्पिटल बना, क्या उनके लिए कोई स्कूल बना, लेकिन पब्लिसिटी इतनी की जा रही है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे कंट्री के लेवल पर हो और चाहे खास तौर पर स्टेट के लेवल पर हो। सच तो यह है कि जो ट्राइबल गरीब जंगल की जमीन पर रह रहा था, जिसके लिए यह कहा गया कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट में हकूक मिलेंगे, उनको पांच या दस मरला या एक-दो कैनाल जमीन, जिस पर वह बैठते हैं, उसकी मिलकियत के हकूक दिए जाएंगे, लेकिन लोग चार-चार साल सरकारी दफ्तरों में दर-बदर हैं। उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है, उल्टा यह हो रहा है कि जो पुराने मकान में रहा रहा था, जिसको पीएमएवाई के तहत केस सैंक्शन हुआ, उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने नहीं देता है। वह कहता है कि यह फॉरेस्ट की जमीन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि जहां ट्राइबल हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो पीएमएवाई केस लेने वाला गरीब है, उसको अपने मकान के लिए वहां पर जमीन नहीं मिल रही है, जहां पर वह बीस साल से रह रहा है।

सर, जो दावे हो रहे हैं, वे उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम यह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो यह नाइंसाफियां हैं, सियासी तौर पर हों, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हों, फण्ड्स के लिहाज से हों, डेवलपमेंट के लिहाज से हों, बेरोजगारी के हवाले से हों। ये चीजें दूर होनी चाहिए। हमें तवक्को है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इनका जवाब दें, जो हमने कहा है और खास तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स, बेरोजगार, कैजुअल लेबर्स के बारे में जो कुछ कहा है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा है। सबसे अहम बात है कि रियासी में रेल पहुंच गई है। कटरा से आगे रियासी है। रियासी से सिर्फ 40 किलोमीटर राजौरी-पुंछ का एरिया है, लेकिन इस बजट में राजौरी-पुंछ की रेलवे लाइन के मुताल्लिक भी कुछ नहीं कहा गया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

(1900/MM/PS)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : एक बार देख लेंगे, क्योंकि माननीय सदस्य ने जानकारी गलत दी है। नेशनल हाईवे और दूसरा एम्स भी जम्मू-कश्मीर को दिया है। उसके बारे में भी नहीं बोला है।

1900 hours

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Budget. It is my maiden speech. I am a first timer in this House. I am thankful to the Congress leadership Shrimati Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, Kharge ji, and also Shri Revanth Reddy ji for giving me this opportunity to represent Telangana and my constituency Bhongir.

With a lot of enthusiasm, I have come to this House as a first timer. This is my second session. In the first session also, I tried to speak on the Presidential Address. But I could not get the opportunity. Now, I want to say a few words on that topic. The Presidential Speech was not a reality. Whereas my leader Rahul Gandhi ji, who had done the Bharat Jodo Yatra from Kanniyakumari to Kashmir, wanted to talk about the reality. But they had disrupted the House that time. They do not want the people of this country to know the facts. For the last two Sessions, I have been watching them. They have only been appreciating themselves and have only been clapping for themselves but have not been speaking for the people of this country.

Now, I come to the Budget. For me, this Budget looks like a political survival Budget. अब की बार 400 नहीं हुआ, अब की बार 240 हुआ। They won 273 seats. This is a reflection of political survival in the 18th Lok Sabha. It is because they want to speak only about two States, that is, Andhra Pradesh and Bihar. When I came to this House, I thought that this is a Temple of Democracy and everybody will get an opportunity and every State will get an opportunity. But what I found later in this House is that the leadership on the other side wants to survive themselves in the 18th Lok Sabha. That is why, they want to compromise and they want to give more budgetary allocation to Andhra Pradesh. And we do not want to object to it also. It is a matter of their development. Every State need development. We are also asking budgetary allocation for every State.

The hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji in her 2024-25 Budget speech announced substantial funds for Andhra Pradesh, while Telangana was notably overlooked. At the beginning of her speech, she dedicated a section to the Andhra Pradesh Reorganisation Act. She said, and I quote:

> "Our Government has made concerted efforts to fulfil the commitments made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act.

Understanding the need for a state capital, we will facilitate special financial assistance through multilateral development agencies in the current financial year with Rs. 15,000 crore.”

The Andhra Pradesh Reorganisation Act also includes the State of Telangana. Telangana is also a part of it. She did not even bother to talk about Telangana. In the last 10 budgets, we are always kept away. They have never bothered about it. In the past, we used to have Members from the BRS Party. They were also supporting the BJP indirectly. They had supported many Bills in the past. They had supported Article 370 and demonetisation, and they had also supported the BJP when there were elections of President, Vice-President and Deputy Chairman of Rajya Sabha. But even then, they did not demand anything for the State. Now, the people of the State have kept them away from this House. There is no Member from the BRS Party. Now, they have given opportunity to eight MPs from the BJP and eight MPs from the Congress thinking that, at least, this time in the 18th Lok Sabha, they will have an opportunity and they will get allocations in the Budget. But this Budget is a total disaster. It kept Telangana away from it.

Hon. Chairperson, Sir, the hon. Finance Minister said, and I quote:

“Under the Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads in Kopparthy node on the Vishakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor, and additional allocations will be provided this year.”

Hon. Chairperson, Sir, we also requested our hon. Chief Minister Shri Revanth Reddy ji. In the last eight months, even though the Model Code of Conduct of election was in force for three months, he met 18 Ministers in the Government of India in the last five months.

(1905/SMN/YSH)

He met the Prime Minister Narendra Modi Ji three times for the sake of development of our State. Even I myself, after winning the elections, requested the Members of Parliament from the other side to work together for the sake of Telangana. For the last two days, I have noticed none of these MPs are working on this issue and not fighting with their leadership on behalf of Telangana.

Nirmala Sitharaman Ji was talking about the Polavaram Project in Andhra Pradesh. We also have a major project which covers 12 lakh acres, that is, our Palamuru Rangareddy Irrigation Scheme. She did not speak about this project. This was the promise made in 2014 when the Reorganisation Act was made. But we have got the Central Horticulture University. They have promised a steel plant in Khammam. They have promised a Rail Coach Factory in six months. More than 10 years have passed. They also promised road connectivity in the backward regions of Telangana. Yesterday, Nirmala Sitharaman Ji was talking about the same thing with Andhra Pradesh also. We would have been very happy if the Reorganisation Act is implemented for both the States. But it did not happen like that. They kept everything away because their only agenda is to safeguard this Government in the 18th Lok Sabha. They know that they do not have the Members. Today also, they are very proudly saying that they have won the elections. How did they win the elections? They got only 240 Members. They have bargained from Nitish Kumar Ji and Chandrababu Naidu Ji and they are trying to survive here.

Our Chief Minister has already given Rs. 31,000 crore to the farmers at the rate of Rs. 2,00,000 at one stretch. This has happened for the first time in India. Nobody is looking at that. We thought that the Government will help us and our Chief Minister will get empowered. Our Chief Minister and our leader Rahul Gandhi Ji gave the guarantees in Andhra Pradesh. We want to fulfil all the guarantees. It is because the BJP, which is in alliance with the BRS Party does not want Congress to perform. They want us to go down. That is why, they made this Budget and they did not allocate anything in this Budget. They did not even care about the promises made in the 2014 Act.

I want to conclude by requesting them to at least, now, look back at the 2014 Act. The 2014 Reorganisation Act is for both the States. It is not for Andhra Pradesh and it is not for any political survival. This Budget is for the people. From here, everybody has to hear. There are many people who are representing across the country. Everybody should get their stake.

Now, yesterday, Nirmala Sitharaman Ji was saying that there was no time to talk about other States. “We have a lot of Budget for other States. I have only time to talk about Bihar and Andhra Pradesh”. This is just because of political gain.

(ends)

1908 बजे

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर चर्चा के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार सांसद बनने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी, आगरा (उत्तर प्रदेश) की जनता को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर लोक सभा में दोबारा भेजने का काम किया और उससे मुझे आपके समक्ष जनता के विषयों को उठाने का अवसर मिलता रहेगा।

माननीय सभापति जी, मैं बजट पर सरकार के पक्ष में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह जो बजट देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने सांतवीं बार पेश किया है, उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति जी, मुझे एक बात पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके साथ आम आदमी पार्टी के जो साथी बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके शासन काल में, जब-जब आपने शासन किया तो आपने किसानों के लिए, खेत के लिए, गांव के लिए कौन से नियम, कौन सी योजनाएं, कौन से कानून बनाएं, जिससे किसानों की आय बढ़ी हो? इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। ये झूठ की बुनियाद, झूठ की दीवारें खड़ी करते हैं। ये अफवाहें फैलाते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करने का काम करते हैं... (व्यवधान)

(1910/RAJ/SM)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी किसानों से लगातार माफी भी मांगेगी, तो देश की जनता, देश के किसान कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे।...(व्यवधान) आपको कभी माफ नहीं करेंगे।...(व्यवधान) आपके नेता को यह नहीं पता होगा कि जौ की बाली कैसी होती है और गेहूं की बाली कैसी होती है? ...(व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान) आपके नेता को नहीं पता होगा कि हरी मिर्च कहां लगती है और लाल मिर्च कहां लगती है? ...(व्यवधान) आप किसानियत की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े और दलित, देश भर के जनमानस के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह बजट रोजगार भी देगा, यह स्वरोजगार भी देगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का माध्यम भी बनेगा।

माननीय सभापति जी, आज दुनिया में भारत की इकोनॉमी सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम ग्यारहवें नम्बर से पांचवें नम्बर पर आ गए हैं। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यह तीसरी अर्थव्यवस्था इसलिए भी बनेगा कि देश की जनता ने प्रधान मंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार अवसर दिया है।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब, शोषित और पीड़ित वर्ग हैं, उनको न्याय देने वाला यह बजट है। इसमें श्रमिकों से लेकर सभी वर्गों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दी गई हैं, उनकी उन्नति का रास्ता इस बजट से होकर निकलेगा। आदिवासी, दलित और पिछड़ों को सशक्त बनाने वाला यह बजट है।

अभी मैं कांग्रेस के साथियों को सुन रहा था। वर्ष 2013-14 से पहले कृषि का कुल 23 हजार करोड़ रुपए का बजट होता था, लेकिन आज 1.52 लाख करोड़ का बजट है। जब पिछला बजट आया था, तो उस बजट की तुलतना में इस बार लगभग 25 हजार करोड़ रुपए अधिक कृषि के लिए अधिक दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को खेती, किसानी और खेत से वास्ता नहीं है।

अभी आम आदमी अपना भाषण दे रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली में किसान को कृषि का दर्जा नहीं है। किसानों को कृषि की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। किसानों को दिल्ली में कोई भी सुविधा नहीं मिलती है।…(व्यवधान) लेकिन ये किसान और किसानियत की बात करते हैं।

कृषि बजट में किसानों की आय निरंतर बढ़े, इसकी लगातार चिंता करने का काम देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार योजनाएं दे रहे हैं। इसमें फसलों का विविधीकरण, खेती के तरीकों में बदलाव, फलों और सब्जियों की पैदावार में वृद्धि एवं उनके भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता है।…(व्यवधान) आपकी सरकार ने सैफई के अलावा कभी कुछ नहीं दिया।…(व्यवधान) आपको सैफई के अलावा कुछ नजर नहीं आता है।

माननीय सभापति जी, दाल, दलहन और तेलहन में आत्मनिर्भरता, उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन पर पूरा फोकस रखा गया है। खाद्य तेलों के लिए फसलों में सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए क्लस्टर बनाने व भंडारण और विपणन के ढांचे के विकास की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

(1915/KN/RP)

महोदय, कोरोना के काल में भी सारे सेक्टर्स बंद हो गए थे, लेकिन एग्रीकलचर का सेक्टर खुला रहा। मेरे देश के किसानों ने मेहनत की, श्रम किया, पसीना बहाया और देश के प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए किसान रेल चलाने का भी काम किया। आज मुझे प्रसन्नता के साथ यह कहना है कि किसान अपनी उपज को देश भर की मंडियों में भेज रहा है, जहां उसको ज्यादा दाम मिल रहे हैं। इसके लिए 167 मार्गों पर आज किसान रेल चलाई जा रही है। यह किसानों की आय को बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम है।

महोदय, ये बार-बार एमएसपी की बात करते हैं। इन्होंने 50 साल तक शासन किया। इनको कभी एमएसपी की याद नहीं आई। देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत से डेढ़ गुना देने का काम किया है। आज देश के किसान उन्नति के रास्ते की ओर आगे जा रहे हैं।

महोदय, चाहे रवि की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, हमारे देश के किसानों ने रिकार्ड उत्पादन करने का काम किया है।… (व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीच-बीच में कांग्रेस वाले किसानों के लिए अपनी कोई एक योजना जरूर बता दें, जो आपके शासन काल में कभी हुई हो। मैं आपको चुनौती देता हूं।… (व्यवधान) मैं अपने योग्य साथी सांसदों को विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को चुनौती देता हूं कि वे अपनी कोई दो योजनाएं गिनाएं, जिनमें ये कह सके कि हमने किसानों के लिए यह किया है। केवल बरगलाने से और भ्रम फैलाने से देश में राजनीति नहीं चल सकती है। आने वाले समय में अभी तो 100 से 99 पर आए हो, आप 39 पर रह जाओगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं।… (व्यवधान)

महोदय, पुराने समय में जब साहूकारों का समय हुआ करता था, ये लोग किसान को बोलने नहीं देते हैं।… (व्यवधान) भाइयों, तुम किसान को रोक भी नहीं पाओगे। मैं किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा करना चाहूंगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : धर्मेन्द्र जी, आप प्लीज बैठ जाइये।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : धर्मेन्द्र जी, आप टोकिये नहीं, वरना आप आगे बोल नहीं पाओगे। फिर मैं टोकूंगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : चाहर जी, आप इधर एड्रेस कीजिए। उधर ध्यान मत दीजिए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : महोदय, ये बीच-बीच में जो टोक रहे हैं, आप मेरा टाइम बढ़ाते जाइयेगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इनको कुछ भी बोलने दो। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान) … *(Not recorded)*

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : महोदय, साहूकारों के चंगुल में किसान हुआ करता था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो साहूकार के चंगुल में किसान होता था।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, आप बार-बार ऐसे मत कीजिए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : महोदय, उनको बड़े मोटे ब्याज पर साहूकारों से लोन लेना पड़ता था। वे खेत तक गिरवी रख जाते थे। किसान अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए कर्ज लेता था। मैं किसान के नाते देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने केसीसी कार्ड किसानों को दिया। आज देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन और मछलीपालन को जोड़ने का काम किया है। आज जिस प्रकार से पशुपालन और मछलीपालन को जोड़ा है, मेरा किसान आगे बढ़ता जा रहा है।

डीएपी और यूरिया – मुझे याद है, हम लोग भी साइकिल पर जाया करते थे कि जाकर बोरी लाद कर ले आए। कांग्रेस के समय पर किसानों पर लाठीचार्ज होता था। कांग्रेस की सरकार थी। मुझे याद है, मेरे मध्य प्रदेश के साथी यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया और कांग्रेस की सरकार ने मेरे निहत्थे किसानों के ऊपर गोली चलाई, 29 किसान मारे गए और उनको सांस तक नहीं आई। … (व्यवधान) आज समय बदल गया है। आज तो यूरिया नीम कोटेड

भी हो गया, आज तो यूरिया नेनो भी हो गया। आज तो हमें बोरी पीठ पर लादने की जरूरत नहीं है। आज तो हम नेनो यूरिया घर लेकर आते हैं। … (व्यवधान)

(1920/VB/NKL)

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि को-ऑपरेटिव मंत्रालय बनाया गया। देश के गृह मंत्री प्रथम सहकारिता मंत्री बने। मैं तो कहूंगा इस देश के लौह पुरुष जैसे श्री अमित शाह जी आज को-ऑपरेटिव को गांवों में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।

महोदय, सहकारी क्षेत्र में अभी भी दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ पर कोई सहकारी संस्था नहीं है। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने यह व्यवस्था की है कि आने वाले दो वर्षों में दो लाख ग्राम पंचायतों को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे किसानों की उन्नति का रास्ता बनेगा।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : प्लीज, अब समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : सर, मुझे 5 मिनट का समय और दे दीजिए।

माननीय सभापति : नहीं। कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : किसानों के लिए कौन-सी फसल उपयुक्त होगी, लाभकारी होगी, उसके लिए प्रचार और प्रोत्साहन पर काम होगा। 32 फसलों के लिए 109 नयी किस्में देने का काम भी इस बजट के अन्दर किया गया है।

पीएम फसल बीमा ने किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाये हैं। मेरे किसान भाई आज निडर होकर फसलें उगाते हैं। जरूरत पड़ने पर, जब अति वृष्टि, ओला वृष्टि, आँधी-तूफान और अग्नि में यदि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो फसल बीमा योजना से उसको मुआवज़ा मिलने का काम होता है, उसके घर-परिवार को बचाने का काम होता है।

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, जो काम पानी में भी होते हैं। उनमें यूरिया और डीएपी भी कम लगाना पड़ता है, वे हेल्दी भी हैं और आज दुनिया में इनको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। हमारे किसान आज सुपर फूड को उगाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें खाकर देश-दुनिया के लोग हेल्दी हो रहे हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है। महोदय, मैं अपने कांग्रेस के साथियों को फिर चुनौती देना चाहता हूँ। इस बीच में एक भी योजना… (व्यवधान) अरे एक भी योजना बता दो भाई, एक योजना का नाम बता दो, जिसे कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए लायी हो। आज तक कोई योजना नहीं आयी।… (व्यवधान) महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि खाद्यान्न के क्षेत्र में 246.42 मिलियन टन उत्पादन कांग्रेस के शासन काल में होता था। अभी खाद्यान्नों का उत्पादन 329.69 मिलियन टन हो रहा है। हम दलहन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम बागबानी में आगे बढ़ रहे हैं।

मैं ई-एनएएम मंडी की भी चर्चा करना चाहूँगा। कांग्रेस के समय में, इन्होंने कोई ई-एनएएम जैसी चीज नहीं लायी। लेकिन आज 1389 मंडियाँ ई-एनएएम मंडीज़ के रूप में काम कर रही हैं। वर्ष 2023 तक 1.76 करोड़ से अधिक किसान उसमें जुड़ चुके हैं और वे लाभ ले रहे हैं। उसमें व्यापारी भी जुड़े हैं, पंजीकृत हुए हैं।

माननीय सभापति : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : सर, किसान की बात सुन लीजिए। इनमें से किसी ने किसानों की बात नहीं रखी। केवल बरगलाना, लोगों में केवल भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।

माननीय सभापति जी, मैं एफपीओ के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। किसान उत्पादक संघ में आज सात हजार से अधिक एफपीओज रजिस्टर्ड हैं। 129.5 करोड़ इक्विटीज के अनुदान भी उनको जारी किये

गये हैं। 994 एफपीओज को 226.7 करोड़ रुपए की गारंटी कवर जारी की गई है। कांग्रेस ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। माननीय सभापति जी, जिस तरह से हम लोगों की हेल्थ होती है, उसी तरह से जमीन की भी हेल्थ होती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्वॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अभी 45,971 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं। चाहे मधुमक्खी पालन हो, कृषि सिंचाई हो, 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' हो, एग्री स्टार्ट अप्स हों, कृषि ऋण का प्रभार हो… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात आधे मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : माननीय सभापति जी, आज किसानों की आय बढ़े, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी लिया गया है। आने वाले समय में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे, प्राचीन खेती से जुड़ेंगे, ज़ीरो बजट खेती से जुड़ेंगे। उसमें किसानों की आय बढ़ेगी। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूँ- भाइयों, आज यूरिया, डीएपी, अन्य कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से कैंसर जैसी गंभीर बिमारियाँ हो रही हैं। आज आवश्यकता है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, देश के किसानों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। यूरिया, डीएपी को दूर रखें। उसके लिए सरकार इंसेंटिव देने का काम कर रही है। इस तरह से एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ने जा रहे हैं।

(1925/PC/VR)

माननीय सभापति जी, हमारे छ: करोड़ किसानों के जमीन के ब्योरे किसान की जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। … (व्यवधान) बजट के अंदर यह प्रावधान किया गया है। … (व्यवधान) पीएम आवास, शौचालय, उज्ज्वला, ये सारी योजनाएं चल रही हैं। … (व्यवधान) 25 करोड़ गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको गरीबी रेखा से ऊपर किया गया है। … (व्यवधान) कांग्रेस नारे लगाती रही, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला नहीं कर पाई। … (व्यवधान) माननीय सभापति जी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम हो रहा है। … (व्यवधान) पांच करोड़ जन-जातीय लोगों के लिए उन्नत ग्राम अभियान है, 63 हजार गांव इसमें शामिल किए गए हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : श्री आनंद भदौरिया जी।

… (व्यवधान)

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : माननीय सभापति जी, नौजवानों को कंपनियों में रोजगार दिए जा रहे हैं, ताकि गांव का नौजवान आगे बढ़े। … (व्यवधान) मैं बस एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आधे मिनट में कंप्लीट कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : गांव का नौजवान आगे बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, गांव-गरीब-किसान की उन्नति हो। … (व्यवधान) यह मेरे देश के प्रधान मंत्री जी की सबसे बड़ी वरीयता है। … (व्यवधान) ये ढोंग करते हैं, ये फर्जी बातें करते हैं और मेरे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : श्री आनंद भदौरिया जी – आप बोलना शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

1926 बजे

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : आदरणीय सभापति जी, आपका धन्यवाद। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पेश किए गए आम बजट पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मेरी पार्टी, मेरे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं।

महोदय, मुझसे पहले मेरी पार्टी के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा अपने संबोधन में बजट के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से मैं खुद को संबद्ध करता हूं। यह बजट वस्तुत: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है, क्योंकि इसमें संविधान सम्मत संघीय गणराज्य के ढांचे को पूरे तरीके से दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाए रखने का समर्थन मूल्य चुकाया गया है।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 'ए' से 'ज़ेड' तक अक्षर होते हैं। इसके एक-एक अक्षर मिलकर ही वर्णमाला पूरी करते हैं। इसमें प्रत्येक अक्षर का समान महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने सिर्फ 'ए' टू 'बी' का ध्यान रखा है। वे 'ए' टू 'बी' पर ही रुक गईं। यहां 'ए' यानी आंध्र प्रदेश और 'बी' यानी बिहार है। मैं जिस राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं, उसका 'यू' वर्णमाला में उसकी जगह की तरह ही उसको केंद्र सरकार और वित्त मंत्री जी ने प्राथमिकता ने कहीं पीछे छोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की बड़ी-बड़ी बातें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के लोग करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य को क्या विशेष वित्तीय पैकेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 'घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, मैं कैसे बोल दूं कि धूप फागुन की नशीली है?'

महोदय, जब बजट प्रस्तुत हो रहा था, तब मुल्क के गांव-गरीब-किसान बेकारी से जूझ रहे थे। मजदूर, महिलाएं और नौजवान, अगड़े-पिछड़े, दलित, मुसलमान, शोषित-पीड़ित-वंचित टकटकी लगाकर बड़ी उम्मीद के साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन उन्हें नाउम्मीदी और मायूसी मिली।

महोदय, आजादी के 77 सालों के बाद, इतने बजट लाने के बाद भी आखिर हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं, जहां आज भी आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है। जब उद्योगपतियों का आप लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो फिर देश के किसानों का और बेरोजगार नौजवानों का शिक्षा ऋण क्यों नहीं माफ होना चाहिए?

महोदय, मनरेगा का बजट न बढ़ाना, जहां निराश करता है, वहीं सरकार से अपेक्षा है कि मजदूरों के हित में मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाकर दो गुने करने का काम किया जाए। पीएम आवास योजना में लाल फीताशाही में उलझकर कहीं न कहीं सूची रह जाती है।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जरूरतमंदों को पीएम आवास के माध्यम से घर नहीं मिल पाते हैं। मेरी मांग है कि सांसदों की सिफारिशों पर पात्र व्यक्तियों को प्रधान मंत्री आवास के माध्यम से घर देने का काम किया जाए।

सरकार ने बजट में बताया कि उसका वित्तीय राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 4.9 फीसदी है, लेकिन यह नहीं बताया कि जो कर्ज हमारे देश के ऊपर वर्ष 2014 के समय 55 लाख करोड़ रुपए था, आज वह बढ़कर 210 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

(1930/CS/SAN)

नौनिहाल बच्चे इस बजट में आज भी समावेशी और विकसित होने की परिभाषा में सम्मिलित होने की प्रतीक्षा में हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों का भी बजट कम कर दिया गया है।

महोदय, अंत में मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा जानवरों ने तबाही मचा रखी है। किसान दिन-रात अपने खेत पर रहने को मजबूर हो रहा है। आवारा पशु लोगों की जान ले रहे हैं। मैं उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा देने की माँग करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके भी क्षेत्र में घोषणा करके आये थे कि आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का वह वायदा याद दिलाते हुए इस विकट समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए स्थायी योजना बनाने के लिए एक विशेष पैकेज की माँग करता हूँ।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहें। जय भीम। अखिलेश यादव जिन्दाबाद।

(इति)

1931 बजे

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : महोदय, मैं इस सरकार के बजट के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि यह किसान विरोधी, छात्र-युवा विरोधी, गरीब विरोधी बजट है। जो पिछला चुनाव हुआ, बजट ने उस चुनाव के जनादेश का उल्लंघन किया है। बजट बनाते समय उस जनादेश को पढ़ा नहीं गया है। बार-बार झटका लग रहा है, उपचुनाव में भी झटका लगा, फिर भी उसी तरह का बजट पेश किया गया है। हम थोड़ा सा एक आंकड़े की तरफ जाना चाहेंगे। लगातार कृषि बजट घटता चला गया है। यह किसानों के खिलाफ है। वर्ष 2019-20 में टोटल बजट का यह 5.44 प्रतिशत था, वर्ष 2020-21 में 5.08 प्रतिशत हुआ, वर्ष 2021-22 में 4.26 प्रतिशत हुआ, वर्ष 2022-23 में 3.84 प्रतिशत हुआ, वर्ष 2023-24 में 3.20 प्रतिशत हुआ और इस बार वर्ष 2024-25 में यह 3.15 प्रतिशत है, तो कृषि बजट में लगातार डिक्लाइन है। ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट घराने बैठकर इसको कैलकुलेट करते हैं कि कृषि को लगातार पीछे धकेलना है। ये आंकड़े कोई गलत नहीं हैं। देश में खेती घाटे में है और देश का किसान लगातार लाभकारी खेती के लिए लड़ रहा है। किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है। एमएसपी का जो सवाल है, एमएसपी एक पहेली बना हुआ है कि C2 प्लस 50 परसेंट या A2 प्लस 50 परसेंट। सरकार बराबर कहती है कि हम लाभकारी दाम दे रहे हैं, लेकिन C2 प्लस 50 परसेंट स्वामीनाथन कमीशन की रिकमंडेशन्स हैं। काम्प्रिहैंसिव कॉस्ट यानी उसमें परिवार का श्रम भी और जमीन का किराया भी है। इसलिए खेती को लाभकारी बनाइए, किसानों की जो लंबित माँग है, जिसके साथ आपने समझौता किया है, उसको आप लागू कीजिए। आपने ये तमाम चीजें और सिंघु बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने के बारे में लिखित में दिया है।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि नौजवानों के प्रति भी यह बजट बहुत ही बेरूखी का इजहार करता है। अव्वल तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें कहा गया कि आधे नौजवान, आधे बेरोजगार रोजगार के काबिल ही नहीं हैं। वे अनएम्प्लॉयबल हैं, तो स्किल इंडिया क्या कर रहा था। स्किल इंडिया था या किल इंडिया था। वह क्या था? क्यों स्कूल नहीं बनाए? अब फिर बात हो रही है कि हम एक करोड़ नौजवानों को इन्टर्नशिप कराएंगे। यह सरकार किसी भी मामले में कंपनियों को मदद करने, कॉरपोरेट्स को मदद करने का बहाना ढूँढ लेती है। फसल बीमा में तीन गुना ज्यादा कारपोरेट्स को दिया गया, एक तिहाई किसान को दिया गया है। इसमें भी 500 कंपनियों को आप जो इन्टर्नशिप के लिए पैसा देंगे तो बेरोजगारों को कम पैसा देंगे, कंपनियों को ज्यादा पैसा देंगे।

(1935/IND/SNT)

सभापति जी, इससे आप अग्निवीर की तरह कम्पनी वीर पैदा करेंगे और फिर जब ये एक करोड़ नौजवान इंटर्नशिप करके लौटेंगे, वे कैसे जिएंगे? आप कम वेतन पर इंटर्नशिप के जरिए कम्पनियों की सेवा उनसे कराना चाहते हैं। जो टैक्स आपने तय किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह कॉर्पोरेट की सरकार है और गरीबों के खिलाफ है। टैक्स में आप 60 परसेंट आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं और जो रिच आदमी हैं, सुपर रिच हैं, उनसे आप मुश्किल से दो परसेंट टैक्स लेते हैं। आप बताएं कि कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर पैसा खर्च होगा? कैसे ओपीएस लागू होगा? कैसे विकलांगों को, गरीबों को तीन हजार रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी? आप सुपर रिच को लगातार छूट दे रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र की मांग रखना चाहता हूं। बिहार के पैकेज पर लगातार चर्चा चल रही है। इस सरकार ने विशेष पैकेज नहीं दिया है। मैं उस समय बिहार विधान सभा में था जब झारखंड के साथ बंटवारा हुआ था। बिहार साढ़े चार सौ करोड़ रुपये के डेफिसिट में था और झारखंड 2700 करोड़ रुपये के बेनिफिट में था इसीलिए उस समय विशेष राज्य की मांग उठी थी। उस समय आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और बिहार से सर्वदलीय शिष्ट मंडल मिलने आया था। भाजपा ओपोजिशन में थी। आज इस सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। जो क्रूशियल सवाल थे जैसे इंटरनेशनल बार्डर से पानी आता है। बाढ़ में बिहार डूब जाता है। क्या उसका उपाय हुआ है? हम समझते हैं कि कोसी हाई डैम बनाने की बात थी। नेपाल में हाई डैम बनना है। सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। दक्षिणी बिहार में सोन कनाल सिस्टम जो अंग्रेजी राज वर्ष 1874 में बनी थी, उस पर इन्द्र पुरी जलाश्य बनाने की मांग है, उस पर आज तक सरकार ने कोई पहल नहीं की है। सिंचाई की व्यवस्था भी वहां खत्म है और बाढ़ नियंत्रण भी खत्म है। गरीबी मिटाने का सवाल भी खत्म। बिहार में जातीय जनगणना हुई और राष्ट्रीय स्तर पर हमने उसे कराने की मांग की है। उसमें सोशियो इकॉनोमी सर्वे में यह बात आई कि 34 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनकी आमदनी छह हजार रुपये प्रति माह से कम है। उनको सरकार दो लाख रुपया देगी। क्या इस पैकेज में वह शामिल है? गरीबी मिटाने का सवाल, बाढ़ नियंत्रण का सवाल, सिंचाई का सवाल तीनों इसी पैकेज में ही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए।

(इति)

1938 बजे

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट 2024-25 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम देश की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार सबसे बड़ा मतदान रूपी आशीर्वाद देकर एनडीए की कर्मयोगी सरकार को पुन: बनाने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे की झलक वर्ष 2024-25 के ऐतिहासिक बजट में देखने को मिल रही है। इन 70 पन्नों में प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने देश की प्रत्येक आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को मोती रूपी माला में पिरोकर हर संवेदनशील मुद्दे को लेकर गंभीरता से इस बजट को बनाने का काम किया है।

मान्यवर, वर्ष 2024-25 के बजट में साढ़े दस प्रतिशत की अनुमानित ग्रोथ रेट दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की प्रगति का संकेत है। इस बजट में चार समूहों का जिक्र किया गया है। इनमें युवा, महिलाएं, अन्नदाता और गरीब के लिए वित्त मंत्री जी ने दिल खोलकर बजट में प्रावधान किया है जो कि किसी भी प्रगतिशील देश के लिए अति-महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो रोजगार, कौशल, स्किलिंग, एमएसएमईज़ और भारत के निर्माता किसान और मध्यम वर्ग का उल्लेख किया गया है।

(1940/RV/AK)

महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बजट में जहां 'कौशल' शब्द का प्रयोग 24 बार हुआ है, वहीं 'ऑन्टरप्रेन्योरशिप', 'इम्प्लॉयमेंट', और 'जॉब्स' का 38 बार जिक्र हुआ है। इसमें 'युवा', 'शिक्षा', और 'युवाओं की जरूरतों' का 17 बार जिक्र है।

माननीय सभापति जी, यह एनडीए सरकार की मूल भावना है और यह युवाओं के प्रति उनकी और वित्त मंत्री जी की गम्भीरता को दिखाने का काम करती है। जहां किसानों को सशक्त करना, कृषि क्षेत्र को हर संभव बढ़ावा देने का काम करना, वहीं मध्यम वर्ग के लिए विशेष छूट उपलब्ध कराना, जिससे उनकी जीविका में बड़े बदलाव आ सकें, यह भविष्य की सोच है।

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रधान मंत्री जी का ड्रीम मंत्रालय - कौशल विकास मंत्रालय - स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मॉडल स्किल लोन योजना का शुभारम्भ हुआ है, जिसमें 7.5 लाख रुपये की ऋण सुविधा मिलेगी। इससे 25,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अगले पाँच वर्षों में एक

हजार से अधिक आई.टी.आईज़. का उन्नयन किया जाएगा और वहीं पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।

महोदय, मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी है कि देश की नींव, जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए के.वी.एस. और एन.वी.एस. में पिछले साल के मुकाबले 802 करोड़ रुपये और 330 करोड़ रुपये बढ़ाने का काम किया गया है। यह आने वाले समय में विकसित भारत के निर्माण में बड़ा योगदान देने का एक काम होगा।

मान्यवर, विश्व पटल पर भारत किस रूप में क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम बदलाव के कारण रोजगार और कृषि पर आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए देश को तैयार करने के लिए इस बजट में प्रधान मंत्री जी की, सरकार की और वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता देखने को मिलती है।

मान्यवर, मैं सामान्य कृषि-आधारित परिवार से आता हूं। मुझे कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों की जानकारी है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे समय में सरकार ने जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास के लिए निर्णय लिया है, जैसे कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलना, खेती-बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी के 109 उच्च कुल पैदावार करने वाली किस्मों को जारी करना, नैचुरल फार्मिंग में ग्राम पंचायत स्तर तक किसानों को प्रोत्साहित करना, इत्यादि।

अभी पहले भी यह विचार किया जा रहा था कि क्यों न दलहन और तिलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ऐसे में सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी फसलों के लिए जो कार्य नीति बनी है, निश्चित रूप से यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हमेशा भ्रष्टाचार और बेइमानी के खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा कहा कि भारत की आत्मा ग्रामीण अंचलों में बसती है। इस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आज कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए किया गया है, इसके लिए भी हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।

महोदय, इससे नए रोजगार पैदा करने का काम होगा। पी.एम.जी.एस.वाई. का चौथा फेज शुरू हुआ है। वह 25,000 से अधिक गांवों को जोड़ने का काम करेगा। वहीं पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी ग्रामीण अंचल और गरीबों के लिए है।

आज कैन्सर की दवाएं सस्ती हुई हैं। यह भी गरीब, खेती और किसानी से जुड़े लोगों के काम आने वाली हैं। चाहे पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना हो, यूरिया

सब्सिडी योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, पी.एम. आवास योजना हो, ये तमाम योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और किसानों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए है।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : चौहान जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(1945/GG/UB)

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : मान्यवर, बस एक मिनट में वाइंडअप कर रहा हूँ। … (व्यवधान) मान्यवर, आज जब देश भर में महिला उद्यमियों और वूमन एम्पावर्मेंट की बात हो रही है, ऐसे समय में 30 करोड़ से अधिक मुद्रा योजना लोन दिए जा रहे हैं। हम उद्योग के सहयोग में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल्स बनाना और शिशुगृहों की स्थापना कर के महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बना कर कामगार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : सर, मैं वाइंडअप कर रहा हूँ। 70% से अधिक पीएम आवास महिलाओं को दिए जा रहे हैं। STEM पाठ्यक्रम का 43% नामांकन बालिकाओं और महिलाओं के लिए है। मान्यवर, एक लाख विद्यार्थियों को ऋण राशि तीन प्रतिशत ब्याज की छूट पर ई-वाउचर से दिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जो यहां नहीं हुई है। … (व्यवधान) मान्यवर, बस मात्र तीस सैकेंड में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात आधे मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : मान्यवर, मैं इतना कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस पवित्र भवन में देश की जनता अपने आने वाले भविष्य से जोड़ कर विश्वास रखती है। आपकी चेयर के ऊपर आशोक चक्र लगा हुआ है, जिसमें 24 स्पोक्स हैं। जो हम सबको यह प्रेरणा देते हैं कि हम 24 घंटे अपने देश की सेवा करें और इन 24 संकल्पों को और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर देश के लोकतंत्र को मज़बूत करने का काम करें। हम माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसान की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। … (व्यवधान)

(इति)

1946 hours

*SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Vanakkam. I stand here to speak on the General Budget for the year 2024-25. I think that the Budget has been formulated on the basis of the Census taken in 2011. Therefore, the budgetary approach is imbalanced, non-progressive and non-inclusive. This Budget intends to save the Head and those in power. It does not spell even a single word about Tamils and Tamil Nadu. Therefore, this Budget is against the cooperative federalism and democracy.

This Budget does not seem to respect the principles of federalism in its true spirit. Tamil Nadu is totally ignored in this Budget. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru *Thalapathy* M.K. Stalin demanded Rs 37,000 crore for implementing several schemes in Tamil Nadu from the Union Government and only a meagre amount of Rs 276 crore was provided by the Union Government. When there were heavy rains and floods that affected Chennai, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu demanded flood relief assistance from the Union Government. The hon. Prime Minister and the hon. Ministers have not even visited the flood-affected areas. They have not even released any fund to Tamil Nadu in this regard to carry out flood relief work.

But the hon. Prime Minister visited Tamil Nadu seven times for campaigning during the General Elections. The people are taking note of how Tamil Nadu has been ignored in this Budget. When there was flood in Gujarat, before the flood water got receded, flood relief assistance was provided to the State of Gujarat. But for Tamil Nadu, not only flood relief assistance, but also the Union Government is showing biased attitude by not releasing funds for carrying out several projects in Tamil Nadu, including the metro rail projects. But Tamil Nadu occupies the second place in collection of tax revenue to the Union Government whether it is the GST or the income-tax collection.

Even though Tamil Nadu collects and provides so much of tax revenues to the Union Government, this Government has brought a Budget

* Original in Tamil

which is purely based on vote bank politics. This Budget claims to improve the global economic ranking of India from 5^{th} place to 3^{rd} place. Besides, they have stated that almost 80 crore people are getting foodgrains and other benefits under the public distribution system as these people are below the poverty line. What an irony? They earlier gave an assurance to double the income of farmers. But after lots of resistance faced by them from the farmers of our country for the proposed three farm legislations, this Government was forced to withdraw all the three farm legislations. You had given an assurance to streamline the conduct of NEET exam.

1949 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

But today we have witnessed so many irregularities in the conduct of NEET in our country and it has affected the future of our student community so much. Only three per cent of GST is levied for Platinum and Gold being used by rich and wealthy persons of our country whereas the GST is levied at 18 per cent for food products used by the common people. We see 77 per cent of wealth accumulated with 10 per cent of the higher strata of our population. You should have provided 20 crore jobs during the last 10 years if you have provided two crore jobs a year as per your assurance. Now in this Budget you have assured once again to provide five crore jobs in the country. I should say that the Union Government is showing partisan approach with favouritism among the different States of this country. I urge upon the Union Government to consider the demands put forth by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru *Thalapathy* M.K. Stalin. As regards release of funds to Tamil Nadu, since Tamil Nadu is the State, which provides more revenue to the Union Government by way of tax collection, I request that the Union Government should immediately release adequate funds that are due to Tamil Nadu and as demanded by our hon. Chief Minister. Thank you.

(ends)

1951 hours

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Honourable Speaker, Sir, I stand before you today to discuss a Budget that is less a financial document and more a desperate attempt by the BJP to hold on to power, a Budget that prioritises pandering over policy, coalition politics over the common good, and optics over outcomes, a Budget that reads like a gratitude letter, a love letter to only two States, while the rest of India is left feeling like a neglected stepchild. By the way I want to remind the States that it is not real love. The same promise was given to them in 2015 when there was special package announced to Bihar.

माननीय अध्यक्ष: क्या ये दोनों राज्य भारत में नहीं हैं?

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): I am just reminding them. It earlier announced a Rs. 1.25 lakh crore package in around 2015. मैं उनको रिमाइंड करा रहा हूं। यह पहले भी हो चुका है, मगर अभी उसकी कोई बात नहीं है। Nobody knows what happened to this Rs. 1.25 lakh crore package which was given in 2015.

This is a Budget that seems more like a Bollywood blockbuster trailer big on hype, but when you look closer, it is all special effects with no real story.

Sir, what is required in this Budget? A large portion of the Indian economy is about consumption; 57.2 per cent is consumption. How are we going to increase the demand? That is the primary question.

In 2014, in UPA Government, 66.6 per cent of direct taxes came from corporates. Today it is 47 per cent; and 53 per cent of the tax is now paid by individuals. If we do not put money into people's hands, how is the demand going to rise? How is it going to improve the economy? That is the primary moot question that has to be discussed.

It is a classic case of "Kahani main ab twist hai". I was reading the Budget document to know what is there. Without any substance, filled with buzzwords and sound like they were picked straight from a corporate jargon dictionary. In fact, this time, I should be thankful that

they have not gone in for 'Stand up India', `Sit up India', `Sleep India', `Walk India', thanks to the Finance Minister for sparing us from that.

The BJP as usual is more focused on staging a show than addressing the pressing needs of our nation. I am going to outline only a few *jumlas* for the sake of time.

Let us talk about agriculture, where the Budget promises new "high-yielding and climate-resilient crop varieties." It is almost as if the Government thinks farmers need a new superhero crop to save the day! The push for 'natural farming' sounds like an attempt to make organic farming the new masala mix that will fix everything. But in reality, farmers are dealing with high input costs, low MSPs which are not legally guaranteed and poor procurement systems.

(1955/RCP/CP)

In fact, in the current Budget, the fertilizer subsidy has been reduced by 13 per cent as compared to RE 2023-24. There are issues that no amount of 'organic mix' can fix.

With great sadness, I would say that as per the NCRB data, one farmer and one agricultural labour are committing suicide every hour in this country. Then, there is an announcement of Digital Public Infrastructure for Agriculture. It sounds as if the Government believes that all farmers are in need of a strong internet connection.

Coming to employment, the Employment Linked Incentive scheme is offering Rs.15,000 for new employees, which is touted as a game-changer. But it is like giving a single samosa at a wedding feast. It is woefully inadequate. The Budget's focus on the formal sector, while ignoring the vast informal sector, is like showing off a picture of a five-star hotel room in an ad for budget accommodation. The Mudra loans are not the miracle cure as they are made out to be. It is all as if the Government believes that throwing in a few freebies will solve all the problems.

From 2014 to 2022, 22.05 crore people have applied for jobs and only 0.33 per cent, that is 7.22 lakh, people got the jobs. What are you going to do about this? You have destroyed the bright MSME sector that we had which provided 12 crore jobs. There are no jobs now.

Infrastructure is another comedy where around Rs.11.11 lakh crore for capital expenditure has been declared in the Budget. It has been presented with much fanfare. As per the data of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, out of 1,843 infrastructure projects, 779 projects are having cost overruns and 449 projects are experiencing delays. When infrastructure projects are declared for Bihar and Andhra Pradesh, they should be very clear that this is what is going to happen with them.

Coming to welfare, the Government talks about targeted and efficient spending which in plain English means cutting budget for MGNREGA, NSAP and things like that. Even in this Budget, amount for MGNREGA has been cut down, amount for Samagra Shiksha has been cut down, amount for PM-POSHAN has been cut down, and amount for old age pension has been cut down.

Finally, I would like to say that Tamil Nadu has been completely ignored by this Government. They have not given us anything. They have stopped our relief fund; they have stopped amount for our GST and they have even stopped amount for our school education.

We have been fighting this ideological battle for a long time. Tamil Nadu will fight fascism. We will fight with our language; we will fight with our wisdom; we will fight with our unity; we will fight with our poetry; we will fight with our music. We will fight and challenge you with joy and celebrations.

Finally, I would say that this is a childish Budget. It is the real *balak buddhi* Budget. Thank you.

(ends)

1958 hours

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Hon. Speaker Sir, I want to thank my Janta Dal Secular great leader, the former Prime Minister of India and Rajya Sabha MP Shri H.D. Deve Gowda ji and my another leader and Union Minister Shri H.D. Kumaraswamy ji. I also extend my gratitude to the people of my constituency Kolar and people of Karnataka for entrusting me with this responsibility. I want to extend my heartful thanks to the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji who has presented a good Union Budget 2024-25.

In the history of Indian democracy, our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has been elected for a third consecutive term, and NDA Government is presenting the budget for a record 11 years continuously, promising a true and wide vision on key fields that emphasise the development of the nation and ample opportunities for all.

The Budget has focussed on skill development to reap benefits out of demographic dividends where the youth, both men and women, will improve their skills and take advantage of abundant opportunities in the field of employment and entrepreneurship.

The Government has taken steps to skill 20 lakh youths over five years including women. Importance is given to women which is almost 50 per cent of our population by reserving Rs. 3 lakh crore for women led development schemes for their economic development. Importance is also given for working women hostels. The Government has also opened new opportunities in higher studies by giving financial support of up to Rs.10 lakh in domestic institutions.

Projecting the MSMEs to compete globally would make the nation’s footprint in manufacturing and services industries another important priority.

(2000/PS/NK)

Providing MSMEs with credit guarantee and enhancing Mudra loan limit to Rs. 20 lakh from Rs. 10 lakh will make the young entrepreneurs to

establish on their own. A scheme to provide internship in top 500 companies to one crore youths in five years by giving Rs. 5,000 internship per month will create employment to youth. The Government has taken responsibility by sanctioning three crore houses in rural areas, which will bring down the economic burden on the people who come under the Below Poverty Line category. The Government has planned for constructing one crore houses under the PMAY-U 2.0 Scheme by allocating Rs. 10 lakh crore.

माननीय अध्यक्ष: मैं सदन से आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य के बोलने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो बोलने वाले वक्ता हैं, उनसे आप कहें कि वह सदन में बैठें, जिनको आगे बोलना है। सदन में बोलने वाले वक्ता बैठे नहीं हैं। उनको आप बोलें कि आगे से सदन में बैठें। जो कल बोलने वाले हैं, वे भी सदन में बैठें, जिनका नाम लिस्ट में है। सदन में बैठेंगे तो सुनेंगे तो बोलेंगे। कोई भी माननीय सदस्य बोल कर सीधा चला जाएगा तो उसको आगे से बोलने का नम्बर नहीं दिया जाएगा। सदन में मैं आपकी सलाह मानता हूं लेकिन यह आसन का अधिकार है, ऐसे सदस्य जो बोलकर सदन से चले जाते हैं।

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): The Government has given importance to research in the agriculture sector to provide climate-resilient varieties, which is utmost required due to climate change. It is also giving thrust to natural farming and digital public infrastructure for coverage of farmers and their land. The Government has adopted PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, where solar units are installed on rooftops to obtain free electricity to one crore households. This will reduce the burden on the power sector, and economically, the householder will benefit. The schemes and allocation that the Government of India has announced under innovation, research and development and next generation reforms, would rather attract and support new way of thinking and exploitation of themselves in a good manner for the establishment of Viksit Bharat, which is the utmost aim of this Budget 2024-25. The Government is giving priorities to youth, women, agriculture, housing, tourism and

entrepreneurship development. So, India is surely going to become the third biggest economy in the near future.

Hon. Speaker, Sir, I also wish to emphasize the importance of key issues relevant to my Parliamentary Constituency, Kolar. They are; water for drinking and irrigation purposes to Kolar and Chikkballapur districts from Krishna River; food processing units for tomato and mango at Kolar, Srinivaspur and Mulbagal; a Government Medical College and a Multi-Speciality Hospital; Railway Coach Factory, which was proposed in 2016; and retirement benefits for the employees of Bharat Gold Mines Limited, which has been pending since 2001. Regularization of BEML Contract Employees at KGF Unit; and upgradation of State Highways to National Highway from Hoskote to Madanapalli, from B.Kothakota to Hosur, and from Kuppam to Bagepalli are other issues.

Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me an opportunity in this august House. Jai Hind.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2003 बजे

<u>तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 26 जुलाई 2024/ 4 श्रावण 1946 (शक)</u>
<u>के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>